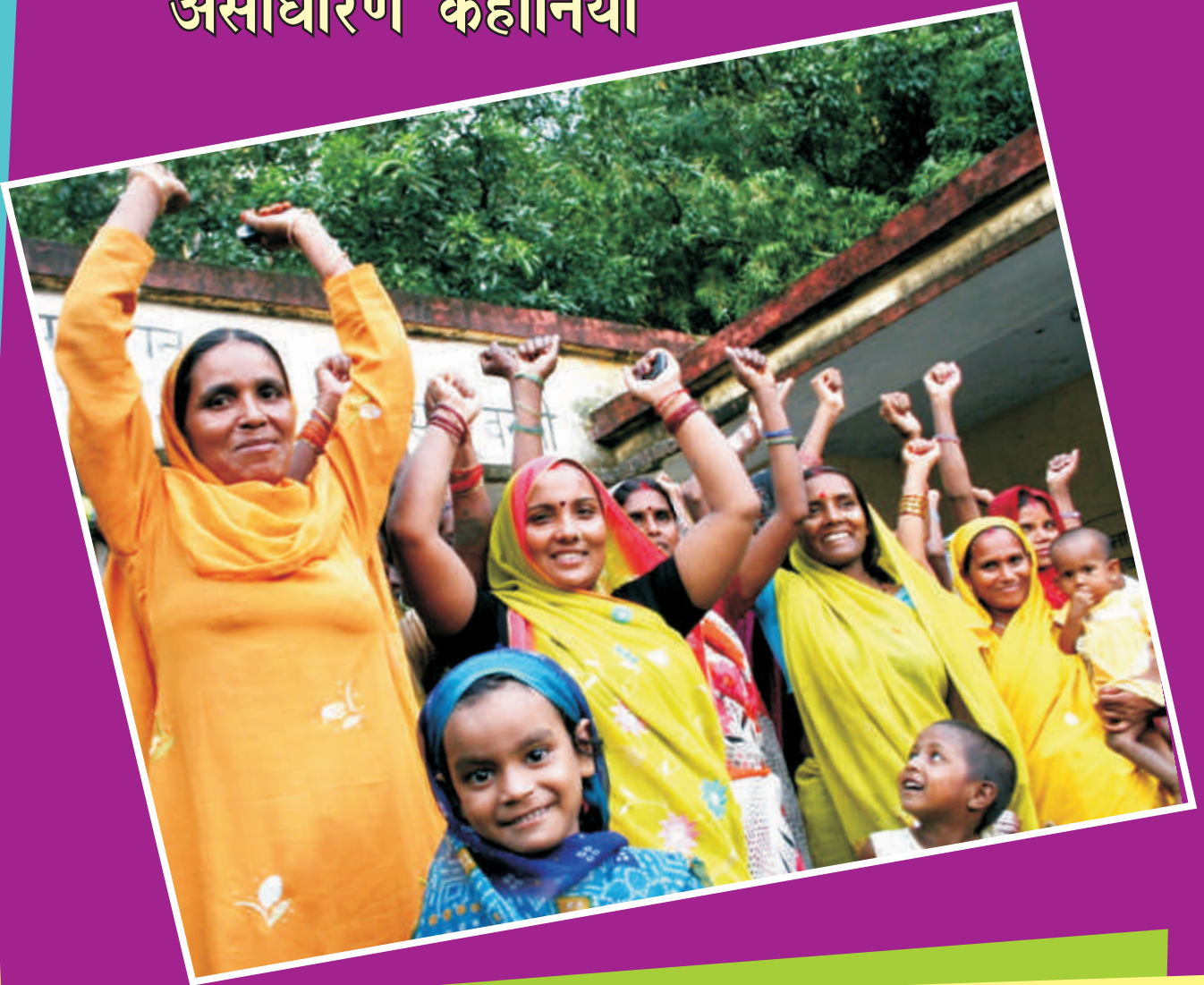


साधारण महिलाओं की असाधारण कहानियाँ



जो जागत है, वो पावत है

(जागरूकता से हकदारी की अनुभूति एवं प्राप्ति होती है।)

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत
नारीसंघ की कहानियों का संग्रह

प्राक्कथन

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपने आप में एक अद्वितीय एवं पहला कार्यक्रम है जो पूरी तरह से अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ एक बड़े स्तर पर दलित एवं वंचित समुदाय की महिलाओं के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूर्वांचल की छोटी-छोटी जमीनी स्तर की संस्थाओं को पहली बार अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ काम करने का अवसर प्रदान किया गया तथा साथ ही साथ इन नागर समाज संगठनों की क्षमतावर्द्धन का भी काम कर रहा है। इस कार्यक्रम का फोकस मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर है। पहला—वंचित समुदाय की महिलाओं को भारी संख्या में संगठित करके उनके अन्दर इस तरह का नेतृत्व विकास करना ताकि वे खुद अपने हक एवं अधिकार की लड़ाई निरन्तर रूप से लड़ सकें। दूसरा—पूर्वांचल में अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ महिला सशक्तिकरण, स्थानीय स्वशासन एवं मानवाधिकार के मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाओं का एक ऐसा बड़ा समूह तैयार करना ताकि वो इस क्षेत्र में वंचित समुदाय के हक एवं अधिकार से जुड़े मुद्दों पर सतत काम कर सकें।

यह दस्तावेज पूर्वी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के बीच परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। जागरूकता के द्वारा प्रेरित और जानकारी से सुसज्जित ये महिलाएं व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं और साथ ही हक और अधिकारों को जानने के बाद उसको प्राप्त करने का दावा भी कर रही हैं। ये महिलाएं नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रही हैं और साथ ही समाज में अपनी एक अलग पहचान भी बना रही हैं। वास्तव में ये महिलाएं ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के प्रभाव से ही प्रभावी रूप में अपना प्रतिनिधित्व कर पा रही हैं।

पानी संस्थान—पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इन्टीग्रेशन उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है जो कि अधिकार आधारित सोच, मुख्यतः महिलाओं के साथ कार्य करती है। पानी के द्वारा अनेक विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्वयं किया जाता है और कुछ विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश की अनेक नागर समाज संगठनों के साथ मिल करके किया जा रहा है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 2007 में 6 संस्थाओं के साथ शुरू हुआ था जो वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश की 9 जिलों के 37 जमीनी स्तर के नागर समाज संगठनों के द्वारा 36 ब्लॉक की 666 ग्रामपंचायतों में क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जैसा की नाम से ही इंगित होता है कि यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने एवं सामुदायिक संगठन अर्थात् नारीसंघ के गठन के माध्यम से उनको हक एवं अधिकार के प्रति जागरूक करके उसकी प्राप्ति सुनिश्चित कराना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तर पर संगठित होने की प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है, इन्हीं अनेक ग्रामपंचायत स्तरीय नारीसंघ जब आपस में मिल करके ब्लॉक स्तर पर संगठित होते हैं तो यही संगठन नारी महासंघ के नाम से जाना जाता है। गठन की प्रक्रिया के अगले चरण में एक जिले के सभी ब्लॉक के ब्लॉक स्तरीय नारी महासंघों के जुड़ जाने से ही जिलास्तरीय नारी महासंघ के गठन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पंचायत से भी ऊपर जाने का उद्देश्य है कि जिससे महिलाओं में संख्या के आधार पर भी ताकत की भावना विकसित हो सके एवं साझा मंच प्राप्त हो सके, जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं एवं उस पर पहल करने की रणनीति की चर्चा कर सकें। इसके अलावा, ब्लॉक एवं जिले स्तर पर संगठित होना इसलिए भी आवश्यक है कि जिससे महिलाएं अपने हक एवं अधिकारों के लिए पैरवी कर सकें, मुख्यतः सम्मान के साथ हक एवं अधिकारों को प्राप्त कर सकें।

महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में उनका सशक्तिकरण हो सके, जिससे कि वे हक एवं अधिकारों को प्राप्त कर सकें। इस संदर्भ में वर्तमान में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मुख्यतः तीन अधिकारों पर केन्द्रित है—भोजन का अधिकार, काम का अधिकार एवं स्थानीय स्वशासन में भागीदारी करने का अधिकार। कार्यक्रम स्तर पर इन अधिकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उचित वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में, मनरेगा के उचित क्रियान्वयन एवं ग्रामसभा का आयोजन करने की मांग एवं उसको एक मंच के रूप में कार्य करते हुए सहभागी रूप से निर्णय लेने के लिए सुदृढ़ करना।

प्रत्येक पार्टनर संस्थाओं को पूर्व निर्धारित ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर ही ग्रामपंचायतों की संख्या में विस्तार करना है किन्तु यह प्रक्रिया सभी ग्राम पंचायतों में एक साथ नहीं प्रारम्भ की जा सकती है। जैसे कि किसी सहयोगी संस्था का लक्ष्य 40 ग्रामपंचायतों में कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने का है किन्तु चरणबद्ध रूप में प्रथम वर्ष में यदि 20 ग्रामपंचायतों में कार्यक्रम का प्रारम्भ करते हैं और जब इस समय सीमा में कार्यक्रम का विकास उचित पैमाने पर हो जाता है तो उस स्थिति में अन्य ग्रामपंचायतों को भी कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित किया जाता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत पार्टनर संस्थाओं के द्वारा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का उचित ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इन कार्यकर्ताओं के लिए पानी संस्थान और उस संस्था द्वारा क्षमतावर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है और इसको विस्तृत रूप में नियोजित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुद्दे मानवाधिकार, जेण्डर एवं सामाजिक न्याय विषयक प्रशिक्षण, नागरिकता एवं स्थानीय स्वशासन, महिला स्वास्थ्य, मनरेगा पर्सपेक्टिव प्लान, अधिकार आधारित पद्धति एवं सामुदायिक गतिशीलता एवं सहजीकरण की रणनीति एवं पद्धति विषय आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं।

इस कार्यक्रम को वित्तीय सहायता **सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, मुंबई** से प्रदान की जा रही है एवं पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन-पानी, कार्यक्रम को तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है, एवं समन्वयन का काम कर रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में पानी सहयोगी संस्था होने के कारण संस्था स्तर पर विभिन्न मुद्दा आधारित आवश्यकताओं के लिए प्रोग्राम सपोर्ट टीम भी स्थापित की गयी है। यह टीम ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की सभी पार्टनर संस्थाओं के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के क्रियान्वयन, क्षमतावर्धन एवं मानिट्रिंग के लिए भी कार्य करती है, जिससे कि कार्यक्रम के वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

किसी भी अन्य कार्यक्रम की भांति ही, इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी अलग-अलग संस्थाओं द्वारा विभिन्न तरीकों से सहजीकरण किया जा रहा है, जिसका कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। इसी आधार पर क्रियान्वयन करते हुए कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एकरूपता भी दिखायी पड़ती है। संक्षेप में, सहजीकरण एवं संस्थागत विशेषज्ञता में विविधता ही इस कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 1 लाख ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना। वर्तमान में, यानि मार्च, 2011 तक 80,436 ग्रामीण महिलाएँ इस कार्यक्रम के माध्यम से संगठित हो चुकी हैं। इस पुस्तिका के माध्यम से इस सफर के दौरान प्राप्त हुए अनेक सकारात्मक अनुभव, उपलब्धियाँ एवं साथ ही साथ अनेक प्रकार की चुनौतियों को भी आपके साथ बांटना चाहते हैं। किसी भी सामाजिक हस्तक्षेप की सफलता लोगों की मानसिकता, विचारों में सकारात्मक परिवर्तन एवं संसाधनों तक पहुंच एवं प्राप्ति में ही निहित है। यहां हम केस स्टडी के माध्यम से इस कार्यक्रम के प्रभाव के परिणामस्वरूप विभिन्न स्तर पर हुए परिवर्तनों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

ई.आर.डब्लू. कार्यक्रम के सभी पार्टनर्स

विषय सूची

- प्राक्कथन
- ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र 04
- ग्रामपंचायत स्तरीय नारीसंघ एवं ब्लाक स्तरीय महासंघ की कहानियाँ 05
- नारीसंघ नेतृत्वकर्ता की कहानियाँ 37
- नागर समाज संगठनों की भूमिका और आगे की दिशा 65
- पार्टनर संस्थाओं का विवरण 67
- दस्तावेज में सामान्य रूप से उपयोग किये गये संक्षिप्त एवं स्थानीय शब्द 70

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र



ग्रामपंचायत स्तरीय नारीसंघ एवं ब्लाक स्तरीय महासंघ की कहानियाँ

1. सामूहिक पहचान का गर्व

“लालसा नारीसंघ ने ग्रामपंचायत, ब्लाक एवं जिले स्तर अपनी अलग पहचान बनायी है। अब लोगो मे हमारी पहचान व्यक्तिगत स्तर से ऊपर होकर हम सभी को नारीसंघ के नाम से जानते हैं।” ये कहना है नारीसंघ की अध्यक्ष सोनिया जी का। आज इनको संगठन से जुड़ करके प्राप्त हुयी नयी पहचान पर बहुत ही गर्व है।

मऊ जिले के घोसी ब्लाक में कार्यरत संस्था भगवान मानव कल्याण समिति के माध्यम से बरौली ग्राम पंचायत में भी ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर लालसा नारी संघ के नाम से पहचान बनी। इस नारी संघ की कुल 178 सदस्य है। नारी संघ के गठन की प्रक्रिया जून 2010 में प्रारम्भ हुआ और गठन के साथ ही महिलाओं की व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में अद्वितीय परिवर्तन की छाप देखी जा सकती है। संगठन की सदस्य मंजू देवी, गीता देवी एवं सोनिया देवी का विकास नेतृत्वकर्ता के रूप में हुआ है। साथ ही ये महिलायें सचिव, अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के उत्तरदायित्व का निर्वहन भी प्रभावी ढंग से कर रही हैं।

नारीसंघ के गठन के पूर्व की स्थिति में महिलाएं अपने ही मुद्दों पर संगठित हो करके प्रयास नहीं कर पा रही थी। संस्था के कार्यकर्ताओ ने दलित एवं अतिवंचित समुदाय की महिलाओं को एकत्रित कर संगठित करने का प्रयास किया। संस्था के द्वारा सर्वप्रथम प्रत्येक पुरवे स्तर पर महिलाओं को महिला मण्डल के अन्तर्गत संगठित करने की पहल की गयी और सभी पुरवे में महिला मण्डल का गठन किया गया। इसके अगले चरण में एक ग्राम पंचायत के सभी महिला मण्डल को एकत्रित कर पंचायत स्तर पर नारी संघ का गठन किया गया।



भगवान मानव कल्याण समिति के द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 30 ग्रामपंचायत मे हस्तक्षेप किया जा रहा है। संस्था के द्वारा नारीसंघ के क्षमतावर्धन के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण मे पहल करने के लिए समय समय पर आवश्यकता आधारित अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन किया जाता है। सीख भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन भी अन्य संस्थाओ के कार्यक्षेत्र मे किया जाता रहा है जिससे कि महिलाओ मे मुद्दों पर पहल करने की समझ विकसित होती है एवं पहल करने के लिए प्रेरित भी करती है।

अन्य नारीसंघ की तरह ही लालसा नारीसंघ अच्छी तरह से काम कर रहा है। सदस्यो न सर्वसम्मति से तीन महिलाओ को अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के रूप मे काम करने के लिए क्रमशः चयनित किया है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी संगठन की बैठको की

लालसा नारीसंघ का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि महिलाएं सशक्त संगठन के माध्यम से वे अधिकारो को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें एवं चुनौती की स्थिति में ग्रामपंचायत से ले करके जिले तक पैरवी एवं दबाव बना करके हक एवं अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करा सकें।

अध्यक्षता करना, मुद्दो पर संगठन की सहमति से निर्णय लेना एवं निर्णय लेने मे मदद करना, स्थानीय नेताओ और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकों और चर्चाओं मे नारीसंघ का प्रतिनिधित्व करते है। सचिव की जिम्मेदारी बैठक का एजेण्डा तैयार करना एवं बैठक की चर्चा एवं निर्णयो का दस्तावेजीकरण करना है। कोषाध्यक्ष सदस्यता शुल्क और खर्च का विवरण रखती है।

लालसा नारीसंघ का एक स्पष्ट नजरिया है। वे महिलाओ के अधिकारो के लिए एक मजबूत संगठन बनाने का कार्य की, जिससे कि महिलाओ का

समूह समस्याओं के समाधान के लिए दबाव समूह के रूप में कार्य कर सकें। नारीसंघ के द्वारा किसी मुद्दे/ समस्या जिसका प्रभाव बहुतायत में होता है उस पर आम सहमति के साथ समस्या ली जाती है। सामान्यतः महिलाएं समाधान की पहल ग्रामपंचायत में ही करती हैं। यदि प्रधान कोई प्रतिक्रिया नहीं करते तब समस्या पर पहल करने के लिए नारीसंघ द्वारा ब्लाक एवं जिले स्तर पर पहल की जाती है।

संस्था के अनुसार "महिलाओं की एकता एवं सामूहिक भावना ही नारीसंघ के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसके परिणामस्वरूप ही किसी समस्या पर आपस में चर्चा करने के बाद ही उस पर संगठित हो कर पहल भी करती हैं।" यह वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो महिलाएं पहले एक दूसरे को जानती तक नहीं थी आज वे संगठित हो दृढ़प्रतिज्ञा हो करके अपने हक एवं अधिकारों को प्राप्त करने की पहल कर रही हैं।

लालसा नारीसंघ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अनेक चुनौतियों का नारीसंघ ने दृढ़कौशल एवं संगठन की भावना से सामना भी किया है। सोनिया देवी मनरेगा के अंतर्गत नारीसंघ के द्वारा किए गए काम का आवेदन देने की घटना का बयान कर रही हैं। जब नारीसंघ की सदस्य संबंधित अधिकारियों को काम का आवेदन देने के लिए गयी तब उनको बहुत ही बुरा लगा और डांटने लगे। सुनीतादेवी बताती हैं कि "जब 14 दिन बाद भी काम प्राप्त नहीं हुआ, तब बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया गया और यह सब देख करके रोजगार सेवक गुस्से में मेरे घर आया और कहा कि "तुम नेता बन गयी हो, बताओ कि क्या करोगी, जब गांव में काम ही नहीं है" यह सब सुन कर परिवार के लोग क्रोधित हुए और मुझे डांट भी पडी।" दोनो से डांट पड़ने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि वह नरेगा एक्ट के काम न उपलब्ध होने पर बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानती थी। अतः अधिकार को प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन का प्रयोग करके सारी समस्याओं को बताया एवं दबाव के परिणामस्वरूप काम प्राप्त हुआ।

उसी समय दूसरी घटना घटी, जब काम का आवेदन देने के लिए नारीसंघ की महिलाएं गयीं, तब रोजगार सेवक क्रोधित हो करके महिलाओं को भगाने का प्रयास करने लगा। "जब पुरुष काम की मांग नहीं करते, तब आप लोग कैसे कर सकती हैं?" इस बार सब तरह की प्रतिक्रियाओं के लिए महिलाएं तैयार थी परिणामस्वरूप उत्तर में महिलाओं ने कहा कि "यदि आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो हम लोग ब्लाक पर बी डी ओ से रीसिव कराएंगे।" इतना सुन करके आवेदन स्वीकार करके काम उपलब्ध कराया गया। निराश रोजगार सेवक महिलाओं को ठीक से काम करने नहीं देता और शक्ति का प्रयोग करके परेशान करने की कोशिश करता। वह उन लोगों के काम में कमियों निकाल करके लगातार कहता रहता कि "अगर काम सही से नहीं किया तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी"। एक बार पुनः संगठन के लोगों ने हेल्पलाइन का प्रयोग ब्लाक से किसी अधिकार को नरेगा के काम को स्वीकृति देने के लिए आने का अनुरोध किया। अन्ततः जो लोग (रोजगारसेवक तथा प्रभावी एवं दबंग) परेशान कर रहे थे उनको एक सबक सीखने को मिला। अब महिलाओं को चुप कराना आसान नहीं था क्योंकि महिलाएं संगठित व जानकारियों से सुसज्जित हैं।

मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के अलावा, ग्रामसभा के क्रियान्वयन के लिए भी नारीसंघ के द्वारा प्रभावी पहल की गयी। महिलाओं द्वारा ग्रामसभा की मांग प्रधान से की गयी और तब से ग्रामपंचायत का आयोजन पूरे कोरम के साथ आयोजित होने लगा और नारीसंघ के सदस्य लिखित एजेण्डे के साथ प्रतिभाग करके विकास से संबंधित मुद्दों पर किए जा रहे निर्णय करने में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि निर्वाचित एवं सरकारी तंत्र से जुड़े लोग भी आम लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं करते। एक ऐसी ही घटना आंगनवाड़ी केन्द्र पर घटित हुई जिसके अंतर्गत नारीसंघ के द्वारा अनियमितता देखी गयी और उसको सही करने के लिए पहल भी गयी। आंगनवाड़ी केन्द्र पर गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को पोषाहार वितरित किया जाता है इसके बाद भी बहुत सी महिलाओं को न तो कभी बताया गया अथवा वितरित किया गया परिणामस्वरूप आत भी बहुत सी महिलाएं जानती भी नहीं हैं। अतः नारीसंघ ने सूचना के अधिकार का प्रयोग करके सूचना प्राप्त की और कमियों का भी चिन्हित करके आंगनवाड़ी को सुधारने के लिए कहा और परिणामस्वरूप उसके कार्य में सुधार भी हुआ, आज वह सभी को आवश्यक सेवा एवं सुविधाएं प्रदान कर रही है।

लालसा नारीसंघ के संगठित हो करके प्रयास करने के परिणामस्वरूप सेवादाताओं एवं निर्वाचित व्यक्तियों की जबाबदेही भी होने लगी है।

2. सूचना की शक्ति

सूचना वास्तव में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हालांकि, इस सूचना के युग की विडम्बना है कि यह समानरूप से सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। कुछ के लिए तो यह आसानी से उपलब्ध है जबकि अन्य के लिए बहुत ही दुर्लभ है।

ज्योति नारीसंघ की अध्यक्ष नन्हकी देवी मानती हैं "हम गरीब लोगों के पास इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए न तो संसाधन हैं और आवश्यक जानकारी भी नहीं है। यहां तक की ये भी नहीं जानते की किस काम के लिए कौन जबाबदेह एवं जिम्मेदारी है।" वे और उनके गाव चौकिया की अन्य महिलाएं सूचना के अभाव में ग्रामपंचायत से लेकर ब्लॉक तक की सूचना को प्राप्त करने में इसी तरह की लाचारी का एहसास करती हैं। इसलिए जब ग्रामीण विकास संस्थान के द्वारा इन मुद्दों पर प्रारम्भिक बैठकों का आयोजन किया गया, इससे महिलाओं का ध्यान आकर्षित हुआ और वे प्रभावित हो करके बैठकों में प्रतिभाग करने लगीं। नन्हकी देवी कहती हैं कि "जब हम लोग एक साथ आने लगे और बैठक में सूचनाएं मिलने लगीं, तब हम लोगों को महसूस हुआ कि संगठित हो करके हम अनेक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।"



वर्ष 2009 में गाजीपुर के सदर ब्लॉक की चौकिया ग्रामपंचायत में ज्योति नारीसंघ का गठन हुआ। महिलाओं ने नन्हकी देवी को अध्यक्ष, रुकमिणी देवी को सचिव एवं मीना देवी को सूचनामंत्री चुना गया। अगुआ महिलाओं के

अनुसार "अगुआ के रूप में हमारी भूमिका, महिलाओं में एकता की भावना का विकास एवं समूह को मजबूत बनाने का कार्य करना एवं हम सामूहिक लाभ के मुद्दों का चुनाव करके सामूहिक लाभ के लिए पहल करते हैं।"

अन्य बातों के अलावा, नारीसंघ प्रमुख एवं प्रासंगिक जानकारियों को सदस्यों को सुलभ करते हैं। सूचना जागरूकता को एवं जागरूकता, जानकारी ही कार्यवाही के लिए प्रेरित करते हैं।

ज्योति नारीसंघ ने मौजूदा कमियों को पता करके सरकार के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया है। ऐसा करने में उन लोगों ने भी चुनौती दी है जिन लोगों के हक एवं अधिकार अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं।

नन्हकी देवी ने नारीसंघ के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नियमित एवं सुलभ बनाने के लिए की गयी पहल को बताते हुए

अन्य बातों के अलावा, नारीसंघ प्रमुख एवं प्रासंगिक जानकारियों को सदस्यों को सुलभ कराते हैं। सूचना जागरूकता को एवं जागरूकता तथा जानकारी ही कार्यवाही के लिए प्रेरित करते हैं।

कहती हैं कि, "पहले स्थिति बहुत ही दयनीय थी, कोटेदार गुणवत्तापूर्ण राशन को बाहर बाजार में बेच देते थे और हम लोगों को निम्नकोटि के राशन देते थे। जब भी कोई विरोध करता, तब वह उससे गाली गलौज करता व तिरस्कृत करके थैले और डिब्बे को फेंक देता और कहता कि जाओ जो करना है कर लो। हम उसके व्यवहार से परेशान थे, किन्तु उसको एवं उसके व्यवहार को सुधारने का कोई रास्ता पता नहीं था। नन्हकी देवी बताती हैं कि "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कानून एवं नियमों को जानने के पश्चात, महिलाओं ने व्यक्तिगत लाभ को प्राप्त करने के लिए पहल की। किन्तु अब भी

कोटेदार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और अंततः नारीसंघ के सदस्य सामूहिक रूप से बात करने के लिए उसके पास गयीं। "हमने गुणवत्तापूर्ण राशन के वितरण की मांग की, और चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोग अनाज का नमूना ले करके जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ आप के खिलाफ शिकायत करेगे।" यह प्रभावी रहा और परिणाम स्वरूप राशन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। हालांकि कोटेदार गाव में दूर के पुरवे की महिलाएं, जो कि संगठित नहीं थीं, को अभी पहले की ही तरह राशन दे रहा था। उन

महिलाओं ने भी कोटेदार की अनियमितता के खिलाफ नारीसंघ की सदस्यों से बात की और नारीसंघ की सदस्य के रूप में संगठन से जुड़ गयी। इस पहल के परिणामस्वरूप राशन वितरण में सुधार हुआ और साथ ही संगठन की शक्ति का भी विस्तार हुआ।

नारीसंघ के सदस्यों का यह अनुभव किया है कि एक बार के प्रयास से स्थायी सफलता व परिवर्तन सम्भव नहीं है। इसलिए उन्हें निरंतर पर अपने कामकाज की नवाचार करना चाहिए। “नारीसंघ की अगुआ को जब से सूचना के अधिकार के अर्न्तगत राशन के मूल्यों, दर की सूची व गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त हुई तबसे कोटेदार नारीसंघ की उपस्थिति में ही मानक के अनुसार सही दर व गुणवत्तापूर्ण राशन का वितरण करते हैं और जिससे सभी बहने बहुत खुश हैं।” नन्हकीदेवी ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन करके अपने ग्रामपंचायत की सूचना प्राप्त किया। इसी क्रम में नारीसंघ की अगुआ ननकी देवी ने सूचना के अधिकार का उपयोग एवं सफलता की चर्चा महासंघ की बैठक में चर्चा की, जिससे की अन्य नारीसंघों को भी उत्साह मिला।

अनेक अवसरों पर गांव के लोग संगठन की शक्ति एवं नेतृत्वकर्ताओं को चुनौती देते थे। इसी तरह की एक घटना को नन्हकी देवी ने बताया, “5 लड़कियों को सावित्री बाई फुले योजना के अंतर्गत लाभाधी के रूप में आवेदन किया किन्तु पात्रता को पूरा करने के बावजूद भी उन लोगों को लाभ नहीं मिला रहा था।” यह जानने के बाद मैंने उनको लाभ दिलाने और अपात्र बताने वालों को गलत साबित करने की चुनौती देने का निर्णय लिया। इस मुद्दे को साबित करके लाभाधियों को लाभ दिलाने के लिए ब्लाक स्तरीय अधिकारियों से बात करके इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई से उनको अवगत कराया। यह मामला एक वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के कारण लम्बित था अतः इस पर भी तुरंत कार्यवाही करके पूर्ण किया गया। लड़कियों को योजना के अंतर्गत साइकिल का वितरण किया गया और वितरण के समय ही अधिकारी ने नन्हकी देवी से कोई भी पैसे की साइकिल का चुनाव करके देने का भी अधिकार दिया। नारीसंघ की अध्यक्ष कहती हैं कि “इस घटना के बाद में लोगों ने नारीसंघ की एकता एवं व्यक्ति को स्वीकार करके मान्यता भी दी।”

हांलाकि महिलाएं संगठन की शक्ति के प्रति जागरूक हैं और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ आगे प्रगति की दिशा में अग्रसर हैं। नन्हकी देवी के शब्दों में “प्रारम्भ में हम लोग अपनी ही शेष मजदूरी के लिए भी विन्न भाषा में अपनी बात कहते थे यदि तभी भी सुनवाई नहीं होती थी तो हम सामूहिक रूप से जाते थे”। नारी संघ की उपस्थिति सरकारी अधिकारियों के समक्ष भी जो कि अपने कार्य एवं जिम्मेदारियों का सही तरह से निर्वहन नहीं करते, उनके लिए नारी संघ दबाव समूह के रूप में कार्य करता है। इससे भी आगे महिलाएं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। “हम आपके जेब से नहीं मांग रहे, जो सरकार ने हमारे लिए प्रावधान किया है, वही हमें चाहिए” इस तरह से ये महिलायें सहयोग न करने वाले सरकारी अधिकारियों के सामने अपनी बातें रखती हैं।

ब्लाक स्तरीय अग्नि नारी महा संघ में 5143 महिलायें सदस्य हैं, ज्योति नारी संघ भी इसका एक भाग है जिसमें 152 सदस्य हैं। नारी महा संघ के माध्यम से कार्यक्षेत्र की अगुआ महिलाएँ एक दूसरे का सहयोग करती हैं, साथ ही संगठित होकर समस्याओं पर पहल भी करती हैं। इसीक्रम में रूहीपुर नारीसंघ की अध्यक्ष संगीता देवी द्वारा पंचायत सचिव के निरंतर अनुपस्थिति के मुद्दे को बैठक में उठाया गया। महासंघ के द्वारा इस मुद्दे पर पहल करते हुए पंचायतसचिव के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी। इसीक्रम में औरंगाबाद नारीसंघ की अध्यक्ष अनरसी देवी के साथ भी महासंघ ने इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की, परिणामस्वरूप उनको न्याय भी मिला। गांव के कुछ दबंग लोगों ने अनरसी देवी को बुरी तरह से पिटाई की और जब पीड़ित रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। किन्तु जब महासंघ की पहल के परिणामस्वरूप पुलिस को दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी। अब नारीसंघ को लगता है कि उनकी ताकत में महत्वपूर्ण कई गुना वृद्धि हुई है।

ज्योति नारीसंघ की कहानी की सफलता का श्रेय महिलाएं को मार्गदर्शन, आवश्यक सूचनाओं एवं जानकारियों की निरन्तर उपलब्धता एवं उनके द्वारा गतिविधियों एवं कार्यवाहियों का निर्धारण ही है। “गांव के शक्तिशाली लोग, प्रधान एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो काम अभी तक पुरुष नहीं कर पा रहे थे, उसको करने का हम महिलाएं भी सोच भी सकते हैं।” अपनी क्षमता को साबित करके आज ज्योति नारीसंघ को यह बताने में गर्व का अहसास होता है।

3. सरकारी कार्यालयों तक पहुंच

“पहले हम लोग सोचते थे कि हम लोग सिर्फ घर का ही काम कर सकते हैं, नारीसंघ से जुड़ने के बाद हमको यह अहसास हुआ कि हम घर से बाहर भी काम करने के लिए सक्षम हैं”, यह कहना है, गाजीपुर जिले के जखनिया ब्लाक के मोलनपुर गाँव की उजाला नारी संघ की अध्यक्ष सुधेश्वरी देवी का।

उनके अनुसार, सबसे बड़ी उपलब्धि है, महिलाओं का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और उनके विवेक के आधार पर सार्वजनिक मुद्दों को संभालने की क्षमता में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

उजाला नारीसंघ का गठन मार्च 2010 में हुआ और 152 महिलाएं सदस्य भी हैं। जबकि सुधेश्वरी देवी नारीसंघ की अध्यक्ष, रजनी देवी सचिव के रूप में एवं संतरादेवी मंत्री के रूप में नारीसंघ का कार्यभार संभालती हैं।

इस गांव में महिलाओं की साक्षरता दर अभी भी बहुत कम है, जिसके कारण महिलाओं में कुछ उलझन रहती है कि वे अपनी बातें सरकारी अधिकारियों के सामने कह भी पाएंगी या नहीं। नारीसंघ की अध्यक्ष के शब्दों में नारीसंघ गठन से पूर्व की स्थिति “पहले हम लोगों को काम के अधिकार, भोजन, पेंशन एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इसके साथ ही हम लोग अपने कामों में इतना व्यस्त रहते थे कि आपस में भी बात करने का समय भी नहीं मिल पाता था।”

हम ऐसा नहीं कह सकते कि नारीसंघ के गठन के पश्चात स्थितियों में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है, किन्तु यह अवश्य है कि इसी के साथ ही परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ है। महिलाएं अब अपने हक के प्रति जागरूक हो गयी हैं और वे महसूस करती हैं कि हक एवं अधिकारों पर दावा करने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ेगा।

उजाला नारीसंघ ने मनरेगा में काम सुनिश्चित करने के लिए एक लम्बी लड़ाई का प्रारम्भ कर दिया है। जिसका प्रारम्भ 35 महिलाओं के द्वारा जॉबकार्ड के आवेदन से प्रारम्भ हुआ। नारी संघ की नेतृत्वकर्ता को याद है कि किस तरह से प्रधान ने उन्हें धमकी दी थी जब वे पहली बार प्रधान को आवेदन देने के लिए गयी थी, तब उन्होंने आवेदन लेने से इन्कार कर दिया था। नाराज प्रधान ने चिल्लाते हुए कहा कि “तुम लोग पुलिस की मार खाने के बाद ही समझोगे।” उसको यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि महिलाएं

उसके सामने अपनी बकाया धनराशि की मांग कर रही हैं। अतः नारीसंघ की सदस्य ब्लाक स्तरीय अधिकारियों से जॉबकार्ड प्राप्त करने के लिए मिली एवं लिखित आवेदन दिया, प्रधान ब्लाक स्तरीय कार्यालय से प्राप्त आदेश के पश्चात प्रधान ने 3 माह के संघर्ष के बाद जॉबकार्ड प्राप्त हुआ।

महिलाओं को जॉबकार्ड तो मिल गया, किन्तु प्रधान के नाराज होने के कारण महिलाओं को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। इसी कड़ी में जब महिलाएं काम का लिखित आवेदन करने ले करके प्रधान के यहाँ गयीं तब प्रधान ने कहा कि वे ब्लाक स्तरीय अधिकारियों से चर्चा के उपरांत ही आवेदन स्वीकृत करेंगे।

सुधेश्वरी देवी के अनुसार, महिलाओं की मुख्य उपलब्धि रही है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, जिसके कारण ही वे सामाजिक मुद्दों पर पहल कर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो गयी हैं।



जब प्रधान को कई बार आवेदन देने का प्रयास असफल होने के कारण महिलाओं ने ब्लाकस्तरीय अधिकारियों से मिल करके आवेदन देने का निश्चय किया। अभी तक महिलाओं को सहयोग न करने के लिए सभी एक दूसरे के साथ थे। इसलिए जब नारीसंघ की महिलाएं ब्लाक पर बी डी ओ को आवेदन देने के लिए गयीं तब उन्होंने आवेदन को ग्राम सचिव से रीसिव कराने के लिए कहा। इसी क्रम में जब महिलाएं ग्राम सचिव के पास आवेदन रीसिव कराने के लिए पहुंचीं तब उसने भी रीसिव करने में असमर्थता व्यक्त की। अब महिलाएं हत्तोत्साहित होने लगी थीं। तब जन ग्रामीण विकास संस्थान (कार्यक्रम का संचालन करने वाली संस्था) के मार्गदर्शन में महिलाएं कार्यक्रम अधिकारी से मिलीं किन्तु यहाँ भी असफलता ही मिली, क्योंकि उन्होंने भी बी डी ओ से ही मिलने को कहा। जैसे ही बी डी ओ को पता चला कि नारीसंघ की महिलाएं उनके कार्यालय आ रही हैं, तो वे आफिस से चले गए। यह स्थिति देखने के बाद महिलाओं को गुस्सा भी आने लगा।

बार बार एक समस्या के बाद दूसरी समस्या देखने के बावजूद भी महिलाओं के द्वारा हक को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का ही अनुसरण किया गया। नारीसंघ के प्रयास से जब सफलता नहीं मिली तब उन्होंने मनरेगा हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करायी। इसका परिणाम आश्चर्यजनक रहा। ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को महिलाओं के कार्य के संदर्भ में आदेश हुआ और अधिकारियों ने प्रधान को भेज दिया। महिलाओं को आज भी याद है कि किस तरह से प्रधान दौड़ते हुए उनके पास आए थे। काम के आवेदन की स्वीकृति न होना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है। प्रधान ने महिलाओं से लिखित में देने का आग्रह किया कि उन्हें अब काम प्राप्त हो चुका है। प्रधान ने महिलाओं से काम देने का वादा किया, किन्तु महिलाओं ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। महिलाओं ने प्रधान से पहले काम के आवेदन को रीसिव करके पावती देने को कहा और तब ही महिलाएं लिखित में पत्र देगीं। अब प्रधान के पास औरकाई रास्ता न होने के कारण उसको आवेदन रीसिव करके पावती देनी पड़ी।

अब तो यह स्पष्ट ही था कि प्रधान के वादे एवं बातों का कोई भरोसा नहीं है। कुछ दिनों के बाद प्रधान ने कुछ मजदूरों को खड़ण्जा लगाने का काम दिया। जब इस बात का पता नारीसंघ को चला तब महिलाएं कार्यस्थल पर पहुंचीं। जैसे तैसे प्रधान ने महिलाओं को वहाँ से वापस करने का प्रयास किया किन्तु महिलाओं ने उनका विरोध किया। प्रधान के ही एक सहायक ने वही से पुलिस को फोन करके बुला लिया और पुलिस ने संबंधित अधिकारी से बात करके इस मामले की सुलह करने का आदेश दिया। अतः नारीसंघ ने पुनः कार्यक्रम अधिकारी से बात करके पूरी समस्या से अवगत कराया। परिणामस्वरूप उन्होंने महिलाओं को नरेगा में काम देने के लिए महिलाओं के उपर दबाव डाला। अन्ततः लम्बे संघर्ष के बाद महिलाओं को मनरेगा में 5 दिन का काम प्राप्त हुआ और यह क्षण महिलाओं के लिए गर्व का था।

अगले ही दिन प्रधान ने नारीसंघ की महिलाओं के साथ एक नया खेल खेला। उसने नारीसंघ की बहनो से कहा कि उनके खेतों से होते हुए एक चकरोड पास हुई, अतः वे जल्दी से जल्दी अपने खेतों में खड़ी धान की फसल काट ले अथवा वो भी नष्ट हो जाएगी। जब संस्था को इस बात मुद्दे की जानकारी हुई तो उन्होंने महिलाओं से ग्राम सभा की एक कॉपी, जिसमें की यह चकरोड पास हुई थी। और यदि निर्णय पहले ही ले लिया गया है तो महिलाओं को मुआवजा मिलना चाहिए। प्रधान को जब महिलाओं ने कॉपी से अवगत कराया तब उसने कहा कि पहले तुम लोग फसल काट लो। तब महिलाओं ने दृढ़तापूर्वक कहा कि सड़क बनाने की अनुमति तब तक नहीं है, जब तक कि उनको मुआवजा नहीं मिलता।

उजाला नारीसंघ ने अभी तक एक लम्बा रास्ता तय किया है, महिलाएं जो अभी तक घरों की चहरदिवारी के अंदर उनमें आत्मविश्वास नहीं था आज वे ही अपने अधिकारों की वकालत करने लगी हैं। नारीसंघ की अध्यक्ष बताती है कि "हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग ब्लाकस्तरीय कार्यालयों में अधिकारियों से मिल करके अपनी बात कह सकेंगे, किन्तु यह हम सब लोगों ने कर दिखाया है।"

उनकी क्षमता को देखने के बाद भी वे महसूस करती हैं कि उन्हें अब भी बहुत कुछ सीखना है। "हम लोगों का पूरी तरह से अभी विकास नहीं हो पाया है, और अच्छे नेतृत्वकर्ता बनने के लिए और जानकारी एवं सीखने की आवश्यकता है।" महिलाओं को अभास है कि वे सही रास्ते पर चल रही हैं किन्तु अभी भी संतुष्ट नहीं हैं।

4. महिला नेतृत्व को मिली सामाजिक पहचान

“का हो नेता जी” सुनीता देवी बताती है कि इस तरह से गांव के लोग उनसे बात करते हैं। सुनीता देवी चिंगारी नारीसंघ की अध्यक्ष हैं। नारीसंघ की अध्यक्ष कहती हैं कि “लोग हमें नेता के रूप में देखते हैं, जब से मैं लोगों की समस्याओं पर पहल करके समाधान करने के लिए ब्लाक से ले करके जिलास्तरीय अधिकारियों से संपर्क करने लगी हूँ।”

समाज में नेतृत्वकर्ता की भावना एवं अपेक्षा सदा पुरुषों से ही रही है महिलाओं से नहीं। हालांकि, नारीसंघ इस प्रचलित अवधारणा के परिवर्तन में महत्वपूर्ण रही है। नारीसंघ के संबोधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आसानी से दिखायी पड़ता है।

चिंगारी नारीसंघ का गठन वर्ष 2010 में मऊ जिले के मोहम्दाबाद ब्लाक के चकजाफरी गांव में प्रारम्भ हुआ। महिला ग्रामोद्योग सेवा समिति के द्वारा नारीसंघ के गठन किया गया जिसमें की सुनीता देवी अध्यक्ष, विमला देवी सचिव एवं गीता देवी कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं।

अब तक नारीसंघ की कुल 99 सदस्य हैं। इनमें से अधिकतर महिलाएं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं उनका लाभ तथा इन्हीं सब कारणों से सामूहिक रूप से नारीसंघ के गठन का निर्णय लिया।

हालांकि महिलाओं ने एक साथ रहने का निर्णय कर लिया था किन्तु पुरुष इस विचार से सहमत नहीं थे। सुनीता देवी को याद आता है “मेरे पति एवं

ससुर भी मेरे नारीसंघ का सदस्य बनने से प्रसन्न नहीं थे। वो कहते कि ‘प्रधान के खिलाफ मत जाओ।’ अन्य महिलाओं को भी उनके परिवार के पुरुषों द्वारा कुछ इसी तरह की बातें सुनी पड़ी। उनके विरोध के बावजूद नारीसंघ भी नारीसंघ ने अपना कार्य जारी रखा। विशेष रूप में, उन लोगों ने मनरेगा के अंतर्गत जॉबकार्ड प्राप्त करने एवं काम पाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया।

ग्रामप्रधान को सबसे अप्रिय घटना महिलाओं द्वारा काम की मांग करना लगा। पहले मनरेगा एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि में हेर-फेर करना आसान था। किसी को भी योजना के बारे में जानकारी न होने के कारण मुश्किल से ही कुछ लोग काम की मांग करने आते थे। अतः सब पर प्रधान का ही नियंत्रण रहता था। वह चुनिंदा मजदूरों को ही काम देता था एवं उनको भी उनकी पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं करता था। इसलिए वह नारीसंघ सदस्यों को काम देने का इच्छुक नहीं रहता था, किन्तु सार्वजनिक रूप में उनको काम के लिए मना भी नहीं करता था, परिणामस्वरूप 50 महिलाओं को चकरोड का काम भी मिला।

महिलाओं के सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। महत्वपूर्ण बात है कि उनके प्रति हो रही हिंसा में भी कमी हो रही है।

नारीसंघ की महिलाएं अपनी सामूहिक सफलता से बहुत खुश थीं और अगले दिन भी काम करने के लिए समय से कार्यस्थल पर पहुँचीं। इसी बीच कार्यस्थल पर प्रधान एवं रोजगार सेवक दोनों ने ही महिलाओं को परेशान करने का दृढ़श्चय करके गए थे, जिससे कि महिलाएं स्वयं ही कार्यस्थल को छोड़ करके चली जाएं। रोजगार सेवक बराबर से उनके द्वारा किए जा रहे काम में कुछ न कुछ गलती निकालने में लगा था और उनकी मजदूरी काट लेने की धमकी दे रहा था। अगले दिन तो वह और ही आक्रामक हो गया। वह महिलाओं के पास पहुँचा, उन्होंने अभी काम प्रारम्भ ही किया था और वह उनके उपर अनावश्यक ही चिल्लाने लगा। तब महिलाओं को अहसास हुआ कि वे दोनों क्या करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा था कि इस तरह से प्रताड़ित करने पर वे स्वयं ही काम छोड़ देंगे, किन्तु महिलाओं ने उनकी मंशा को गलत सिद्ध कर दिया।



इसके विपरीत महिलाओं ने प्रताड़ना के लिए स्वयं ही उसको मौका देने लगी क्योंकि अब उन्होंने इस मुद्दे को बाहर (ब्लाक स्तरीय अधिकारियों) ले जाने का निर्णय कर लिया था।

नारीसंघ ने ब्लाकस्तरीय कार्यालय पर जा करके इस अन्याय के विरुद्ध रिपोर्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने रोजगार सेवक के द्वारा उपयोग किए गए अभद्र भाषा एवं उसके व्यवहार को बताया। एम जी एस एस संस्था के कार्यकर्ता भी वहां उपस्थित हो कर महिलाओं का सहयोग कर रहे थे। कुछ पत्रकार भी आ गए। इस प्रकार छोटी सी अवधि में महिलाओं की वास्तविक मांग की दिशा में बड़ा समर्थन मिला। अधिकारियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रधान, सचिव एवं रोजगार सेवक को बुला करके कानून एवं नियम को पालन करने का कड़े शब्दों में आदेश दिया। रोजगार सेवक के विरुद्ध जांच का आदेश दिया। इस सफलता से सामूहिकता की भावना मजबूत हुई।

महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखती हैं, और यह महिलाओं के विरुद्ध हो रही घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं को समाप्त करने का नेतृत्व भी कर रही हैं। उन्हीं में से एक अगुआ महिला भी घरेलू हिंसा का शिकार थी, उनके पति शराब पी करके मार-पीट करता था। नारीसंघ ने कई बार उससे इस तरह के व्यवहार को बंद करने के लिए बात भी की थी। “अब वह कभी मारता नहीं अपितु उसके काम में सहयोग करता है, बच्चों की जिम्मेदारी में भी हाथ बंटा करके साथ देने लगा है।”

चिंगारी नारीसंघ ने संस्था द्वारा चलाए गए ग्रामस्वराज्य अभियान में भी सक्रिय भागीदारी की थी। इसी अभियान के अंतर्गत महिलाओं ने गाँव स्तर पर विकास समूह के रूप में “विकास दल” का गठन किया। समूह के सदस्य प्रत्येक मतदाता तक पहुंच करके उनके विकास के मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के मुद्दों की प्राथमिकता का संकलन करना था। इस तरह से यह संकलन ही मतदाताओं के समक्ष एक उदघोषणापत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। मतदाताओं को निर्वाचित करने के क्रम में मतदाताओं के साथ खुली चर्चा का आयोजन भी किया गया। सभी प्रतिभागियों ने इन मुद्दों पर कार्य करने का वादा भी किया। नारीसंघ की इस पहल के परिणामस्वरूप चयनित प्रधान महिलाओं को प्रत्येक कार्य के लिए सूचित करते हैं और जवाबदेही भी सुनिश्चित करते हैं। सामूहिक मांग करने पर ग्रामसभा का आयोजन तो करते ही हैं साथ ही विकास दल द्वारा चिन्हित एवं चयनित व्यक्तियों की पात्रता सुनिश्चित करके उस पर पहल भी करते हैं।

चिंगारी नारीसंघ की अगुआ महिलाओं ने स्थानीय स्वशासन में उनकी भागीदारी एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। “पहले महिलाएं ग्रामसभा की खुली बैठक जैसी बातों से अनभिज्ञ थी, उनको लगता था कि ये सब तो सिर्फ पुरुषों के लिए ही हैं। किन्तु अब वे प्रतिभाग करके अपने विचारों को भी बैठक में रखने लगी हैं।” महिलाओं की गतिशीलता एवं उनके आत्मविश्वास में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। “जब आवश्यकता पड़ती है तब महिलाएं ब्लाक कार्यालयों में आसानी से जाने लगी हैं, अब उनको किसी भी तरह का डर या संकोच नहीं लगता है।” महिलाएं यह भी बताती हैं कि अब इतनी सक्षम हो गयी हैं कि अपने सरकारी कार्यालयों में अपने काम बिना रिश्तों दिए काम करा लेती हैं।

नारीसंघ जहाँ अपनी सफलता एवं उपलब्धियों को प्रसन्नता के साथ बताती हैं तो साथ ही कुछ ऐसे मुद्दों को भी रखना नहीं भूलती जिन क्षेत्रों में अभी पहल करने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में वे बताती हैं कि जैसे महिलाएं निर्वाचित पदों पर अभी भी सक्षम और मुखर नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कोटा के प्रावधान के अनुसार महिलाओं को आरक्षण तो मिलता है किन्तु उनके कार्यों को घर के पुरुष एवं बेटों के द्वारा ही निर्णय ले करके किया जाता है। महिलाएं वास्तविक रूप में प्रतिभाग न करके सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए ही कार्य करती हैं। चिंगारी नारीसंघ के अभी तक के प्रयास को देख करके यह अपेक्षा की जा सकती है कि भविष्य में उनके द्वारा हस्तक्षेप करके इस पर पहल की जा सकती है।

5. पुरुषों को साबित किया गलत

यह सच है कि नारीसंघ के कारण महिलाओं को अपनी शक्ति का आभास हुआ है। किन्तु गठन की प्रक्रिया के दौरान महिलाओं ने दृढ़ उत्साह से विभिन्न स्तरों पर समस्याओं का समाना भी किया। परिवार एवं समाज के सामान्य मुद्दों से हट कर नारीसंघ में रुचि लेने के कारण ही महिलाओं को अनेक समस्याओं का समाना करना पड़ा।

शक्ति नारीसंघ के गठन की प्रक्रिया कोई अपवाद नहीं अपितु इसका भी गठन अन्य संगठनों की तरह ही हुआ है। वाराणसी जिले में अराजीलाईन ब्लॉक के बहोरनपुर ग्राम पंचायत में मार्च 2009 में महिलाओं द्वारा नारीसंघ का गठन किया गया और अब तक 262 महिलाओं को नारी संघ में जोड़ा गया। नारी संघ के गठन की प्रक्रिया में महिला स्वरोजगार समिति ने सहयोग किया।

नारीसंघ की अध्यक्ष गीता देवी, उपाध्यक्ष निर्मला देवी और कोषाध्यक्ष बदामा देवी, संगठन के गठन के दौरान आये कठिनाईयों को बताते हुए कहती हैं कि “समाज में हम औरतों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हमारे परिवार के पुरुषों का सोचना था कि महिलाओं के लिए कोई भी बुद्धिमानी का कार्य करना मुश्किल है, उनका कहना था कि हम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम महिलाओं को घर से बाहर निकलकर बैठक में जाने से रोकने वालों में सबसे पहला व्यक्ति घर के पुरुष ही थे। जब भी महिलाएँ घर से बाहर कदम निकलने लगती हैं तो उसे परिवार का अपमान माना जाता है, लेकिन हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। यदि हमारे परिवार के पुरुष ही हमारा सम्मान नहीं करते हैं तो, बाहर के पुरुष कैसे करेंगे? उनके मुताबिक नारीसंघ किसी काम का नहीं था और न ही इस संगठन के माध्यम से कोई परिवर्तन होने वाला था। इस ग्राम पंचायत के अन्य पुरुषों की सोच परिवार के पुरुषों से अलग नहीं थी उनका भी कहना था कि घर में कोई पुरुष नहीं है, जो अब औरतें घर से बाहर निकल कर चारों ओर घूमती हैं। बैठक में जाने पर गाँव के पुरुष कहते कि महिलाएँ वहाँ केवल चाय समोसा, मिठाई खाने व गप मारने जाती हैं। वे मनरेगा के अर्न्तगत हमारे काम के अनुरोध को खारिज करते हुए कहते कि महिलाएँ निर्माण कार्यस्थल पर काम करने के योग्य नहीं हैं। वे नारीसंघ की बहनो को उनके कामों में, चाहे वे गलत ही कर रहे हों तो भी दखलंदाजी न करने का निरंतर सुझाव दिया करते थे।

प्रारम्भ में नारीसंघ की बहनें जब बैठकों अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके घर वापस आतीं, तो कुछ को तो पति का गुस्सा एवं मार भी झेलनी पड़ता था।



इस दौर से गुजरते हुए, महिलाओं ने प्रतिकूल वातावरण में भी आपस में मिलना जारी रखा। लेकिन बिना किसी भी प्रकार के भुगतान के ज्यादातर महिलाओं को बैठक में आने या कार्यक्रम में भाग लेने पर घर लौटने पर परिवारिक संघर्षों जैसे परिणाम का सामना भी करना पड़ता। यहां तक कि कुछ तो अपने पतियों के द्वारा इसी बात के लिए मारी पीटी भी जाती थी। लेकिन अब तक हम महिलाओं ने यह निर्धारित कर लिया था कि हम नारीसंघ का एक हिस्सा हैं और हमेशा इससे जुड़ी रहेगी। “क्योंकि हम महिलाओं को एहसास हो गया था कि हम सब पर होने वाली हिंसा के बढ़ते

प्रभाव को हम सभी एक दूसरे के समर्थन के बिना नहीं समाप्त कर सकते हैं। नारीसंघ से जुड़ने के बाद हम महिलाओं को यह एहसास हो गया कि हम औरतो का जीवन बेकार नहीं है, और हम हमारे आदमियों को विश्वास कराना चाहते हैं कि हम भी एक सक्षम मनुष्य हैं।

नारी संघ की अगुआ बताती है कि "अगर उन्हें शाम को पतियों के हिंसा का सामना भी करना पड़े तो भी महिलायें बैठक में जरूर भाग लेती थीं। अब वे पीछे मुड़कर देखने के लिये तैयार नहीं थीं। इस प्रकार, महिलाओं ने परिवार व सामाजिक प्रतिरोधो का दृढ़ता के साथ सामना करके शक्ति नारी संघ की शुरुआत किया। लगभग सभी गाँवों में इसी प्रक्रिया के साथ नारीसंघ परिवर्तन का एक हिस्सा बना और उनकी एकता में ही उनकी शक्ति निहित हैं। एक बार फिर शक्ति नारीसंघ ने अपने अधिकारों का दावा करने के लिए एक ठोस कदम उठाकर अपनी पहचान स्थापित किया।

नारीसंघ की अगुआ बताती है कि "हम तब तक लड़ाई लड़ते रहे जबतक कि हमें जॉब कार्ड नहीं मिला गया। इसके लिए पाँच गाँव से नारी संघ की सदस्य एक साथ संगठित होकर खण्ड विकास अधिकारी के सामने जाकर अपनी माँग को प्रस्तुत किया। जॉब कार्ड मिलने के बाद हमें काम मिला, मेट का चयन हुआ और कार्यस्थल पर सभी सुविधाएँ प्राप्त होने लगी। उनका कहना है कि हमें सफलता इसलिए मिली क्योंकि हम संगठित हैं।"

रोजगार गारंटी कानून में काम मिलने के परिणाम के रूप में कृषि मजदूरी में भी बढ़ोत्तरी हुई है। गीता देवी बढ़ती हुई मजदूरी को विस्तार से बताते हुए कहती है कि "पिछले तीन साल पहले हमें दिन भर में 20 से 25 रुपये की कृषि मजदूरी मिलती थी, पिछले साल इसमें 60 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई और इस वर्ष कुछ कार्यों के लिए मजदूरी 100 रुपये तक मिल रही है।" सदस्यों को एहसास हुआ कि कृषि मजदूरी मनरेगा मजदूरी के बराबर होनी चाहिए और मनरेगा में काम के दिन भी बढ़ने चाहिए।

शक्ति नारीसंघ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) की स्थिति में सुधार के लिए भी पहल किया। इससे पहले लोगों को कभी भी, अनाज व मिट्टी का तेल सही समय पर व उचित मात्रा में नहीं मिलता था। इसी तरह की समस्या नारीसंघ की अध्यक्ष गीता देवी की बेटी के शादी समय पर भी हुई। उनके पति कोटे की दुकान से मिट्टी का तेल लेने गये। लेकिन कोटेदार ने उन्हें मिट्टी का तेल देने से इंकार कर दिया और उनके डिब्बे को दूर फेंक दिया। जब ये घटना नारीसंघ के सदस्यों का पता चला तो सभी सदस्य एकत्र होकर कोटेदार के पास गईं। जब कोटेदार का सामना सदस्यों से हुआ तो वह डर गया और सदस्यों को रोकने की क्षमता कोटेदार में नहीं हुई व उसने गीता देवी के पति को जरूरत के अनुसार मिट्टी का तेल तुरन्त दे दिया।

नारीसंघ के सदस्यों ने आर टी आई के माध्यम से कोटे के दुकान से सम्बन्धित सभी जानकारी इकट्ठा करके जिलाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर जाँच होने के बाद कोटेदार ने अपना लाइसेंस खो दिया। यह नारीसंघ के सदस्यों के लिए एक उपलब्धि थी, लेकिन व्यावहारिक रूप से कोटे की दुकान का दूर जाने से इस उपलब्धि का कोई मतलब नहीं रह गया था। महिलायें लंबे समय तक इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी और उन्होंने अपना उचित कोटा प्राप्त किया।

अक्सर परिवार और समुदाय के लोग टिप्पणी करते रहते थे कि इस संगठन से कुछ भी नहीं होने वाला है। "जब कोई भी बदलाव लाने के लिए सक्षम नहीं है तो आप लोग कैसे करेंगे? यह महिलाओं के पहल की प्रतिक्रिया थी। परन्तु नारी संघ की प्रक्रिया और उसके प्रभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब निराशावादी आवाज दूर व कम हुए हैं। अपनी अब तक की यात्रा के दौरान शक्ति नारी संघ ने यह अनुभव किया है कि जब से वे सामूहिक रूप से लड़ाई करने लगी है तब से उन्हें अपने अधिकारों का एहसास हुआ है। नारीसंघ के अगुआ का यह विश्वास है कि "अगर हम निरन्तर एक साथ चलते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी।"

6. ताकत का विस्तार करती नारीसंघ की महिलाएं

राधिका देवी को अब भी याद है कि जब नारीसंघ की नेतृत्वकारी महिलाएं जिला मजिस्ट्रेट से मिलने गयी थीं, तब उन्होंने खण्ड विकास अधिकारी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि "यदि आप दो दिन के अंदर इन महिलाओं का जॉबकार्ड देने में असफल होंगे, तो मैं आपको आपकी कार्य एवं जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफलता के परिणामस्वरूप मैं आपका वेतन रोक दूंगा।" उन्होंने बी डी ओ को यह चेतावनी दी और बी डी ओ ने आवश्यक कार्यवाही की।

राधिका नारीसंघ का गठन वर्ष 2008 में गाजीपुर जिले के सदर ब्लॉक के रसूलपुर ग्रामपंचायत में हुआ, इस नारीसंघ की अध्यक्ष राधिका देवी हैं। अन्य अगुआ महिलाएं अतवारी देवी एवं कुन्ती देवी क्रमशः सचिव एवं सूचनामंत्री के पद पर हैं। ग्रामीण विकास संस्थान ने गठन में सहजकर्ता की भूमिका निभायी।

यह घटना नारीसंघ के गठन के कुछ माह बाद ही घटित हुई। राधिका देवी प्रयासों का विस्तृत विवरण करते हुए बताती हैं कि "हम लोगों ने ग्रामप्रधान के पास जॉबकार्ड के लिए आवेदन किया। उसने ऐसी प्रतिक्रिया दिखायी जैसे वे बहुत ही व्यस्त हैं। उनके प्रतिक्रिया को देखते हुए मैंने उनको प्रावधान से अवगत कराते हुए कहा कि आवेदन करने के 15 दिन के अंदर जॉबकार्ड मिल जाना चाहिए।" यह सुन करके उनको गुस्सा आ गया।" उन्होंने गुस्से से चीखते हुए कहा कि हमें नियम न बताओ, मुझे जब समय मिलेगा तब मैं करूंगा, इंतजार करना है तो करो अथवा जहा से हो सके बनवा जाओ आर बनवा लो।" जब उन्होंने दलील को

अभी कुछ समय पहले की बात है जब मऊ जिले में महिला अगुआ का सम्मेलन हुआ था। जिसमें की 9 जिले के लोग आए थे। इतनी बड़ी संख्या में सशक्त महिलाओं को देख करके हम लोगों को भी बहुत संबल मिला, और महसूस हुआ की हम लोग अकेले नहीं हैं।



खारिज कर दिया तब हम लोग सचिव के पास गए, तो वे भी आपने काम पर नहीं थे। जब स्थानीय स्तर पर किए प्रयास का कोई भी परिणाम नहीं दिखाई दिया तब महिलाएं संबंठित होकर के ब्लॉक पर बी डी ओ के पास गयीं। वहां पर भी नारीसंघ की बात की सुनवायी तो हुई किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्राम प्रधान से लेकर के बीडीओ, सभी स्तर पर महिलाओं के धैर्य की परीक्षा लेते हुए दिखायी दिए। वे सोच रहे थे कि जल्दी ही वे हत्तोतसाहित हो जाएंगी। लेकिन नारीसंघ की महिलाओं ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि जब तक उनके हाथ में उनका जॉबकार्ड नहीं होगा, तब तक वे चुप नहीं बैठेंगी। प्रयास की अगली कड़ी में, वे ब्लॉक पर मनरेगा दिवस की सार्वजनिक बैठक में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची। यहां जिलाधिकारी के

समक्ष आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया और जिलाधिकारी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने महिलाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके मुद्दे पर शीघ्र ही कार्यवाही की जागी। अगले ही दिन इस लम्बे संघर्ष का फल भी मिला। प्रधान एवं सेक्रेटरी ने बैठक कर जॉबकार्ड वितरित किए।

लेकिन अब भी नारीसंघ के संघर्ष की लड़ाई समाप्त नहीं हुई। जॉबकार्ड प्राप्त करने के बाद भी, महिलाओं को काम एवं उसके उचित भुगतान के लिए पुनः संघर्ष करना पड़ा। "काम समाप्त होने पर कुछ को 50 रूपए तो कुछ को 60 रूपए, मजदूरी का भुगतान किया गया। नारीसंघ की अध्यक्ष बताती हैं "हम लोग शांत न बैठ करके बी डी ओ से मिलने गए। हम लोगों ने उनसे माँग

की, तकनीकी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही मजदूरी का वितरण होना चाहिए। एक बार जब यह सब हो गया, तभी से 100 रूपए मजदूरी मिलने लगी।”

इस नारीसंघ को अपने गाव मे सस्ते गल्ले की दुकान को नियमित करने के लिए भी इसी तरह का संघर्ष छेडा गया। इस कार्य के लिए तहसील दिवस- तहसील स्तरीय जन सुनवायी के द्वारा शिकायत का निस्तारण, जिसमे ग्रामपंचायत स्तरीय समस्यओ का समाधान का आयोजन किया जाता है। महिलाओ को एहसास हुआ कि कोटेदार उनके साथ चाल चल रहा है। वह लोगो को बताता था कि चीनी का कोटा समाप्त हो गया है किन्तु फिर भी उनके कार्ड मे वह वितरित लिखता था। जब महिलाओ ने उससे पूछताछ की, तब वह महिलाओ को अपनी तरफ करने का प्रयास करने लगा। अनुरोध करते हुए कहा कि “मैं आप लोगो को जितनी जरूरत होगी, उतनी चीनी दूंगा, लेकिन आप लोग इसको आप लोग मुददा मत बनाइए।” लेकिन महिलाओ ने कहा कि सभी को उनके कार्ड के अनुसार ही मिलना चाहिए।अभी भी कोटेदार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, अत तहसील दिवस मे उपजिलाधिकारी के समक्ष यह घटना प्रस्तुत की।एक सप्ताह के बाद एस डी एम एवं सप्लाई औचक निरीक्षण के लिए गाव मे आए। कोटे के वितरण मे अनियमितता होने के कारण कोटेदार का लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया और साथ ही एक नए कोटेदार की नियुक्त किया।

नारीसंघ ने लोगो को आश्वस्त करते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओ की पात्र व्यक्तियो को लाभ अवश्य मिलेगा।” हम लोगो के पहल एवं प्रयास से 12 लोगो को महामाया पेंशन योजना एवं 4 लोगो को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिला।” कुछ लोगो को बिना लिखित सूचना के कल्याणकारी योजनाओ के लाभार्थी की सूची से नाम हटा भी दिया गया। नारीसंघ ने इस मुददे पर आर टी आई के माध्यम से पहल की। इसके बाद जब आवेदन डाला गया तो पेंशन पुनः प्रारंभ हो गयी।

लोग नारीसंघ के काम को अभी भी महत्व नहीं देते, जब भी महिलाए ब्लाक अथवा जिला कार्यालय पर जाती तब भी लोग व्यंग कसते थे,और कहते “ देखो ये लोग चली है नेता बनने”।किन्तु अब यदि ब्लाक या जिले पर किसी अधिकारी से मिलने जाना होता है तो पुरुष भी नारीसंघ से बातचीत करने के बाद ही जाते है और कभी कभी नेतृत्वकारी महिलाओ को साथ मे ले करके भी जाते है। अब वे कहते है कि “यदि महिलाओ ने पहल नहीं की होती तो गाव वालों को कभी भी मनरेगा के अंतर्गत कुछ भी न तो जाबकार्ड और न ही काम मिल पाता।”

लेकिन नारीसंघ की बहने सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अन्य गावो तक अपनी पहुँच को मानती है। “पहले हम घर से बाहर निकलने मे भी डरते थे किन्तु अब तो हम लोग जिले तक भी आसानी से चले जाते हैं। नारी महासंघ के माध्यम से आस पास की ग्राम पंचायतो मे नारीसंघ से जुडी बहनो की भी समस्याओ के समाधान के लिए पहल करने का प्रयास करते है।” नारीसंघ ने असंभव को भी सम्भव बना दिया।” मार्च 2011 मे मऊ जिले मे क्षेत्रीय अगुआ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमे की 9 जिले की अगुआ बहनो ने प्रतिभाग किया।’ बहुत सी नेतृत्वकर्ताओ से मिल करके लगा कि नारीसंघ सशक्त हो गया है, और तब हम लोगो को लगा कि हम लोग अकेले नहीं है बल्कि हम लोगो की संख्या बहुत बडी है।’ यह कहना है नारीसंघ की अध्यक्ष का, जिनको लगता है कि इस तरह की बातचीत, सम्मेलनो मे प्रतिभाग करके एवं एकत्रित होने से नारीसंघ के आत्मविश्वास एवं ताकत मे वृद्धि होती है।

7. अधिकारों की प्राप्ति

“यह नेता नहीं बनेगी,” इस बात की घोषणा करते हुए राधा देवी के पति उनको नारी संघ के बैठक में जाने के लिए मना करते थे। यह एक बड़ी समस्या थी जिसको सद्भावना नारी संघ के सदस्यों को संगठन के गठन के प्रक्रिया के दौरान सामना करना पड़ा था। परिवार के सदस्यों द्वारा, विशेषकर पति सबसे ज्यादा आपत्ति उठाते थे और अपने पत्तिनयों को बैठक में जाने के लिए मुश्किल पैदा करते थे।

महिलायें व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर इस समस्या के लिए आवाज उठाती रही है। राधा देवी के मामले में, दस महिलायें सामूहिक रूप से इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उनसे मुलाकात किया। उन्होंने उनसे बात किया और कहा जब तक नारी संघ के प्रति आपकी सोच नहीं बदल जाती तब तक हम आपका घर छोड़कर नहीं जायेंगे। और अब राधा देवी नारी संघ की सचिव है।

सद्भावना नारी संघ का गठन बस्ती जिले के सदर ब्लाक के सोनबरसा ग्राम पंचायत की महिलाओं द्वारा सभी प्रकार के समास्याओं पर आवाज उठाने के लिए किया गया। इस संगठन का गठन मई 2009 में सद्भावना नारी संघ के सहयोग से किया गया और वर्तमान में, इस संगठन में कुल 182 महिलायें, सदस्य है। नारी संघ के सदस्यों ने शोभा देवी को अध्यक्ष व मनसा देवी को कोषाध्यक्ष पद के लिए चयन किया।

मनरेगा के बारे में जानकारी होने के बाद नारी संघ की महिलाओं ने अपना जाब कार्ड बनवाने का फैसला किया। उन्होंने एक आवेदन पत्र लिखा और रोजगार सेवक के पास लेकर गयी। लेकिन उसने आवेदन लेने से इन्कार कर दिया। सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों से बचने के लिए, यह एक विशिष्ट तरीका है। ये लोग जानते हैं कि यदि औपचारिक रूप से आवेदन स्वीकार कर लेंगे तो 15 दिन के अन्दर काम उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उनकी हो जायेगी। नारी संघ की महिलाओं को यह पहले से



महिलाओ ने सिर्फ अपने अधिकारो तक पहुँच कर प्राप्त ही नही किया, अपितु समाज मे लोगो को महसूस हो गया कि अब उनको और मूर्ख बना करके अधिकारो का हनन नही किया जा सकता।

पता था, इसीलिए उन्होंने रोजगार सेवक पर आवेदन लेने के लिए दबाव डाला। जब वह महिलाओं को नजरअंदाज करने लगा तो महिलायें उसके घर के सामने बैठकर गीत गाने लगी। जब उसने महसूस हुआ कि महिलायें उसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं है तो उसने अपने सहयोग के लिए ग्राम प्रधान को भी बुला लिया। जब ग्राम प्रधान भी महिलाओं को वापस भेजने में सफल नहीं हुआ तो इन दोनों ने अपने सहयोग के लिए पंचायत सचिव को बुलाया। महिलाओं की दृढ़ता को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गये और इस समय ये लोग महिलाओं को जबाव देने के लिए तैयार नहीं थे। ये लोग महिलाओं से, प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी की उम्मीद नहीं कर रहे थे। पंचायत सचिव ने उनसे पूछा, “तुम्हें यह

कैसे पता चला ?” ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे पता चलने के बाद ये लोग संस्था के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हुये उन पर आरोप लगाने लगे। ये अपने बचाव की कोशिश करते हुए कहने लगे कि “महिलाओं को जानकारी देना गलत है, हम लोग काम नहीं करेंगे, आप क्या कर लेंगे ?” कार्यकर्ता ने कहा कि, “यदि आप इन्हें काम नहीं देंगे तो महिलायें खण्ड विकास अधिकारी के पास जायेगी।” इस तरह के मामले में खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत सचिव से ही अपना काम सही ढंग

से ना करने के लिए स्पष्टीकरण माँगता है। इस बात का एहसास होते ही उसने तुरंत कहा कि, वह आवेदन स्वीकार करेगा। संगठन के लिए यह पहला सबक था कि जब आप जागरूक व संगठित हो जाते हैं, तब अपने अधिकारों का एहसास भी हो जाता है।

लेकिन महिलाओं को जाब कार्ड मिलने के बाद भी काम नहीं मिल रहा था, इसलिए पुनः महिलाओं को प्रधान के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। नारी संघ की अध्यक्ष बताती है कि "जब उसने हमें काम नहीं दिया तो हमने जबरदस्ती नरेगा कार्यस्थल पर जाकर काम करने की कोशिश किया, और पुनः काम पाने के लिए खण्ड विकास अधिकारी के पास गये।" महिलाओं ने ना केवल अपने काम का अधिकार सुरक्षित किया है बल्कि यह तथ्य भी स्थापित कर दिया है कि अब वे लोग जागरूक हो गयी है और उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। प्रधान अब इतना बदल गया है कि महिलाओं को पहले से ही काम के लिए में सूचित कर देता है।

यह उल्लेखनीय है कि महिलाओं ने केवल अपने स्वयं के हकदारी के लिए ही काम नहीं किया है बल्कि वे महिलाओं के अन्य मुद्दों पर भी जागरूक व संवेदनशील हुई है। महिलाओं द्वारा अब सामूहिक रूप से अपने गाँव में अन्याय के खिलाफ हस्ताक्षेप किया जाने लगा है, इसका एक उदाहरण फूलपरी है।

फूलपरी सोनवरसा गाँव की रहने वाली है। वह बहुत गरीब है और मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों के साथ अपने परिवार के भरण-पोषण करती है। इसी गाँव की, होम गार्ड का काम करने वाली, एक अन्य महिला जिसका नाम सवारी देवी है, फूलपरी को परेशान करती थी। गरीब और वंचित होने के नाते, वह सवारी देवी का विरोध नहीं कर पाती थी और जब फूलपरी को उसका व्यवहार असहायनीय लगने लगा तो वह सवारी देवी से भिड़ने के बजाय पास के दूसरे गाँव में रहने चली गयी। वहाँ वह एक घर में नौकरानी का काम करने लगी। जब नारी संघ की महिलाओं को फूलपरी के स्थिति के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसकी स्थिति जानने के लिए उसे नारी संघ की बैठक में बुलवाया। फूलपरी ने अपनी कहानी बताया जो हर किसी के दिल को छू गयी। नारी संघ की महिलाओं ने उसे यह आश्वासन दिया कि यदि वह अपने घर वापस आना चाहती है तो नारी संघ की महिलायें उसका पक्ष लेगीं और उसके साथ खड़ी होंगीं। अगले दिन फूलपरी अपने घर वापस आ गयी और सवारी देवी ने पुनः उसे परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन नारी संघ के हस्तक्षेप के कारण इस बार उसका प्रयास विफल हो गया। नारी संघ की महिलाओं ने उसका घर घेर लिया और उसे अपना व्यवहार बदलने के लिये चेतावनी दिया। उसने फूलपरी से माफी मांगा। नारी संघ के सदस्यों ने उसे चेतावनी दिया कि, "यदि पुनः हमें यह होते हुए दिखायी दिया तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे और तुम्हारे खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवायेंगे।" सवारी देवी ने उसी दिन के बाद से फूलपरी को परेशान करना बंद कर दिया। बाद में फूलपरी नारी संघ के सदस्य बन गयी और अपने जीवन में इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत भी हो गयी।

नारी संघ की अगुआ बताती है कि, "नारी संघ से जुड़ने के बाद हमने एहसास किया कि हम साथ रहकर ही अपने अधिकारों की पूर्ति करने के लिए सक्षम है केवल संगठित होकर मांग करने की जरूरत है।" अंततः उनको यह भी पता है कि सत्ता में बैठे लोग आसानी से ऐसा नहीं होने देंगे। किन्तु ये महिलायें अपनी रणनीतियों के साथ इस तरह के चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं।" यहां तक कि मांगने के बाद भी हमें नहीं मिल पाता था, देने वाले लोग ही इसे हड़पना चाहते हैं।" सही मायने में महिलाओं को इस सत्यता का एहसास हो गया है कि कोई भी अधिकार, किसी के देने से नहीं मिलता बल्कि यह स्वयं से पूरा किया जा सकता है।

8. संगठन ही समाधान

बस्ती जिले के बस्ती सदर ब्लाक की ग्रामपंचायत देवरिया के नारीसंघ मे कुल 170 सदस्य है। चार महिला नेतृत्वकर्ताओ का सशक्त संगठन है, जिसमे अवधेश कुमारी अध्यक्ष, मेहरुन्निशा सचिव, साधना देवी कोषाध्यक्ष एवं राजमती देवी संगठन मंत्री है।

सहजकर्ता के रूप मे कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही संस्था सदभावना ग्रामीण विकास संस्थान का विचार है कि "देवरिया नारीसंघ के पास नारीसंघ के गठन से ले करके अभी तक की बहुत सी उपलब्धियां रही है, किन्तु इसका प्रारम्भ आसान नहीं था।" इस तथ्य का स्वीकारते हुए अवधेश कुमारी कहती है कि "हले हम लोग संगठित होने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि स्वयं सेवी संगठन से जुड़ने का हम लोगो का अनुभव अच्छा नहीं था। हम लोगो ने 7 स्वयं सहायता समूहो का गठन किया किन्तु हम लोगो को कोई भी सम्मेलन नहीं मिली जिसके परिणामस्वरूप समूह निष्क्रिय हो गया। इसी कारण जब पहले संस्था की कार्यकर्ता सुनीता बहन ने नारीसंघ के गठन की बात हम लोगो को बतायी तब हम लोगो ने एक सिरे से ही इस बात को खारिज कर दिया।" किन्तु वे पास के ही गांव की थी



और हम लोग भी उनको जानते थे तो उन्ही के भरोसे पर हम लोगो ने संगठन के गठन की प्रक्रिया का प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हम लोगो को तब तक कोई भी लाभ नहीं होगा, हमे हमारे अधिकार नहीं मिल पाएंगे, जब तक की हम संगठित हो करके मुददो पर पहल नहीं करेगे।" अवधेश कुमारी उन कुछ महिलाओ मे से है जिन्होंने संगठन की कल्पना को साकार किया।

"उन्होंने अनेक कार्यक्रमो एवं योजनाओ तथा संबंधित प्रावधानो की भी जानकारी दी। योजनाओ के जानने के बाद हम लोग यह जानने के लिए रुचि लेने लगे, कि किस तरह से ये योजनाए पात्रो को प्राप्त हो सकती है। सुनीता बहन ने कहा कि योजनाओ को प्राप्त करने के लिए और बहनो को संगठित करने की आवश्यकता है।" मैने देखा कि अभी बहुत सी महिलाए संगठित नहीं हुई थी तो मैने संगठन को मजबूत करने के लिए नेतृत्व करने का निर्णय लिया। मई, 2009 तक संगठन मे 43 महिलाए संगठित हो चुकी थी और इस मरह से नारीसंघ का गठन हुआ।" ये महिलाए नया नयी जानकारीओ को प्राप्त करके समस्याओ का समाधान करने का प्रयास करती है जिससे कि इनके जीवनस्तर मे सुधार हो सके।

लेकिन परिवार के सदस्य अभी भी सहमत एवं आश्वस्त नहीं थे। अवधेश कुमारी के पति एवं सास ससुर को भी नारीसंघ के गठन

अब तो इस गांव मे यह प्रथा ही हो गयी है कि नारीसंघ की अगुआ एवं सदस्य को प्रधान ग्रामसभा एवं अन्य आवश्यक बैठकों एवं मुददों की जानकारी पहले ही देने लगे हैं।

की बात रास नहीं आयी। "उन लोगो ने इसी बात के गुस्से के कारण मुझसे कई दिन बात नहीं की।" लेकिन उन्हे नारीसंघ के गठन से कई तरह के सामूहिक लाभ दिखाई पड रहे थे, अतः उनकी सोच थी कि अधिक से अधिक महिलाए नारीसंघ की सदस्य बने। इनका यह तथ्य इस पूरी बात की समझ प्रस्तुत करता है " देखिए जब हम लोग घर पर रहते थे, तब हम लोगो को कुछ भी नहीं मिलता था, किन्तु जब से बाहर निकलने और ब्लाक तक जाने मे सक्षम हुए तब जा करके हम लोगो का जाबकार्ड प्राप्त हुआ।"

जाबकार्ड प्राप्त करने के बाद महिलाओ को काम भी मिला, किन्तु यह अति उत्साह आया। नारीसंघ की अध्यक्ष बताती है कि " एक दिन महिलाए कार्यस्थल पर मिट्टी ढो रही थी, किन्तु पुरुष उनके टोकरी मे बहुत अधिक मिट्टी भर रहे थे। हम लोग उसको उठा ही नहीं पा रहे थे, और जल्दी ही हम लोगो के गर्दन एवं कमर मे दर्द होने लगा। इसलिए हम लोगो ने उन लोगो को कम मिट्टी डालने के अनुरोध किया किन्तु किसी भी तरह से उन लोगो ने नहीं माना। इसके विरोध मे हम महिलाओ ने काम को रोक दिया और कार्यस्थल पर ही बैठे रहे। हम लोगो ने सुपरवाइजर को आज के काम

की पूरी मजदूरी देने एवं कार्यस्थल पर उत्पन्न की गयी समस्याओं को समाप्त करने का अनुरोध किया। आपसी एकता के कारण ही हम लोग अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में सफल हुए और इसी घटना के साथ नारीसंघ की शक्ति एवं पहचान बढ़ी।”

नारीसंघ की सदस्यों को आभास हुआ कि वे एकता के साथ मुद्दों पर पहल करके ही सफलता प्राप्त कर सकती हैं, और इसी जोश में महिलाओं ने और भी मुद्दों पर आवाज उठाई।” हम लोगों को राशन की दुकान से सही राशन नहीं मिलता था एवं साथ ही कोटेदार हम लोगों से मनमाने पैसे भी लेता था। इसी कारण हम लोगों ने हेल्पलाइन का प्रयोग कर उसकी शिकायत दर्ज करायी।” यह कहना है कोटेदार के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने वाली सदस्य का, वह इस कार्यवाही को देखकर हैरान रह गयी क्योंकि उसकी समस्या का तेजी समाधान मिला। कोटेदार को कड़ी चेतावनी दी गयी, और इस सफलता ने नारीसंघ के आत्मविश्वास को और मजबूत कर दिया।

इसी आत्मविश्वास के साथ महिलाओं ने सचिव का भी सामना किया, “हम महिलाओं ने सचिव से ग्राम सभा के आयोजन करने की मांग की, किन्तु उस समय सचिव में कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त करते हुए प्रधान से चर्चा कर मुझे बुला करके बैठक के आयोजन की तिथि बतायी। पहली बार हमारे गाव की महिलाएं इस तरह से किसी बैठक में गयी थी।” अवधेश कुमारी ने बताया। अब नारीसंघ की सदस्य सदैव ही इस बैठक में बढ़ करके प्रतिभाग करती हैं।

अब तो नारीसंघ को ग्रामसभा के आयोजन से संबंधित सभी जानकारी, जैसे दिन एवं तारीख पहले से ही पता रहती है और यह अब धीरे धीरे एक प्रथा हो गयी है कि नारीसंघ की सदस्य को सूचित किए बिना किसी भी बैठक का आयोजन ग्रामसभा में नहीं किया जाता है। नारीसंघ की सदस्य मानती हैं कि सेवादाताओं पर दबाव समूह के रूप में कार्य करती हैं।” नारीसंघ के प्रयास के परिणामस्वरूप ग्रामसभा का नियमित आयोजन किया जाने लगा। अब हम लोग व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास के मुद्दों को रखते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है, तब दबाव समूह के रूप में भी कार्य करते हैं।”

नारीसंघ के प्रयास के परिणामस्वरूप मेवाती देवी, जो विधवा है, को सरकारी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ। उनको विधवा पेंशन एवं और एक घर सरकारी योजना के अंतर्गत आवंटित हुआ। पहले एकल महिलाओं की समस्याओं को प्रासथमिकता में ले करके कोई भी पहल नहीं होती थी। मेवाती देवी को तो योजनाओं के बारे में पूछने की न तो हिम्मत थी और न ही जानकारी, किन्तु नारीसंघ ने उसके हक के लिए लड़ाई लड़ी।

नारीसंघ ने घरेलू हिंसा से संबंधित मुद्दों पर भी पहल की। नारीसंघ की सदस्य को उसके पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था तब नारीसंघ ने उसको पूरा सहयोग किया। नारीसंघ उसके पति के पास जाकरके बोली की वह अपनी पत्नी को मारना और अपशब्द बोलना बन्द कर दे, किन्तु उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किन्तु जब महिलाओं ने उसके कड़े शब्दों में कहा कि नारीसंघ इसकी शिकायत पुलिस में करेगा, तब उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। महिलाओं को लगता है कि नारीसंघ से जुड़ने के बाद ही वे अपने को महत्व देने लगी हैं।

नारीसंघ की अगुआ यह बोलते हुए गर्व महसूस करती हैं कि “अब हम लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब हमारे परिवार के पुरुष भी हम लोगों से ही सरकारी योजनाओं एवं उनके प्रावधानों को पूछते हैं। पहले जो असम्भव लगता था अब हम लोगों में एकता के कारण वह सब सम्भव हो गया। हम लोग अब हमेशा अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सदैव संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं।” उन लोगों ने अपनी सामूहिक शक्ति को समुदाय से लेकर के सरकारी दफ्तरों में भी कर ली है। अब तो अधिकारी भी देखते ही कहते हैं कि “नारीसंघ की महिलाएं आ रही हैं, इनका काम जल्दी से पूरा करिए”। अब तो यदि कोई महिला किसी काम के संदर्भ में आवेदन देती है तब भी उसे शीघ्र बुला करके उसके बातों को सुन करके काम कर देते हैं।

9. नारीसंघ के सहयोग से गांव में नरेगा कार्ययोजना बनी

नारीसंघ ने महिलाओं को अपने हालातों व अन्य समस्याओं से समझौता करने की जगह उन्हें साहसी व आशावादी बनाया है। सिसवा बाबू गांव में महिलाओं को इस घटना से कोई अपत्ति नहीं है।

जब नारीसंघ की सदस्यों से पूछा गया कि आपने क्यों संगठन बनाकर कार्य करना पसंद किया तो उन्होंने कहा कि इस संगठन के माध्यम से हम समस्याओं पर पहल कर अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकेंगे। महिलाएं आत्मविश्वास व प्रतिष्ठा के साथ जीवनयापन करना चाहती हैं। नारीसंघ का गठन सृष्टि सेवा संस्थान के द्वारा महाराजगंज जिले के सदर ब्लॉक के सिसवा बाबू ग्राम पंचायत में मई 2009 में हुआ और नारीसंघ में 156 सदस्य हैं।

सभी महिलाओं के समस्या पर पहल करने और नारीसंघ के सदस्यों के बीच सहयोग की भावना को बनाये रखने के लिये और बैठक के संचालन की मुख्य रूप से जिम्मेदारी अगुआ पूजा देवी, सरिता देवी और हसीबुननिशा की है। वे ब्लॉक व जिला स्तर पर नारीसंघ की महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों को उठाती हैं।

नारीसंघ अपने सदस्यों को पी0डी0एस0, मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर, इन योजनाओं को प्राप्त करने के लिये पहल करती है। पूजा देवी ने काम के अधिकार के अर्न्तगत मनरेगा में काम प्राप्त करने का अनुभव बताते हुए कहती है कि "जब महिलाएं पहली बार प्रधान और रोजगार सेवक के पास गयीं, तो उन्होंने काम देने से इंकार करते हुए कहा कि यहाँ आप लोगों के लिए कोई काम नहीं है। बी0डी0ओ0 ने भी उन्हीं की बात का समर्थन किया। हम महिलाओं को मालूम था कि वे हम सभी से झूठ बोल रहे हैं और फिर नारीसंघ ने उनसे इसी बात को लिखित रूप में देने की मांग की, किन्तु यह सुन करके बी0डी0ओ0 ने काम उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।" सृष्टि सेवा संस्थान से नारीसंघ को जानकारी प्राप्त हुई, कि मनरेगा के अर्न्तगत काम के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उचित योजना ही नहीं तैयार की गई है। अतः संस्था के सुझाव के आधार पर नारीसंघ ने ग्राम पंचायत की मदद से मनरेगा समिति गठित की, जो इस ग्राम पंचायत में पहली बार विभिन्न विकास के मुद्दों को चिन्हित करके आवश्यकताओं का आंकलन कर योजना निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ की। मनरेगा समिति के प्रयास से मनरेगा पंचवर्षीय योजना को ग्रामसभा में पास होने के बाद बी0डी0ओ0 के समक्ष प्रस्तुत किया। निरंतर प्रयास के पश्चात् गाँव में मनरेगा के अर्न्तगत 11 लाख रुपये की धनराशि का कार्य प्रारम्भ हुआ। नारीसंघ ने प्रधान से कहा कि "अब हम लोगों को मनरेगा प्रावधान



के अनुसार 100 दिनों का कार्य मिलना चाहिए क्योंकि हम लोगों के प्रयास से 100 दिन का काम अब ग्राम पंचायत में उपलब्ध है।”

नारीसंघ की पहल से कोटेदार संबंधी समस्या पर भी सफलता मिली। इस ग्राम पंचायत के कोटेदार की दुकान महीने में एक बार खुलती थी, वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मानक अनुसार राशन वितरित नहीं करता और जब लोग आवाज उठाते तब वह लोगों से बेरुखी से व्यवहार करता था। जब नारीसंघ भोजन के अधिकार के अर्न्तगत कोटेदार से मानक के अनुसार राशन वितरित करने को कहा, तो कोटेदार ने कहा कि “नारीसंघ हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी पहचान जिलास्तरीय अधिकारियों से है और मैं ही सिर्फ गबन नहीं करता बल्कि सभी अधिकारी इसमें अपना हिस्सा ले कर आपस में माल बॉट लेते हैं” परन्तु किसी को भी इन अधिकारियों के विरुद्ध बोलने के हिम्मत नहीं है। नारीसंघ ने साहस के साथ कोटेदार के द्वारा किये जाने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध करते हुए गांव के प्रधान से उसकी शिकायत किया। प्रधान के द्वारा कोई पहल नहीं होने पर नारीसंघ ने जिलाधिकारी से कोटेदार की शिकायत की, किन्तु वहां भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसके विपरीत पूजा देवी को धमकी मिली। अब गाँव के लोगों को कोटेदार द्वारा कहे शब्दों पर विश्वास होने लगा कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। किन्तु नारीसंघ चुप नहीं बैठी और आर0टी0आई0 के माध्यम से कोटेदार से संबंधी सूचनाये प्राप्त कर रणनीति बनाई और हेल्पलाईन नम्बर पर शिकायत दर्ज कराई। अब कोटेदार के खिलाफ जांच-पडताल की कार्यवाही होने पर यह साबित हो गया कि वह कार्डधारको के हिस्से का राशन वितरित न कर राशन खुली बाजार में बेच देते हैं। नारीसंघ ने प्रमाण के साथ जिलाधिकारी से कोटेदार की पुनः शिकायत की। नारीसंघ द्वारा कोटेदार के खिलाफ किये गये इन सभी प्रयासों से कोटेदार ने दण्ड का भुगतान किया और उसके कामकाज में भी सुधार आया। नारीसंघ की अगुआ पूजा देवी कहती है कि “शुरुआत में हमें निराशा मिली, लेकिन हम महिलाओं ने दृढ़ संकल्प के साथ निरन्तर संघर्ष करते रहे, अब हम महिलाओं को किसी भी धमकी से फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा। किन्तु नारीसंघ को यह सफलता सामूहिक एकता व संगठित रूप से किये गये पहल से मिली है।”

महिलाओं में बहुत परिवर्तन आया है, अब वे आत्मविश्वास एवं जानकारी से लबरेज हो करके सेवादताओं से बात करने लगी हैं।

जब महिलाओं से पूछा गया कि क्या नारीसंघ के कारण महिलाओं में क्या परिवर्तन हुए हैं, तुरन्त ही नारीसंघ की अगुआ ने बताया कि “हम महिलाओं में बहुत बदलाव आया है, पहले हम किसी भी अधिकारी से बात करने से डरते थे लेकिन अब हम लोग अधिकारियों के साथ बातचीत करती हैं, घर से बाहर निकलने से जानकारी व आत्मविश्वास बढ़ा है। काम के अधिकार के अर्न्तगत मनरेगा में 100 दिनों का काम मिलने से अब पारिवारिक आय में महिलाओं की भी सहभागिता बढ़ी है।”

10. सक्रिय एवं जबावदेह बना सरकारी तंत्र

30 आर0टी0आई0 एवं 80 बार हेल्पलाइन का प्रयोग करने एवं अन्य ग्रामपंचायतों में करवाना, इस तरह की आंकड़ा बिना किसी संकोच के पेडरा ग्रामपंचायत के इन्कलाब नारीसंघ, विकासखण्ड अतरौलिया, जिला आजमगढ़ के नारीसंघ की महिलाएं बताती हैं। इसका प्रयोग उनके द्वारा पूरे ब्लॉक में मनरेगा के अंतर्गत काम एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य अधिकारों को प्राप्त करने की पहल की। इन्कलाब नारीसंघ का गठन वर्ष 2008 में गठन की प्रक्रिया कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने वाली ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत 40 सदस्यों के साथ नारीसंघ का प्रारम्भ हुआ और वर्तमान में 110 सदस्य हैं।

अध्यक्ष सुरसत्ती देवी बताती हैं कि सामूहिक गठन से महिलाओं की सोच में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। "पहले व्यक्तिगत लाभों के लिए ही चिंतित रहते थे। यदि हम लोगों को किसी योजना या लाभा का पता चलता तो हम किसी को बताने के बारे में सोचते ही नहीं थे बल्कि प्रयास करते कि किसी को पता न चले। हम बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि अन्य को मिल रहा है या नहीं, किन्तु अब ऐसा नहीं है।" नेतृत्वकारी महिलाएं, जिनका विश्वास है कि संगठन के माध्यम से ही स्थिति में सुधार आ सकता है, किन्तु खण्डित होने पर अधिकारों तक पहुँच नहीं हो सकेगी। महिलाएं पहले की तरह नहीं हैं, अपितु वे संगठित हो करके विचार एवं कार्य करती हैं। अब प्रयास करते हैं कि वास्तव में जरूरतमंद, जो कि पात्र हैं उनको ही लाभ मिले।

नारीसंघ की पहल को पुरुषों द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जाता था, बल्कि यह मजाक और उपहास का विषय था। "रास्ता दो, भाई नेता आ रही है।" जब महिलाएं बैठक के लिए जाती तो गाँव के लोग टिप्पणी करते। पुरुष बैठक स्थान के आस पास ही टहलते रहते और कुछ तो पास ही में बैठ करके ताश भी खेलने लगते, जिससे कि वे हम लोगों के ऊपर नजर रखकर बुरी टिप्पणी भी कर सकें। महिलाओं ने इन लोगों की अपमानजनक बातों को नजरअंदाज करते हुए कार्य करने का प्रयास करती रहीं। अंततः सहज करने वाली संस्था के माध्यम से दी जाने वाली जानकारियों एवं अनुभवों से नारीसंघ अधिक जागरूक हो कर प्रभावी क्रियान्वयन करने में सक्षम हुआ।

महिलाएं चिन्हित समस्याओं पर रणनीति बना करके पहल कर रही हैं। इनमें प्रत्येक स्तर पर सरकारी अधिकारियों को लिखित आवेदन के माध्यम से अनुरोध, दबाव के रूप में आर0टी0आई0 का प्रयोग और प्रजातांत्रिक रूप में दबाव समूह के रूप में कार्य कर रही हैं। अधिकारों को प्राप्त करने के लिए महिलाएं बहुत सी युक्तियाँ अपना कर पहल कर रही हैं।



अगस्त 2011 में नारीसंघ की सोना देवी ने अपनी समस्या बतायी कि शिकायत कर उसका निरंतर अनुसरण करने के बावजूद भी उनकी मजदूरी लगभग एक साल से लम्बित है। इस बैठक की अध्यक्षता लालपत्ती देवी द्वारा की गयी। दो बैठकों में चर्चा के उपरांत मांग को पूरा करने के लिए महिलाओं ने ब्लाक पर जाने का निर्णय लिया। 25 अगस्त को प्रातः ही 62 महिलाएं संगठित हो कर ट्रैक्टर ट्राली से अतरौलिया पहुंची, नारीसंघ से प्रेरित हो कर 52 पुरुष भी उनके साथ साइकिल से गए। इतनी संख्या देखकर एडीओ ने उन लोगों से आने

पहले की तरह अब महिलाएं स्वार्थी नहीं हैं, अपितु वे संगठित सोच के साथ विचार एवं पहल करने लगी हैं। इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि पात्र व्यक्तियों को ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

का कारण पूछा। लालपत्ती देवी ने कहा कि वे खण्ड विकास अधिकारी से मिलना चाहती हैं, तब उन्होंने कहा कि वे आज नहीं हैं, किन्तु महिलाएं आज नहीं सुनने को तैयार नहीं थीं और बीडीओ कार्यालय की ओर जाने लगीं। लालपत्ती देवी ने उनके कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया कुछ कर्मचारी एवं अन्य लोग अंदर ही बन्द हो गए। दो महिलाओं को द्वार पर निरीक्षण करने के लिए खड़ा करके, वे मांग करने के लंबी कि ताला बीडीओ या फिर एडीएम के आने पर ही खोला जाएगा। जब उन लोगों को आश्वासन मिला कि 20 मिनट में एसडीएम आ जाएंगे, तब ताला खोला। एडीएम पहुंचे और उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। महिलाओं ने उनसे लिखित प्राप्त करने की मांग की। अन्त में महिलाएं वापस गयीं और 15 दिन तक प्रतीक्षा की, अभी भी मजदूरी नहीं मिली तो पुनः एडीएम से मिलने गयीं। पहली बार ब्लाक पर गए उनको 3 महीने हो चुके हैं किन्तु संघर्ष करने पर कोई भी सफलता नहीं प्राप्त हुई।

कोटे के संबंध में भी एक दिलचस्प घटना घटी। लालपत्ती देवी एक दिन सुबह के समय कोटेदार के यहाँ राशन लेने के लिए गईं और कोटेदार ने राशन देने से मना कर दिया। फिर वह काम करने गाँव से बाहर चली गयीं और शाम को पहुंची तब कोटेदार ने कहा कि दिन में ही स्टॉक खत्म हो गया और अब तो शाम भी हो गयी है। जब बैठक में नारीसंघ को पता चला कि उसको कोटेदार ने राशन नहीं दिया तब महिलाएं कोटेदार के यहाँ गयीं और उसको राशन देने की मांग करने लगीं, और महिलाओं ने बूधनपूर में उपजिलाधिकारी के यहाँ शिकायत करने की धमकी भी दी, कोटेदार भी संगठन को समझ गया था कि वे सिर्फ कहती ही नहीं अपितु करके भी दिखाती हैं। उसने लालपत्ती देवी के पति को राशन देने के लिए बुलवाया, राशन तो मिला और साथ में सलाह भी दी, कि “अब महिलाएं नेता बन गयी हैं! यह हमारे लिए एक समस्या है, कोई संदेह नहीं लेकिन सावधान रहना चाहिए, आपको तो खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप तो अधिक प्रभावित होंगे।”

नारीसंघ द्वारा स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी पहल की गयी। कुमारी देवी की बहू शारदा देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव कराने के लिए 820 रूपए नर्स को देना पड़ा। दो दिन बाद 30 नारीसंघ की महिलाएं स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंच कर स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत की। पूरी शिकायत सुनने के बाद वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उस नर्स की शिकायत की, परिणामस्वरूप उसने पैसे वापस करते हुए अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। इसके बाद बंसराजी देवी ने नर्स से कहा कि तुम लोग हमेशा यही करती हो जब कोई शिकायत करता है तो माफी मांग लेती हो, फिर उसी रास्ते पर चलने लगती हो। तब उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी से इस तरह के सेवादाताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का निर्णय ले जिससे कि इस तरह की समस्याओं को समाना आम जनता को न करना पड़े। अंत में चिकित्सा अधिकारी ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और महिलाएं अपने घर वापस आ गयीं।

स्पष्ट है कि जानकारी प्राप्त करने से महिलाओं के आत्मविश्वास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लक्षित होने लगा है। मुख्य रूप से प्रावधानों की जानकारी होने के कारण ही वे स्पष्ट रूप में अपनी मांग को उठाने में सक्षम हैं और कार्यवाही न होने की स्थिति में वे सभी दरवाजे खटखटाने का साहस रखती हैं जिनसे कि पहल हो सकती है।

11. अधिकार के खातिर सूचना

जानकारी का महत्व उनसे पूछिए जो इसे पाने में असमर्थ है। उन लोगों के लिए जानकारी बहुत अनमोल है। ये लोग सूचना और जानकारी को अपनी उपेक्षित स्थिति पर काबू पाने के लिए, एक तरीके के रूप में उपयोग करते हैं। कान्ती देवी बताती हैं कि कम से कम हम एक साथ आयेगे तो हमे थोड़ी और अधिक जानकारी हो जायेगी। अगर हमे जानकारी होगी तो हम अपना और अधिक सुधार करने के लिए सक्षम हो जायेगे, जब हमारा विकास होगा तो गाँव भी विकसित होगा। कान्ती देवी अम्बेडकर नगर जिले में भीटी ब्लाक के बाला पैकोली ग्राम पंचायत में नारी संघ की अध्यक्ष हैं। वह सचिव आरती देवी व कोषाध्यक्ष शान्ती देवी के साथ संगठन का नेतृत्व कर रही हैं।

इस नारीसंघ का गठन हाल ही में भीटी ब्लाक के ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के द्वारा जून 2011 में हुआ है। वर्तमान समय में संगठन में सदस्यों की कुल संख्या 167 है जो अपने स्वभाव से भी मजबूत है। इसीलिए, नारीसंघ के सदस्यों की एकता को देखकर इस ग्राम पंचायत के स्थानीय नेता डर गये, और उन्होंने इस संगठन के सदस्यों की सामूहिक भावना को निरूत्साहित करने का प्रयास किया। कान्ती देवी कहती हैं कि "गाँव के प्रधान ने हम महिलाओं को आगाह किया कि नारीसंघ की बैठक नहीं करे और यही चेतावनी उन्होंने हमारे परिवार के सदस्यों को भी दी, और कहा कि 'अगर इन महिलाओं ने नेता बनने की कोशिश की तो तुम लोगों को जो कुछ पहले से मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा।' नारीसंघ की कुछ सदस्य कहती हैं कि कोटेदार ने भी हमें प्रभावित करने की कोशिश किया। कोटेदार का कहना था कि अगर हम उसके खिलाफ शिकायत नहीं करेगें तो वह हमें सही राशन देते रहेगें।" लेकिन नारी संघ के सदस्यों ने अपने प्रयासों को निरन्तर जारी रखा है।



कान्ती देवी ने अपने संगठन की पहली सामूहिक सफलता के अनुभव के बारे में बताते हुए कहती हैं कि, "हम में से कई लोगों के पास जॉबकार्ड था, किन्तु काम कैसे मिलेगा यह पता नहीं था। नारीसंघ से जुड़ने के बाद हम सभी को लिखित काम का आवेदन करने की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद हम सभी काम की मांग हेतु लिखित आवेदन के साथ प्रधान से मिलने गये। लेकिन प्रधान ने आवेदन को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और 4-5 दिन में काम देने का वादा किया। किन्तु प्रधान के कहे अनुसार महिलाओं को काम नहीं मिला। इसीलिए, नारीसंघ की सदस्य फिर से लिखित आवेदन के साथ प्रधान के पास गईं और उसी समय उसे स्वीकृत कराया। यह नारीसंघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, अब इतना तो है कि काम ना दिये जाने की दशा में हम लोग बेरोजगारी भत्ते का दावा कर सकते हैं। नारीसंघ के 36 सदस्यों ने लिखित काम की मांग किया और उन्हीं के साथ 20 अन्य महिलाओं को भी मनरेगा में 8 दिन का काम प्राप्त हुआ। महिलाओं ने पहल करके कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाया।" इस सफलता से महिलाओं की एकता और अधिक मजबूत हो गई।

जून 2011 में इस गाँव के प्राथमिक विद्यालय पर जिला सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत आयोजित किया गया था। नारीसंघ के लगभग 300 सदस्यों ने इसमें भाग लिया और उन्होंने सिविल जज श्री राकेश कुमार के समक्ष मनरेगा से संबंधित समस्याओं को रखा।

मुख्य वक्ताओं में से श्री रण विजय ने मनरेगा के महत्व पर चर्चा करते हुए बताया कि गरीब परिवार के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर उनके पलायन के संकट को रोकना ही, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए उचित क्रियान्वयन और सम्मिलित प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। नारीसंघ की सदस्य रामकली, माया देवी ने

“समाज मे हम लोगो को लोग नेता कहने लगे है, किन्तु हम लोग अपनी कमियो को जानते है इसलिए आगे अभी और सीखने का प्रयास कर रहे है।”

अधिनियम का सही अर्थ बताते हुए इसके खराब क्रियान्वयन के बारे में बताया कि “पिछले वर्ष हम सभी को मनरेगा में केवल 16–20 दिन ही काम मिला। ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड व काम की मांग हेतु आवेदन देने के लिए प्रपत्र ही उपलब्ध नहीं रहता है।” न्यायाधीश ने मनरेगा ए० पी० ओ० से जवाब मांगा और साथ ही यह निर्देशित किया कि दो दिनों के अन्दर प्रावधानों की पूर्ति करना अनिवार्य है। नारीसंघ की एक अन्य अगुआ महिला कमरूल निशा देवी ने पी०डी०सी० से

सम्बन्धित शिकायत किया, इससे पहले भी यह शिकायत तहसील दिवस के अवसर पर रखा गया था। सिविल जज ने उस दिन कुल 254 शिकायत को सुना जिसमें इंदिरा आवास, आवास योजना, विधवा व विकलांग पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनियमितताओं और मनरेगा के अर्न्तगत काम की कमी जैसे समस्यायें थीं। न्यायाधीश ने महिलाओं को निर्देश दिया कि मनरेगा संबंधी समस्याओं के लिए लिखित शिकायत, संबन्धित अधिकारी के सामने अवश्य पेश करे। मनरेगा ए० पी० ओ० ने तुरंत घोषणा किया कि जिन लोगों को जॉबकार्ड चाहिए वे अगले दिन मेरे कार्यालय में मुझसे मिल सकते हैं।

इसी तरह के एक मामले में, वृद्धा पेंशन को पिछले ढाई सालो से रोक दिया गया था और इसे पुनः लोक अदालत के कारण बहाल किया गया। इस लोक अदालत का प्रभाव आसपास के ग्राम पंचायतों पर भी पडा और 19 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिला। लोक अदालत के बाद, एक सप्ताह के अन्दर लोगो ने काम की मांग किया और काम की मांग करने के तीन दिन बाद 90 महिलाओं को काम मिल गया और मजदूरी भी समय से भुगतान हो रहा है। लोक अदालत ने महिलाओं के पहल को मजबूत बनाने और प्रभावी ढंग से उनकी समस्याओं को हल करने में मदद किया है।

“अब हम सत्ता के किसी भी व्यक्ति से बात करने में संकोच नहीं करते हैं चाहे वह प्रधान, सिक्रेटरी, ब्लाक या जिला स्तर का अधिकारी ही क्यों ना हो। हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए ब्लाक या जिला स्तर पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।” यह कहना है उन महिलाओं का जिन्होंने नारी संघ के सदस्यों के अंशदान के माध्यम से आने जाने का खर्च उठाया।

लोगो ने पहले से ही हम महिलाओं को नेता के रूप में संबोधित करना शुरू कर दिया है लेकिन हम सभी अपनी सीमाओं के बारे में जागरूक हो गये हैं। हमको प्रशिक्षण एवं सामूहिक पहल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर इसी प्रकार हमारे सामूहिक प्रयास जारी रहे तो हम सभी हर क्षेत्र में प्रभावी हो जाएंगे।”

12. रानी दुर्गावती नारीसंघ

महरूआ गाँव की महिलाओं के जीवन में नारीसंघ के गठन के बाद से कई मायनों में बदलाव आया है। इस संगठन के माध्यम से महिलाओं को अपने छिपे अस्तित्व को बाहर निकालने का एक अवसर प्राप्त हुआ। वे प्रत्येक बैठक के साथ और अधिक जानकार हो रही हैं और प्रत्येक पहल के साथ इनमें और अधिक विश्वास बढ़ रहा है। इसके अलावा, सामूहिक क्षमता का अनुभव करने के बाद और अधिक महिलाएँ नारी संघ से जुड़ गयीं।

रानी दुर्गावती नारीसंघ का गठन अम्बेडकरनगर जिले के कटेहरी ब्लॉक के महरूआ ग्राम पंचायत में हुआ और इस संगठन के गठन में स्वविश्वास, अम्बेडकरनगर की संस्था द्वारा सहयोग किया गया था। सायरा देवी और प्रेमा देवी इस संगठन की अध्यक्ष व सचिव हैं। अब तक लगभग 154 महिलायें इस संगठन का हिस्सा बन चुकी हैं।

नारीसंघ की अध्यक्ष सायरा देवी को संगठन के शुरुआती दौर में आयी चुनौतियाँ याद हैं। वे बताती हैं कि, “मैं बैठक में भाग लेने के लिए उत्साहित रहती थी, किन्तु मेरे ससुराल के लोगों को मेरा बैठक में जाना पसंद नहीं था। हर बार बैठक से लौटने के बाद मेरी सास मुझे डाँटने लगती। परन्तु मुझे बैठक से बहुत सी जानकारी मिलती थी इसीलिए, उनके गुस्सा हाने के बावजूद भी मैं बैठक में जाती थी,” सायरा देवी याद करते हुए बताती हैं कि, बाद में मैंने परिवार के प्रतिरोधों पर काबू पाने के लिए एक बहुत ही रोचक रणनीति अपनाई। “एक बार मैं अपनी सास को भी बैठक में लेकर गई और उन्हें बैठक में हम लोगों की चर्चा पसंद आई।” अब मेरी सास नारीसंघ के कार्यों में रूचि लेती हैं, बैठक में आती हैं और अपनी बहू का पूरा समर्थन करती हैं।

जिस प्रकार सरकारी अधिकारी और प्रशासन के प्रतिरोध से निपटना आसान नहीं था, उसी प्रकार परिवार के सदस्यों के प्रतिरोध का सामना करना भी आसान नहीं था। प्रेमा देवी ने मनरेगा के अन्तर्गत काम पाने के लिए किए गये संघर्ष को याद करते हुए



पहले कोई सूचना एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए भी अधिकारियों की सिफारिश करनी पड़ती थी, किन्तु वर्तमान परिस्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

बताती है कि “ हममें से 16 सदस्य काम पाने हेतु लिखित आवेदन के साथ पंचायत कार्यालय गये , किन्तु पंचायत सचिव ने आवेदन को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। सचिव की बात सुनकर हम सभी सदस्य वही बैठ गये और कहा जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तब उसने हम सभी को दूसरे दिन आने के लिए कहा।” और जब महिलाये दूसरे दिन वहां पहुंची, तो पंचायत सचिव कार्यालय से गायब हो गया। तब महिलाओं ने कार्यालय के क्लर्क पर दबाव बनाया कि वो फोन करके सचिव को तुरंत बुलाए। अब सचिव लंबे समय तक महिलाओं का सामना करने से नहीं बच

सकते थे। प्रेमा देवी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वह हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं करते, तो हम सभी पूरी तैयारी के साथ ब्लाक कार्यालय में जाकर बी0डी0ओ0 का घेराव करेंगे। प्रेमा देवी का अनुभव है कि अधिकारों का एहसास करके ही हम अपने को स्थापित कर पाये हैं। उन्होंने उस जगह को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनका आवेदन औपचारिक रूप से ले नहीं लिया गया।

प्रेमा देवी और सायरा देवी ने नारीसंघ की शुरुआती दौर में घटित एक सीखपूर्ण घटना के बारे बताते हुए कहते हैं कि जब महिलाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों के बारे में जानकारी हुई तो उन्हें अपने कोटेदार के द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार का एहसास हुआ कि वह कैसे लोगों के अधिकारों का हनन करके उनके हिस्से का राशन हडप रहा है।” प्रत्येक कार्ड धारक को 35 किलोग्राम राशन प्रति महीने मिलना चाहिए, किन्तु हमारा कोटेदार हमें केवल 28 किलोग्राम ही देता था। जब तक उचित मात्रा में राशन नहीं मिलेगा तब तक हमने राशन लेने से इन्कार कर दिया और फोन द्वारा एस0डी0एम0 को सूचित किया। हमारी शिकायत के जबाब में एस0डी0एम0 अगले दिन गाँव में पहुँच कर स्थिति की छानबीन किया और कोटेदार के खिलाफ शिकायत सही पाये जाने पर उन्होंने कोटेदार को मानक के अनुसार सही मात्रा में राशन वितरित करने की चेतावनी दी।” महिलाओं को इसके बाद के परिणाम के बारे में पता नहीं था। असली मुसीबत की शुरुआत तो एस0डी0एम के वापस जाने के बाद हुआ। कोटेदार ने महिलाओं को धमकी दी एवं उनकी सामूहिक भावना को तोड़ने में सफल हो गया। महिला अगुआ ने बताया कि “इससे पहले ना तो हम संगठित थे और ना ही सामूहिक रूप से मजबूत थे, इसीलिए कोटेदार सफल हो गया हांलाकि वह हमारे मकसद को तोड़ने में विफल रहा।” यद्यपि उनका प्रयास बेकार नहीं गया। महिलाओं के आशा के अनुरूप ,स्थानीय स्तर पर यह ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुआ परन्तु आस-पास के सात गाँवों में, इस गाँव की घटना की जानकारी होने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति में सुधार हुआ। यहां तक कि अपने गाँव के कोटेदार से ही यह संदेश मिला।

“पहले सूचना लेना बहुत ‘मंहगा’ था। कार्यालयों में लोगों के हाथ में पैसे दिये बिना सूचना मिलना असम्भव था। आज स्थिति काफी हद तक बदल गयी है।” इसका अर्थ है कि महिलाओं को जानकारी लेने के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। परन्तु अब भी उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ता है। स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उन्हें धमकी दी जाती है और दबाव भी बनाया जाता है, विशेषकर तब जब वे सूचना के अधिकार के अर्न्तगत सूचना माँगती हैं। लेकिन अब वे संगठित हो गयी और इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं।

13. जय मां शक्ति नारी महासंघ

नारीसंघ ग्रामपंचायत स्तर पर का संगठन है, जबकि नारी महासंघ ब्लाकस्तर पर प्रत्येक नारीसंघ की नेतृत्वकारी महिलाओं का ब्लाक स्तरीय संगठन है।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नारी महासंघ का गठन एक महत्वपूर्ण प्रगति है और साथ ही इसके प्रभाव को भी समझने की आवश्यकता है। हालांकि नारीसंघ ग्रामपंचायत स्तर पर सक्रिय एवं जीवंत है, किन्तु सभी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर अर्थात् ग्रामपंचायत पर करना सम्भव नहीं है। इसके अलावा जब तक स्थानीय नेताओं को लगता है कि ऊपर तक पहुंच नहीं है तब तक वे उत्तरदायित्व नहीं निभाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में नारी महासंघ के गठन का विचार बहुत ही प्रभावी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होता है क्योंकि इससे महिलाओं की ब्लाक स्तर तक सामूहिक पहचान बनने के साथ ही, महिलाएं अपने गाँव से बाहर जाने में भी सक्षम हो जाती हैं।

नारीमहासंघ की सोच बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह महिलाओं को सामूहिक पहचान प्राप्त करने के साथ ही गाँव से बाहर निकल कर मुद्दों पर सोचने एवं पहल करने में सक्षम बनाता है।

संक्षेप में नारी महासंघ पैरवी करने के लिए महत्वपूर्ण चरण है। यह समूह महिलाओं को उनके मुद्दे ब्लाक एवं जिले पर ले जाने में मदद करता है। बहने अनेक गाँवों की होने के बावजूद भी, सामूहिक सहयोग की भावना के साथ प्रभावी प्रयास करके कार्य करने में सक्षम है।

जय मां शक्ति नारी महासंघ ऐसा एक सामूहिक मंच है, जिसमें कि वाराणसी जिले की आराजी लाइन ब्लाक के 30 ग्रामपंचायतों के नारीसंघ की 167 महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं। महिला स्वरोजगार समिति के सहयोग से वर्ष 2009 में सीता देवी, निर्मला देवी और ललिता देवी के नेतृत्व में नारी महासंघ का गठन किया गया।

जिन मुद्दों पर ग्रामपंचायत स्तरीय नारीसंघ की बैठक में पहल नहीं हो पाती है अथवा पहल प्रभावी नहीं होती, तब उन मुद्दों पर महासंघ की बैठक में चर्चा की जाती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया दोनों ही स्तरों पर समान होती है। मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने के उपरांत ही रणनीति का निर्धारण किया जाता है। "अब हम लोग सब जानने लगे हैं, नियम-कानून भी जानने लगे हैं, यह भी की

कब और कैसे करना है, और कौन जिम्मेदार व्यक्ति है यह भी जानने लगे हैं, अतः अब हम लोग जिम्मेदार व्यक्तियों को उनकी कार्य एवं जिम्मेदारी के प्रति जबाबदेही सुनिश्चित कराने का भी प्रयास करने लगे हैं। हम लोग संगठित हो करके साक्ष्यों के साथ जाते थे और यह प्रभावी भी रहा है।" महासंघ की नेतृत्वकर्ता कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रूप में क्रियान्वित भी कर रही हैं।



हांलाकि नारीसंघ संघर्षशील ही रहती है किन्तु कभी कभी यह प्रभावी नहीं हो पाता। काम के संबंध में नारीसंघ सरकारी अधिकारियों, निर्वाचित व्यक्तियों और मीडिया के साथ भी समय समय पर वार्ता कर उनका सहयोग प्राप्त करती है। सामूहिक मांग की पहल के

अतिरिक्त, नारीमहासंघ संस्था के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर पैरवी के मुद्दों की भी पहल करती है। ऐसा ही एक कार्यक्रम 12 मई 2011 को जिला मुख्यालय पर सरकारी अधिकारियों एवं मीडिया पर "नारीमहासंघ की ब्लाकस्तरीय अधिकारियों एवं मीडिया के साथ समन्वय बैठक" का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहे किन्तु प्रतिनिधि के रूप में जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी ने प्रतिभाग किया। लगभग 100 महिलाओं ने प्रतिभाग करके

अपने अनुभव बतायीं एवं साथ ही सरकारी अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी महिलाओं की बातों तथा अधिकारियों के अनुभव के साथ कार्यक्रम को स्थान दिया।

इस कार्यक्रम के आयोजन के परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ। एक सप्ताह के भीतर ही जिलाधिकारी ने नारी महासंघ की नेतृत्वकर्ता को बात करने के लिए कार्यालय बुलाया एवं ज्ञापन पर चर्चा करते हुए कहा "दस्तावेज को देखने से पता चला कि आप लोगों की ग्रामसभा एवं मनरेगा से संबंधित मांगें पूरी हो चुकी हैं।" किन्तु यह सही नहीं है, यह सिर्फ कागज पर ही हुआ है।" उसने आरोप लगाते हुए पूछा कि "यदि



वास्तव में यह हुई होती तो हम लोग क्यों मांग करते?" और चर्चा के बाद जिलाधिकारी महिलाओं की बात पर विचार करने के लिए तैयार हुए। ग्रामपंचायत स्तर पर योजनाओं जैसे पी0डी0एस0, मनरेगा एवं ग्रामसभा तथा अन्य योजनाओं जैसे वृद्धा पेंशन एवं इन्दिरा आवास के क्रियान्वयन की जांच करायी गयी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविकता निकल कर सबके सामने आ गयी।

अंत में जिलाधिकारी को महासंघ की मांगों पर यकीन हुआ और अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए कदम भी उठाए गए। उन्होंने महिलाओं का समर्थन कर आश्वासित करते हुए कहा "आप लोग कभी भी आ करके मुझसे मिल सकती हैं।" जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद से ही क्रियान्वयन में गतिशीलता आ गयी। ग्रामसभा आयोजन का नियोजन, मनरेगा में पर्सपेक्टिव प्लान बनने लगी और राशन वितरण में भी सुधार हुआ। इस प्रकार से महासंघ की पहल के परिणामस्वरूप सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी मदद मिली।

14. क्रान्ति नारीमहासंघ

ग्रामीण विकास सेवा संस्थान के द्वारा 2007 में प्रतापगढ़ जिले के मंगरौरा ब्लाक में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भिक वर्ष में 10 ग्रामपंचायतों से प्रारम्भ हो कर वर्तमान में 40 में कार्य का विस्तार हुआ है। महासंघ के गठन की प्रक्रिया का प्रारम्भ वर्ष 2010 में प्रत्येक 20 ग्रामपंचायतों की 2-2 अगुआ महिलाओं के साथ क्रान्ति नारीमहासंघ का गठन हुआ और वर्तमान में 40 ग्रामपंचायतों की अगुआ महासंघ में संगठित हैं। वर्तमान में 80 अगुआ बहने महासंघ की त्रैमासिक बैठक का आयोजन करती हैं। 6 सदस्यीय टीम क्रान्ति नारी महासंघ को ब्लाक स्तर पर प्रस्तुत करती हैं, जिसकी अध्यक्ष राजकुमारी एवं नीलम देवी, बड़का देवी, सुशीला देवी, सरवरी बेगम, संजू देवी का क्षमतावर्धन करके मुद्दों पर समय समय पर पैरवी करती हैं।

नारी महासंघ के द्वारा मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर उचित पहल के लिए ब्लाक से ले करके जिलाधिकारी के समक्ष मुद्दों को रखती हैं। जब महिलाएं काम का लिखित आवेदन ले करके प्रधान के पास जाती हैं तब प्रधान रिसीविंग देने से मना कर देते हैं और इसके लिए यही जिम्मेदार होते हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं विकल्प के रूप में ब्लाक पर जा करके रिसीविंग कराती हैं और इस मुद्दे पर भी महासंघ द्वारा पहल की जाती है।

सितम्बर 2011 में नारीमहासंघ के द्वारा 4 ग्रामपंचायतों की सदस्यों को जब 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तब महिलाओं ने बेरोजगारी भत्ते का आवेदन किया परिणामस्वरूप महिलाओं को 3 दिन के अंदर ही काम मिला।

सरकारी तंत्र को उत्तरदायी बनाने में अनेक समस्याएं आती हैं, इसलिए महिलाओं के अथक प्रयास के बाद भी कुछ मुद्दों पर ही सफलता प्राप्त हो सकी है, लेकिन इन प्रयासों से उनको पहचान एवं स्थान भी मिला।

अनेक गांवों जैसे नरहरपुरम वैसवारा, शंकरपुर, सरसीडीहा आदि में नारीमहासंघ के निरंतर प्रयास के परिणामस्वरूप ही वितरण की दशा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

“मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए महिलाएं ही नेतृत्व कर रही हैं, पुरुषों की अपेक्षा में अधिक संख्या में महिलाएं यहां पर जॉबकार्ड बनवा करके काम भी प्राप्त कर रही हैं।”



ग्रामसभा का आयोजन अधिकतर स्थानों पर कागजों में ही होता था। नारी महासंघ के द्वारा प्रत्येक ग्रामपंचायतों में वर्ष 2010 में आयोजित ग्रामसभाओं का विस्तृत ब्यौरा आरटीआई द्वारा डीपीआर से मांगा गया।

महासंघ ने सभी ग्रामपंचायतों के सदस्यों से समस्याओं पर पहल करने के आर टी आई एवं हेल्पलाइन का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। यदि सूचना नहीं प्राप्त हो पाती तो उस स्थिति में अन्य प्रकार से पहल करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि अभी तक 500 आरटीआई एवं 2000 बार मनरेगा एवं पीडीएस हेल्पलाइन का प्रयोग नारीसंघों द्वारा किया जा चुका है। इन मुद्दों पर भी बैठकों में चर्चा की जाती रहती है।

महिलाएं अनेक कठिनाइयों एवं समस्याओं के बाद भी विकास कार्यों के प्रति समर्पित हैं। उनकी लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता का परीक्षण अनेक अवसरों पर महसूस किया गया। जैसे कि जब बड़का देवी के द्वारा सल्लाहीपुर की कोटे में अनियमितता का मुद्दा उठाया, तब कोटदार ने अधिक मात्रा में चीनी ले करके इस मुद्दे को न उठाने का प्रयास किया, किन्तु उन्होंने इन्कार करते हुए सभी का उचित मात्रा में वितरण करने की बात पर डटी रही।

हमने वह प्राप्त कर लिया है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था।” मनरेगा के क्रियान्वयन में महिलाएं ही अगुआई कर रही हैं। पुरुषों से भी अधिक महिलाओं ने जाबकार्ड बनवा करके मनरेगा में काम कर संबंधित हक को प्राप्त किया है। हम लोगों ने पहले कभी अपने गांव के बारे में इस तरह से सोचा ही नहीं था, अब हम लोग ग्रामसभा का आयोजन कागजों से बाहर वास्तविकता में आयोजित कराने की मांग करते हैं। विकास के प्रति समर्पित सेवादाताओं के साथ विकास हम भी गाँव के विकास कार्यों में भागीदारी करना चाहते हैं।”

नारीसंघ जब सरकारी कार्यालयों में जाती है तब अधिकारी नाराज होते हैं। महिलाएं बताती हैं कि “हम लोग आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम हमारे हक प्राप्त करना चाहते हैं।” इसी तरह से अपने विचार निर्वाचित प्रतिनिधियों के समक्ष भी रखती हैं।

भौसहिया गांव की 45 महिलाएं ने काम की मांग की किन्तु 20 दिनों तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। इसी दौरान बरसाय एवं सल्लाहीपुर के लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अतः लगभग 70 महिलाएं संगठित हो बेरोजगारी भत्ते की मांग करने बीडीओ कार्यालय पहुँची। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि “यदि काम नहीं दे सकते हैं तो भत्ता दीजिए।” कुपित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 3 दिन के अंदर काम देने का आश्वासन दिया। इस समयावधि में सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर 40 मजदूरों को काम मिला। कार्यस्थल पर दो पुरुषों को छोड़ कर सभी महिलाओं को ही काम मिला।

नारीसंघ एवं महासंघ के गठन से महिलाओं के नेतृत्व प्रदर्शन का एक साझा मंच प्राप्त हुआ है। महासंघ की नेतृत्वकारी सदस्य एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में भ्रमण कर नारीसंघ की बैठकों में प्रतिभाग करके नेतृत्वक्षमता का विकास करती हैं। अन्य गांवों की सदस्यों के साथ भी वे अपनत्व महसूस करने लगी हैं।

15. सामूहिक प्रयास

अम्बेडकरनगर जिले के जलालपुर ब्लाक के 20 ग्रामपंचायतो के 56 गांवों से 258 महिला अगुआ हैं। सभी नारीसंघ की 2571 सदस्यो ने सदस्यता ग्रहण की।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही जन शिक्षण केन्द्र ने नारीसंघ के गठन के प्रारंभ में ही विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करके उसमें नरेगा एवं पीडीएस से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के परिणामस्वरूप महिलाएं जागरूक हुईं। एक बार जब महिलाओं को आभास हुआ कि इन नियमों से उनको सहायता मिल सकती है, तब महिलाएं संगठित होना प्रारंभ हो गयी। नारी महासंघ की अध्यक्ष किसमती देवी बताती हैं "हम लोग किरन दीदी की बातों से प्रभावित हो कर मई 2010 में नारीसंघ के गठन की प्रक्रिया का प्रारंभ कर सितम्बर 2010 में गठन हुआ और हाथ उपर उठा करके सभी ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने की शपथ भी ली।"



किसमती देवी कहती हैं "हांलाकि हम ही लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं, हम लोग सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। रणनीति के आधार पर मुद्दों पर पहल करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग पहल करते हैं, उनको निशाना भी बनाया जाता है। जिन लोगों ने आरटीआई डाली और लिखित आवेदन के माध्यम से काम की मांग की एवं पीडीएस के मुद्दों पर आवाज उठायी, उन लोगों को लाभ प्राप्त करने में समस्याओं का समाधान भी करना पडा। किन्तु इस तरह की बातों पर ध्यान न दे कर हम लोग संगठन में विश्वास करते हैं।

मई 2011 में महासंघ ने आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया। 257 महिलाओं ने अलग अलग आवेदन से राशनकार्ड, राशन वितरण एवं 18 ग्रामपंचायतों में 20 राशन की दुकानों का निरीक्षण करने के संबंध में था जिससे वे अपने राशन प्राप्त करने के इरादे में सफलता प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत 18 राशन की दुकानों की समस्या का समाधान करने के लिए निरीक्षण किया। जब भी महिलाओं ने स्थानीय स्तर पर शिकायत की, तब उनको चुप कराने के लिए धमकियां भी मिली किन्तु आरटीआई डालने पर तो और भी धमकियां मिली। महासंघ की अगुआ किसमती, सुनीता, संगीता ने स्थानीय स्तर पर सहयोग के लिए प्रत्येक गाँवों में जाकर लोगों को प्रोत्साहित किया। महिलाओं में एकता, नियमों के बारे में जानकारी एवं मुद्दों को कोर्ट तक ले जाने की बातों से दबाव बन पा रहा है।

"हम संगठन की शक्ति में विश्वास करते हैं, अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। रणनीति आधारित मुद्दों पर संगठित पहल करते हैं।"

आवेदन डालने के पहले ही महिलाओं को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी थी, अतः महिलाओं ने गाँव से ले कर पंचायत स्तर तक की सूचनाएं मांगी और इस अभियान को धवरूआ और मालीपुर के प्रधानों ने भी समर्थन एवं सहयोग किया और आवेदन पोस्ट किए। नेतृत्वकारी महिलाओं का एक समूह वरिष्ठ डिवीजनल सिविल न्यायाधीश से मिल कर उनको पहल के बारे में सूचित किया। महिलाओं ने आरटीआई का उत्तर न मिलने के संदर्भ में लिखित ज्ञापन भी दिया और जब कोटेदारों को नोटिस मिला तब नारीसंघ का उत्साह बढ़ गया।

आवेग में आ करके महिलाओं के सभी आवेदनों पर कार्यवाही न होना पर आवाज भी उठायी। सभी पर पहल होने पर महिलाओं पर प्रधान एवं कोटेदार का दबाव भी पड़ने लगा। कुछ कोटेदार ने नारीसंघ से बात करके समस्याओं का समाधान करने के लिए नारीसंघ से बात भी की। कोटेदारों की उचित प्रतिक्रिया मिलने पर महिलाओं ने शीघ्र कोई कार्यवाही न करने का निर्णय लिया।

"पहले सब भगवान भरोसे था, अब महासंघ अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे हैं।" किसमती देवी कहती हैं, "यदि हम लोग अकेले प्रयास करते तो सफल नहीं होते किन्तु संगठित होने से पहल का प्रभाव दिखने लगा है, किन्तु अभी महिलाओं को अधिकारों को प्राप्त करने एवं स्वतंत्र होना सफर लम्बा है लेकिन अब महिलाएं समझ गयी हैं कि कुछ भी असम्भव नहीं है।"

16. सम्मानजनक जीवन के लिए प्रयास

पचास वर्षीय कैलाशी देवी मदनपट्टी ग्राम पंचायत की रानी लक्ष्मीबाई नारी संघ की अगुआ महिला है ,जिसका गठन मार्च 2008 में किया और इसमें 181 महिलायें सदस्य के रूप में जुड़ी है। इसकी गठन की प्रक्रिया में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा सहयोग किया गया था।

कैलाशी देवी स्वयं को साबित करने वाली एक महिला अगुआ है जो फूलन देवी नारी महा संघ की अध्यक्ष है और जिला स्तरीय पैरोकारी समूह की सदस्य भी है।

मुश्किल से 13 वर्ष की उम्र से ही कैलाशी देवी के कंधों पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। अपने कठिनाइयों के बारे में बताते हुए वह कहती है कि उनके पति मानसिक रूप बीमार थे ,उनके सास-ससुर ने युवा दंपति से कहा कि उनके घर से दूर होजाये और अपने दम पर जीने के लिए कहा। तब से वह भी अकेले अपने दम पर अपने परिवार को व्यवस्थित रूप से चला रही है।

अपने गाँव की स्थिति बताते हुए कैलाशी देवी कहती है कि महिलाओं को उचित काम मिल पाना मुश्किल था। उनको मजदूरों के रूप में प्राथमिकता नहीं दी जाती थी और जब कभी काम पर रखा जाता था तो कम भुगतान किया जाता था।

“जब भी महिलायें प्रधान का दरवाजा खटखटाती तो वह जल्दी काम शुरू करने का वादा करता लेकिन कभी काम शुरू नहीं करता था। महिलाओं को उसके शब्दों पर विश्वास था और काम के लिए इन्तजार करना पड़ता था। कभी-कभी एक या दो दिन के लिए काम मिल जाता था और बीच में ही बंद कर दिया जाता था ,” नारी संघ के गठन के पहले यही स्थिति थी। जब महिलाओं को एहसास हुआ तो उन्होंने काम के लिए लिखित



आवेदन जमा किया ,उन्हें यह भी एहसास हुआ कि प्रधान उनसे झूठ बोल रहा था। पहले 3 पुरुष और 10 महिलाओं ने लिखित आवेदन दिया और उसके बाद 51 महिलाओं ने अपना काम का आवेदन प्रस्तुत किया , दोनों आवेदनों को रोजगार सेवक ने रिसेव किया। 6 दिन के अन्दर उन्हें सूचना मिली की काम शुरू हो गया है। लगभग 150 से 175 लोगों को चार दिन का काम मिला। काम सुनिश्चित करने की इस प्रक्रिया को देखकर प्रधान परेशान हो गया और उसने नारी संघ की महिलाओं व संस्था के कार्यकर्ताओं को धमकी दिया।

कैलाशी देवी ने नारी संघ के काम को आवश्यक समझ कर चुनौती के रूप में अपनाया। इस प्रक्रिया में वह एक साधारण दबू महिला से एक मुखर अगुआ के रूप में बदल गयी। वह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए कहती है कि “ मैं एक अगुआ के रूप में कब परिवर्तित हो गयी इसका मुझे एहसास ही नहीं हुआ।” सामूहिक कार्यों में अगुवाई करने के लिए अपने अन्दर नेतृत्व क्षमता को एहसास करते हुए कहती है कि ,“यह सच है कि मैंने अगुवाई की है और सामूहिक रूप से हम बहुत सी चीजों को हासिल किया है।

हमने उचित राशन वितरण के लिए संघर्ष किया है, ग्राम सभा की खुली बैठक में पंचायत सचिव का सामना किया है और काम की मांग को लेकर जिला कलेक्टर तक भी गये हैं और हम अपनी सभी मांगों को पूरा करने में सफल भी हुए। जब मैंने इस प्रकार के पहल को करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी लिया तो मेरे अन्दर नेतृत्व के गुणों का भी विकास हुआ।”

इस गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण प्रक्रिया समस्याओं से भरी हुयी थी। लोगों को उचित मात्रा में राशन नहीं मिलता था, विशेष रूप से मिट्टी का तेल तीन महीने से नहीं मिल रहा था। नारी संघ की बैठक में इस समस्या पर विचार विमर्श किया गया। लेकिन महिलायें पहल करने के लिए तैयार नहीं थी। कैलाशी देवी ने इस समस्या पर पहल करने के लिए अगुवाई किया और महिलाओं से संगठित होकर कोटेदार का सामना करने के लिए अपील किया। महिलाओं के एक समूह ने, प्रति कोटा नियमित मिट्टी के तेल के आपूर्ति बारे में पूछने के लिए कोटेदार से मुलाकात किया। कोटेदार गुस्से में आकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनके डिब्बे को फेंक दिया। उसने

“समुदाय के लोगो ने महसूस किया कि नारीसंघ के द्वारा की जाने पहल से प्राप्त सफलताओ से सिर्फ महिलाओ का ही लाभ नही होता, अपितु अपरोक्ष रूप से पूरा समाज ही लाभान्वित हो रहा है।”

लगभग शारीरिक रूप से एक महिला पर हमला किया। कैलाशी देवी ने इस मामले में हस्ताक्षेप किया और उसे चेतावनी दिया कि अगर वह अपना दुर्व्यवहार जारी रखेगा तो उनके शिकायत के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। कोटेदार ने एहसास किया कि उनको धोखाधड़ी से दूर करना आसान नहीं है क्योंकि महिलायें संगठित हैं और अच्छी तरह से जानकारी भी ले रही हैं। उसने उचित ढंग से राशन वितरित किया। अब जब कभी महिलाये मांग करती तो वह ठीक से व्यवहार करता लेकिन जो महिलाये जागरूक नहीं थी उनको बहकाता था। वहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज में कई अनियमितायें हैं जिसको महिलाये साफ करना चाहती हैं।

शुरुआत में महिलाओं द्वारा स्थिति को बदलने के लिए किये जाने वाले प्रयास के प्रति समाज का दृष्टिकोण नकारात्मक था। लोग टिप्पणी करते थे कि, “पुरुष बदलाव लाने की कोशिश कर चुके अब महिलाये उनके जैसा प्रयास कर रही हैं, लेकिन यह असंभव प्रयास है।” लेकिन अब समुदाय को महिलाओं के क्षमता का एहसास हो गया था। वे देखते थे कि महिलायें ब्लाक व जिला स्तर के अधिकारियों से अपने समास्याओं के समाधान के लिए मिल रही हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यहसास हो गया था, महिलाओं का पहल केवल महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है बल्कि उससे पूरा समुदाय लाभान्वित होगा। यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को भी समझ आ गया था कि यदि उन्हें रोकना चाहे तो भी महिलाये नहीं सुनेगी। इसलिए महिलाओं का समर्थन करना ही उनके हित में है।

कैलाशी देवी कहती हैं कि “ मैं एक महिला अगुआ हूँ और सरकारी अधिकारी हमारी सेवा के लिए हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वे गैर जिम्मेदारना हरकत करते हैं जबकि ये जागरूक और सक्षम हैं।” वह गर्व महसूस करती है कि वह सत्ता में बैठे लोगों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने में सक्षम है।

भोजन के अधिकार और काम के अधिकार पर जोर देने के अलावा महिलाओं को गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि महिलाओं का शोषण नहीं करना चाहिए और गरीब और सामाजिक दृष्टिकोण से हाशिए पर रहने वाली महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। उनके मन में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण है।

17. आम संसाधनो तक पहुँच सुनिश्चित

रासलपारा नारी संघ, अम्बेडकर नगर जिले में, कटेहरी ब्लाक के रासलपार ग्राम पंचायत में अपने क्रेडिट से उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त किया है। इस संगठन का गठन 189 सदस्यों के साथ मार्च 2008 में, लोक जागृति संस्थान के सहयोग से किया गया और इस नारी संघ के लोगों ने सफलतापूर्वक गाँव के तालाब के उपयोग लिए पहुँच सुरक्षित किया है।

संगठन की कोषाध्यक्ष प्रभावती देवी जिनकी उम्र 35 वर्ष है, गर्व के साथ अपने नारी संघ के उपलब्धि बताती है। “हमारे गाँव में एक तालाब है जिसका उपयोग मछली पालन के लिए किया जाता है। लेकिन कई सालों से इस तालाब पर गाँव एक प्रभावशाली व्यक्ति का कब्जा था और कोई अन्य इसका उपयोग नहीं कर पाता था। हाल ही में मेरे पड़ोस के कुछ बच्चे तालाब में मछली पकड़ने के लिए गये थे तब दंबंग व्यक्ति द्वारा उन बच्चों की बुरी तरह से पिटाई की गयी। मैंने सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। वह कैसे समुदाय के संसाधन का उपयोग निजी सम्पत्ति के रूप में कर सकता है? यह एक आम संसाधन है और कोई समान रूप से इसका उपयोग कर सकता है। उसे किसी को भी रोकने या परेशान करने



का कोई अधिकार नहीं है।” इस सोच के साथ प्रभावती देवी ने संगठन के सदस्यों के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया। प्रभावशाली व्यक्ति ने गाँव वालों का अपने खिलाफ खड़ा होते देख, अपना रुख नरम रखते हुए सबको यह विश्वास दिलाया कि तालाब पर अब सबका बराबर का अधिकार होगा। लेकिन वह प्रभावती देवी को अपने पक्ष में करने के लिए पैसे का प्रलोभन देना चाहा, लेकिन वह उनका मनोबल तोड़ने में सफल नहीं हो पाया। अंततः गाँव के सभी परिवारों का तालाब पर पहुँच सुनिश्चित हुआ। इस प्रकार प्रभावती देवी ने गाँव के आम संसाधनों का गबन करने वालों को एक चुनौती दिया और यह भी सुनिश्चित किया कि अब इस तरह के संसाधनों पर सभी लोगों का बराबर का अधिकार होगा। नारी संघ की महिलाओं ने सामूहिक रूप से इसमें मछली पालन करने लगे। दंबंग व्यक्ति कभी-कभी उन्हें धमकी देने की कोशिश करता रहता है लेकिन अब ये लोग जबाव देना सीख गये हैं।

“सार्वजनिक संसाधनो पर समाज के प्रभावी लोगो के अधिकार को नारीसंघ ने चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संसाधनो पर सभी पर सभी को अधिकार प्राप्त हुआ।”

प्रभावती देवी अपने सफलता का श्रेय नारी संघ को देते हुए कहती है कि “इस संगठन से हमारे जीवन में बदलाव हुआ। जहाँ महिलायें पहले अपने परिवार में भी बात करने से डरती थी वही अब पूरे विश्वास के साथ सरकारी अधिकारियों के सामने भी अपनी बात रखने लगी है। अब ये लोग स्वयं दावा करके अपने अधिकारों की रक्षा करना सीख गयी है।”

प्रभावती देवी जैसी महिलाए अब जानकार हो गयी है। काम के अधिकार के अंतर्गत काम प्राप्त करने से ले करके ग्रामसभा की बैठको मे मुद्दो पर चर्चा एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया मे प्रतिभाग करने के लिए भी उत्साहित है।

महिलाएं अपनी मांगो को उठाने के साथ ही अन्य कार्यवाहियो मे भी योगदान दे रही है। अब वे लोग एक भी ग्रामसभा की बैठक को कभी भी छोडना नही चाहती है। मार्च 2011 मे महिलाओं को ग्रामसभा के बारे मे तब सूचना मिली जब वे काम करने के लिए जा रही थी। किन्तु जैसे ही बैठक पता चला महिलाए वापस बैठक मे प्रतिभाग करने के लिए आ गयी। प्रधान उन लोगो को देख करके अचंभित रह गया जब उसको पता चला कि महिलाए काम छोड़ करके बैठक के लिए आ रही है। महिलाओं ने कहा कि हम लोग बैठक मे प्रतिभाग करने के लिए एक दिन की मजदूरी संतोष करने को तैयार है, क्योंकि अब वे ग्रामसभा के महत्व से भलीभांति परिचित है।

नारीसंघ नेतृत्वकर्ताओं की कहानियाँ

1. आत्मशक्ति का एहसास

प्रतापगढ़ जिले के मंगरौरा ब्लाक में सकरा गाँव की नीलम देवी, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से विकसित महिला अगुवाओं के बीच में शायद सबसे कम उम्र और सबसे अधिक शिक्षित महिला अगुआ हैं।

वह 28 साल की विवाहित महिला है और उनके पास एक बेटा भी है। उनके पति स्नातक है और एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नीलम देवी स्वयं भी जुनियर हाई स्कूल तक पढ़ी लिखी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की तुलना में, जहाँ हर दस महिलाओं में से चार महिला अनपढ़ हैं, उनका शैक्षिक स्तर काफी अच्छा है।

नीलम देवी एक संवेदनशील महिला हैं और सामाजिक भेदभाव के मुद्दे हमेशा उनके दिल को छूते रहे हैं। लेकिन इससे पहले वह इस बारे में कुछ करने के लिए अपने आपको असहाय महसूस करती थी। वह ताजा घटना याद करते हुए बताती हैं कि कैसे उनके गाँव के जमींदार उनके समुदाय के लोगों को अपने खेतों में काम करने के लिए मजबूर करते थे और मजदूरी के लिए भी परेशान करते थे। “मैं इस

स्थिति के लिए स्वयं को दुखी महसूस करती थी लेकिन अधिकतर लोग भूमिहीन हैं और उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। वह अपने गाँव की महिलाओं के स्थिति के बारे में भी उतनी ही चिंतित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्तर पर लैंगिक विभाजन अधिक प्रमुख है। नारी संघ के गठन के पहले की स्थिति बताते हुए नीलम देवी कहती हैं कि, “महिलाओं के लिए उनका घर ही उनकी दुनिया होती है। उनसे घर के चारदीवारी के भीतर ही रहने और गाँव के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की उम्मीद की जाती है। हमने कभी इस तरह की रिवाजों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं किया और किसी ने कभी भी हमें नहीं बताया कि हमारे अधिकार क्या हैं।

जब से नारी संघ की गठन की प्रक्रिया आरम्भ हुई थी तभी से स्थिति में बदलाव शुरू हो गया। शुरुआत के बैठकों में संस्था के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं एक साथ आने की जरूरत पर जोर दिया। “उन्होंने हमें बताया कि हमें घरेलू कामकाज से बाहर निकल

भोजन और काम हमारी मुख्य चिंता है। जब आपका पेट खाली हो तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं कर सकते हैं।

— नीलम देवी,
अध्यक्ष, आजाद नारीसंघ

कर सोचना चाहिए और यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे आस-पास क्या चल रहा है,” नीलम देवी याद करके जोड़ते हुए कहती हैं कि, “इस तरह के बातचीत के माध्यम से महिलाओं ने अपने अन्दर की शक्ति को महसूस किया और यह भी एहसास किया कि हम एक साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं और बहुत सुधार हो सकता है।” अधिकतर गरीब, अनुसूचित जाति, मजदूरी करने वाली महिलाओं ने मिलकर पंचायत स्तर पर जून 2010 में आजाद नारी संघ का गठन किया गया।

सकरा गाँव की महिलायें एकमत होकर नीलम देवी को अपने संगठन के अध्यक्ष के रूप में चयन किया। वह अपने नारी संघ का नेतृत्व कर रही हैं जिसमें कुल 112 महिलायें सदस्य के रूप में जुड़ी हैं। नीलम देवी को गर्व है लेकिन अपने नव अर्जित स्थिति के बारे में विनम्र हैं। अपने स्वयं के शब्दों में नीलम देवी मानना है कि, “मैं एक साधारण महिला थी, बमुश्किल मुझे अपने घर की चारदीवारी से बाहर के दुनिया के बारे में कुछ भी पता होता था।” लेकिन अब वह बदल गयी है और आम महिलाओं के बीच में असाधारण काम करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आत्मविश्वास से लबरेज और सकारात्मक सोच की नीलम देवी अपने इस बदलाव का श्रेय महिलाओं के संगठन को देती हैं।



नारी संघ के सदस्यों की समझ विकसित करने और पहल करने के लिए प्रेरित करने में सूचनाओं का आदान प्रदान और प्रशिक्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीलम देवी का मानना है कि मासिक बैठक के माध्यम से नियमित बातचीत और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से महिलायें पहल करने में सक्षम हुई हैं और उनके गाँव की स्थिति में भी सुधार हुआ है।

आजाद नारीसंघ का सबसे पहला पहल गाँव के स्कूल से संबन्धित है। नीलम देवी को आज भी अपनी पहली सफलता याद है। 'मिड डे मिल का खराब क्रियान्वयन और शिक्षकों की अनियमित उपास्थिति जैसी कई समस्यायें थी। एक दिन नारीसंघ के सदस्यों का एक समूह प्रधानाध्यापक से मुलाकात किया और समस्याओं पर चर्चा किया। शुरुआत में शिक्षकों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया और महिलाओं के सुझाव को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन नारी संघ के सदस्य निरंतर पहल करते रहे। अंत में स्थिति में सुधार हुआ। नीलम देवी संतुष्टि के भावना के साथ बताती है कि, " अब शिक्षक समय से आने लगे हैं और गाँव वालों के प्रति जबाबदेह भी हैं। "

इसी तरह, नारी संघ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज में सुधार के लिए कार्य किया। पी0डी0एस0 के नियमों की जानकारी होने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि गाँव की राशन की दुकान ठीक से नहीं चल रही है। कोटेदार के पंसद और सनक के कारण बी0पी0एल0 कार्ड धारकों ने बहुत कुछ सहा। जब तक वह अपने तरीके में बदलाव नहीं लाया तब तक नारी संघ के सदस्यों ने कई बार उसका सामना किया।

आजाद नारी संघ ने महिलाओं के लिए जॉब कार्ड सुरक्षित करने और मनरेगा में काम सुनिश्चित करने के सफलतापूर्वक संघर्ष किया। प्रासंगिक रूप से नीलम देवी कहती है कि भोजन और काम हमारी मुख्य चिंता है। जब आपका पेट खाली हो तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं कर सकते हैं।"

हालांकि नारी संघ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मजदूरी के मुद्दे को प्राथमिकता पर लिया है, इसके अलावा जब ऐसी कोई अन्य समस्या आती है तो इसने लिंग भेदभाव जैसे मुद्दे को भी उठाया है। संगठन ने महिलाओं की तरफ से इस तरह के कई घटनाओं पर हस्ताक्षर किया है। उनके गाँव के एक ऐसे मामले में, मांस के दुकान का मालिक एक महिला का भेड़ खरीदने के बाद उसको पैसे के भुगतान के लिए परेशान कर रहा था। नाराज महिला ने अपनी इस समस्या को नारी संघ की बैठक में बताया। नारी संघ की सभी महिलाओं ने एक साथ मिलकर दुकान मालिक से संपर्क किया और उस महिला का बकाया धनराशि दिलवाया।

जिस तरह से नारीसंघ का विकास हो रहा है, उसके बारे में नीलम देवी ने अपार संतुष्टि व्यक्त किया। नारी संघ के साथ आने से उनके धारणा में भी बदलाव हुआ है, विशेषकर महिलाओं के सम्बन्ध में। "मैं अब महिलाओं को कमजोर और असुरक्षित के रूप में नहीं देखती हूँ। बल्कि प्रत्येक और हर महिला में लक्ष्मीबाई (झांसी की रानी जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ा) और दुर्गा (जो राक्षसों से युद्ध करने वाली देवी हैं) की अभिव्यक्ति होती है।" नीलम देवी का मानना है कि हर एक महिला के अन्दर सकारात्मक ऊर्जा है और नारी संघ के रूप में उनके संगठन की ताकत कई गुना हो गयी है।

2. अब और विनम्रता नहीं

नारीसंघ के साथ जुड़ करके महिलाओं के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण प्रभाव दिखायी पड़ने लगा है। बड़का देवी प्रतापगढ़ जिले के मंगरौरा ब्लाक के सलाहीपुर ग्रामपंचायत में सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया की प्रमाण विशेष रूप से दलित महिलाओं में ही देखा जा सकता है।

51 वर्ष की बड़का देवी का विवाह 17 वर्ष की उम्र में हुआ और उनके 4 बच्चे हैं। वो खेत में मजदूरी करती है। इनके परिवार के पास थोड़ा सा खेत है जिसमें कि ये लोग अनाज उगाते हैं और आय के लिए खेती की मजदूरी के साथ ही अन्य जगहों पर मजदूरी करके जीवनयापन करते हैं।



“संगठन के अभाव में पहले हम लोग कमजोर एवं शोषित थे।”

— बड़का देवी
अध्यक्ष, नयना नारीसंघ

उनके गाव मे उच्च जाति के लोगो का ही प्रभाव है और वे हमेशा ही दलित समुदाय के लोगो का शोषण करते है। बडका देवी भी अनुसूचित जाति से है और अनेक बार सामाजिक मुद्दो पर भेदभाव उन्होने भी देखा है। उदाहरण के रूप मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हो रहे भेदभाव पर भी देखा जा सकता है, “हांलाकि गरीबो को ही सस्ते राशन सबसे अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन कोटेदार पहले उच्चजाति के लोगो को राशन देने के बाद ही बचा हुआ हम लोगो को देता है। हम

लोगो को यह सब बर्दाशत करना पडता है।” इसी तरह के बहुत से उदाहरण उनके पास बाटने के लिए है।

उसका समुदाय उच्च जाति के लोगो के प्रभुत्व के आगे घुटने टेक देते और आपस मे ही लड़ाई करते। बडका देवी बताती है कि “हम लोगो के समुदाय मे आपस मे ही लोग छोटी छोटी बातो पर लड़ाई करते।” हम लोग अनभिज्ञ थे और हम लोगो को गाव मे सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओ एवं कार्यक्रमो की कोई जानकारी नही थी।” इससे यह जाहिर है कि उनके समुदाय के लोग विकास की योजनाओ से पूरी तरह वंचित रह गए।

नयना नारीसंघ का गठन वर्ष 2009 मे हुआ। नारीसंघ के गठन के लिए आयोजित की गयी कुड ही बैठको ने बड़का देवी के उपर अपनी अमित छाप छोड़ी। यहां पर पहली बार उनको पता चला कि उनके अधिकार क्या होता है और उनके अधिकार क्या है और उनके अधिकारो का किस तरह से हनन हो रहा है। वो याद करते हुए कहती है कि “संतोष (संस्था के कार्यकर्ता) हम लोगो को लगातार बताते कि आप लोगो का हक मारा जा रहा है, वो हमारे गाँव के ही बहुत से उदाहरण देते जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे अनियमितता, मनरेगा मे अनियमितता से ले कर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग आदि को बताते।” पहले तो वे उत्पीड़न को चुनौती न मान करके अपनी किस्मत ही मानते थे, किन्तु हक—अधिकारो की जानकारी होने से हम लोगो का दृष्टिकोण मे परिवर्तन हुआ।

शायद अब उनको यह समझ में आ गया था कि अधिकार कोई किसी को देता नही बल्कि इसको कोई किसी से ले नही सकता। इसके अलावा उन्हे अपने अधिकारो के लिए दावा भी करना पडेगा। जागरूक हो के बड़का देवी ने समुदाय की 35 महिलाओ कों साथ ले करके नारीसंघ से जुडने का निर्णय लिया। वह नारीसंघ की अध्यक्ष चुनी गयी और अन्य कामो के साथ ही उनको अन्य गाँवो मे भी बैठक करके महिलाओ को नारीसंघ के बारे मे चर्चा करके गतिशील करने की जिम्मेदारी दी गयी। वर्तमान मे नारीसंघ की 206 सदस्य है। नारीसंघ के अधिकतर सदस्य अशिक्षित थे और बडका देवी भी पूरी तरह से अशिक्षित थी अत उन्होने संस्था द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संदर्भन केन्द्र चलाने के लिए अपने घर मे जगह भी दी।

बडका देवी के नेतृत्वकारी लक्षण स्पष्ट हो गए, जैसे कि उन्होने नरेगा के मुददे पर की गयी पहल को बताते हुए कहती है कि “जब काम की मांग करने के लिए कुछ महिलाए प्रधान के पास गयी, तो उन्होने काम देने से इन्कार कर दिया। उसके बाद 32 सदस्यो को साथ ले करके पुन अपनी मांग को दोहराया, और कहा कि महिलाए कार्यस्थल पर धरना देगी और तब तक किसी को भी काम नही करने देगी, जब तक की महिलाओ को काम नही मिल जाता।” इसके बाद किसी तरह से प्रधान ने हम लेगो से दूसरे दिन आवश्यक औजार ले करके कार्यस्थल पर आने के लिए कहा। किसी तरह से दूसरे दिन काम पर जाने के लिए फावडा और छौली का इंतजाम किया। प्रधान ने पुरुषो कं बराबर ही हम लोगो को भी काम दिया। हम लोगो ने कम समय मे पुरुषो से भी पहले काम को पूरा कर लिया। अब प्रधान के पास हम लोगो काम न देने का कोई भी वजह नही थी। अगले ही दिन 32 महिलाओ को जॉबकार्ड मिल गया और अपने नाम से बैंक मे खाता भी खुलवाया। उसके बाद से महिलाओ काम मिलने मे कोई समस्या नही हुई। उन्होने लिंग एवं रूढ़िवादिता पर आधारित व्यवस्था को भी चुनौती देते हुए यह दिखा दिया कि महिलाए भी अपरंपरागत कार्यों को करने मे सक्षम है। आज उनके गाव मे मनरेगा कार्यस्थल पर महिलाए ही अधिक संख्या मे काम करती है। इससे आगे बढ महिलाओ ने नरेगा के कार्या का निष्पादन भी सुनिश्चित कराया। अब तो गांव का नरेगा पर्सपेक्टिव प्लान भी बन गया है जिससे की मानवदिवस मे वृद्धि हो सके।

सलाहीपुर के नारीसंघ ने गाँव की स्थिति मे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। कोटेदार जो कि पहले उच्च जाति के लोगो की तरफदारी करता था आज वह भी बी0पी0एल0 कार्डधारको को प्राथमिकता देने लगा है। पहले जो महिलाएं प्रधान के सामने अपनी बाते नही रख पाती थीं आज वो ही ग्रामसभा की बैठक मे जा करके अपनी मांगो को भी रखने लगी हैं।

बड़का देवी से चर्चा के दौरान अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में भी चला। महिलाओं का संगठित एवं एकजुट हो करके काम करना ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। बड़का देवी जोकि आज संगठित आवाज एवं संगठित पहल को महत्वपूर्ण मानती हैं, वे कहती हैं कि “पहले हम लोग कमजोर एवं दबू थे क्योंकि हम लोग संगठित नहीं थे।”

3. जन्म से संघर्षकारी स्वभाव

छविराजी देवी 8 सितम्बर 2010 को गठित हुए गंगा नारीसंघ की सक्रिय सदस्य हैं। 48 वर्ष की छविराजी देवी अब अगुआ के रूप में जानी जाती हैं हालांकि अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने सफलतापूर्वक अपना जीवनयापन किया।

मऊ जिले के घोसी ब्लॉक के रसड़ी गाँव की छविराजी देवी जन्मजात बहादुर हैं। जीवन में उनके सामने अनेक समस्याएं आयीं किन्तु सभी के समक्ष वे हिम्मत एवं जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर सामना किया।

छविराजी देवी का गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण अनेक बार समझौता करना। उनके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पाचवी कक्षा के बाद ही उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनका विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर उनको अपने बीमार पति एवं ससुर की देखभाल गरीबी के बीच ही करनी पड़ी। वह अपने परिवार के गुजारे के लिए मजदूरी करने लगी। कम उम्र में ही उनके पति का भी निधन हो गया। फिर उन्होंने अपने दोनों बच्चों की अकेले ही देखभाल की। हालांकि उनके बड़े पुत्र की 17 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण मृत्यु हो गयी।

छविराजी देवी ने यह शोक भी निगल लिया और छोटे बेटे की देखभाल करने लगी। अब वह बड़ा हो करके अपने परिवार की आय में भी योगदान दे रहा है।



“नारीसंघ की सदस्यों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप ही वे जाति एवं धर्म आधारित भेदभाव से ऊपर उठ करके एक दूसरे को सुनने एवं सम्मान भी देने लगी हैं।”

— छविराजी देवी
अध्यक्ष, गंगा नारीसंघ

छविराजी देवी के संघर्षमयी जीवन के कारण महिलाओं की समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर उनकी संवेदना थी, अतः उन्होंने नारीसंघ से जुड़ने का निर्णय लिया। “महिलाएं जाति, समुदाय एवं संस्कृति के आधार पर बँटे होने के कारण ही उन्होंने एक दूसरे की सहयोग एवं समर्थन करना ही नहीं सीखा।” छविराजी देवी ने अकेले ही अपने परिवार की देखभाल की थी। वह महिलाओं की स्थिति के प्रति चिंतित थी और उनको लगता है कि संगठित हो करके ही महिलाओं को समाज में महत्व एवं सम्मान मिल सकता है जिसकी वे हकदार हैं। “मेरा विश्वास है कि संगठित होने के बाद ही महिलाओं की समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है।” उन्होंने नारीसंघ का हिस्सा बनने का फैसला इस उम्मीद के साथ किया कि इसके

माध्यम से महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूक हो करके सरकारी योजनाओं को समझ कर एवं प्राप्त करके ही आत्मनिर्भर हो पाएंगी। गंगा नारीसंघ ने अच्छी तरह से काम करके उनकी दोनों ही दुविधाओं को समाप्त किया।

नारीसंघ की सफलता में छविराजी देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सीख भ्रमण में प्रतिभाग करने से उनकी समझ विकसित हुई। अब वो स्थानीय महिलाओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सूचना के अधिकार, मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन गयी हैं।

बिना कष्ट उठाए, कोई लाभ नहीं मिलता—यह कहना है जानकारी प्राप्त करने की इच्छुक छविराजी देवी का। वे याद करते हुए बताती हैं कि किस तरह से उनका पुत्र एवं पड़ोसी नारीसंघ के काम से बाहर जाने के खिलाफ थे। “मेरा बेटा मेरे बार बार यात्रा करने, बाहर जाकर बैठको एवं प्रशिक्षणों में प्रतिभाग लेने के विरुद्ध था, कई बार तो उसने मुझे बाहर जा करके इन कामों को बंद करने के लिए भी कहा। अंत में जब उसकी बातों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो पड़ोसी भी उसकी निराशात्मक धुन में

शामिल हो गए। उनके विरोध एवं आलोचना के बावजूद भी छविराजी देवी अपने विश्वास के साथ जारी रखा। नारीसंघ के पहल की सफलता देखने के बाद ही उनके प्रतिरोध कम होने लगे।

प्राप्त ज्ञान एवं जानकारी के माध्यम से छविराजी देवी ने नारीसंघ की 5 विधवा सदस्यों की पेंशन के लिए पहल करके उसको पुनर्जीवित करने में मदद की। परिणामस्वरूप बिना कोई कारण बताए उनकी ही पेंशन रोक दी गयी, और सब मेहनत बेकार हो गयी। उन्होंने अपनी स्थिति का विवरण ग्रामप्रधान एवं ब्लाक पर संबंधित अधिकारी को बताया, किन्तु कोई कार्यवाही न हुई। इसी बीच उन्होंने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से प्राप्त जानकारी के आधार पर उन्होंने इस मुद्दे पर नए सिरे से कार्यवाही की और सफलता मिलने तक प्रयास जारी रखा। सफलता प्राप्त होने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने नारीसंघ के 10 सदस्यों का मनरेगा में जॉबकार्ड एवं व्यक्तिगत खाता भी खुलवाया। छविराजी देवी बताती हैं कि "मुझे भी इन योजनाओं के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही जानकारी हुई है। पहले भी मैं ब्लाक पर अधिकारियों से बात तो कर लेती थी किन्तु जानकारी मिलने के बाद प्राप्त हुई सफलताओं और उपलब्धियों से मेरा हौसला मजबूत हो गया है।" छविराजी देवी ने नारीसंघ के सदस्यों का सिर्फ जॉबकार्ड बनवाने एवं बैंक में खाता ही नहीं खुलवाया बल्कि साथ ही उनको सशक्त करने का काम भी किया, जिससे कि वे बेरोजगारी भत्ते की मांग कर सकें एवं कोई समस्या होने पर मनरेगा हेल्पलाइन का उपयोग करके समाधान कर सकें।

छविराजी देवी के अनुसार नारीसंघ का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि महिलाओं के सोच एवं नजरिए तथा धारणा में परिवर्तन है। नारीसंघ की नेतृत्वकर्ता, जो कि सभी महिलाओं को संगठित देखना चाहती हैं, वो बताती हैं कि "नारीसंघ के सदस्य अब जाति एवं समुदाय के विभाजन के दायरे से उपर उठ कर इन असमानताओं को समाप्त करके एक साथ बैठको में आ करके बिना किसी संकोच के एक दूसरे से बात करने लगे हैं। महिलाओं में असमानता कम हुई और सभी एक दूसरे का सम्मान करने लगी हैं।"

4. स्थानीय सत्ताधरियों को चुनौती

गाजीपुर जिले में, सदर ब्लाक में, औरंगाबाद गाँव की रहने वाली अनरसी देवी का मानना है कि, "नारी संघ के साथ जुड़ाव होने के बाद मुझे महिलाओं के पास की आंतरिक शक्ति का एहसास हुआ है। मुझे लगता है कि महिलायें कुछ भी करने के लिए सक्षम हैं, बशर्ते उनको सही जानकारी और सही मार्गदर्शन मिलता रहे।"

पचास साल के उम्र की अनरसी देवी महामाया नारी संघ की अध्यक्ष हैं जिसका गठन जून 2009 में किया गया। एक बच्चे के रूप में, वे अपनी स्कूली शिक्षा से चूक गयी थीं। अब वह और अनपढ़ नहीं रहना चाहती हैं और इसीलिए अन्य नारी संघ के सदस्यों के साथ साक्षरता केन्द्र की कक्षाओं में आती हैं।

अनरसी देवी यह स्वीकार करती हैं कि, "ग्रामीण महिलाओं को एकजुट करना आसान नहीं है। वास्तव में, यह उतना मुश्किल है जितना चट्टान पर घास उगाना।" वह अपने नारी संघ के बारे में और अधिक बताते हुए कहती हैं कि संगठन के रूप में नारी संघ उनके लिए बहुत मायने रखता है।

हालांकि नारी संघ के गठन के पहले की स्थिति को समझाते हुए वे कहती हैं कि, "महिलायें पूरी तरह से पुरुषों पर आश्रित थी, वे स्वयं से निर्णय लेने में डरती थी और इसीलिए शायद वे कभी भी स्वतंत्र रूप से बातचीत नहीं कर पाती थी।" पीछे मुड़ कर देखे तो, उन्हें लगता है कि असुरक्षा और नकारात्मक सोच ही महिलाओं को पीछे ले जाती है। शुरुआत में कई लोग बैठकों में प्रतिभाग करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ समय बाद, 17 महिलाओं को साथ लेकर नारी संघ के गठन का फैसला लिया गया।

यद्यपि परिवार के लोग उनका सहयोग करते थे, फिर भी अनरसी देवी को गाँव वालों के विरोधों का सामना करना पड़ा था। उन लोगों ने, उन्हें समुदाय की महिलाओं को संगठन के गठन के माध्यम से बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया। वे लोग उनके



“नारी संघ हम महिलाओं के सामूहिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारे समुदाय के लोग भी हमें गम्भीरता से लेते हैं और हमारे सुझावों को महत्व देते हैं।”

—अनरसी देवी
अध्यक्ष, महामाया नारी संघ

प्रयासों को यह कह कर खारिज कर दिया कि बैठक से कुछ नहीं होने वाला है। यहां तक कि उन लोगों ने उनके पहल और नेतृत्व का भी मजाक उड़ाया। अपने अन्दर विश्वास बनाये रखने के लिए अनरसी देवी के लिए यह कठिन समय था।

नारी संघ के अध्यक्ष के रूप में, महिलाओं को एकजुट करने और नारी संघ में सदस्यता बढ़ाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत से काम किया जिसके फलस्वरूप सितम्बर 2011 तक 197 महिलायें संगठन से जुड़ गयीं। नारी संघ की गठन की प्रक्रिया से ही महिलाओं में कई तरह का बदलाव आया। अब वे एक साथ मिलकर रहने से परहेज नहीं करती हैं। अब महिलायें एक फोन पर तुरंत इकट्ठा हो जाती

हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार रहती हैं।

इस नारी संघ ने महिलाओं के नाम जॉबकार्ड बनवाने के लिए अपने सामूहिक शक्ति का प्रयोग किया। अनरसी देवी पूरी भावना के साथ अपने इस पहल को बयान करते हुए कहती हैं कि, “जॉबकार्ड प्राप्त करने के लिए हमने कई बार प्रधान, पंचायत सचिव और ब्लाक स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात किया। यद्यपि हमारे सभी प्रयास विफल रहे और हम निराश थे। एक बार जब हम ब्लाक कार्यालय में गये थे तो हमने सी0डी0ओ0 (मुख्य विकास अधिकारी) के कार का अन्दर प्रवेश करते हुए देखा। उसी समय हमने एक बार उन्हें पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने हमारी मांगों को सुना और प्रधान व पंचायत सचिव को तुरंत हमारे जाब कार्ड को जारी करने का आदेश दिया। उसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जल्द जाब कार्ड नहीं मिलने के स्थिति में हम उनसे दोबारा मिल सकते हैं। अगले दिन आवेदन के अनुसार 65 लोगों को जाब कार्ड मिला। हम खुश थे।” अनरसी देवी जानती थी कि प्रधान बहुत सी महिलाओं को जाब कार्ड देने के लिए इच्छुक नहीं था। जाब कार्ड सौंपते समय उसने अपने क्रोध को व्यक्त किया। उसने कहा कि जाब कार्ड बनवाने से कोई फायदा नहीं है उन लोगों को काम नहीं मिलेगा। अनरसी देवी ने उसके शब्दों को चुनौती के रूप में लिया। “हमने 35 दिन के काम का मांग किया। शुरु में प्रधान ने हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया लेकिन बाद में मान गया और एक दिन उसके जमीन पर काम मिला और हमे मजदूरी भी प्राप्त हुई।” हांलाकि प्रधान महिलाओं के साथ चाल चल रहा था। “बाद में हमें एहसास हुआ कि वह धन अनुचित था। मनरेगा कानून के अर्न्तगत केवल बी0पी0एल0 और अनुसूचित जाति परिवारों के लिए ही व्यक्तिगत भूमि पर विकास के कार्य की अनुमति है। संस्था की सामूदायिक कार्यकर्ता ने हमें हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत करने का सुझाव दिया जो हमने किया।” अनरसी देवी ने हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई और डी0एम0 (जिला मजिस्ट्रेट) से भी बात किया जिन्होंने सी0डी0ओ0 व बी0डी0ओ0 को आगे की जांच के लिए कहा। अंत में, प्रधान ने उपयोग किए गये अनुचित धन को वापस किया। अनरसी देवी खुश थी कि वे प्रधान को सबक सिखाने में सक्षम थी।

अब तक अनरसी देवी को यह एहसास हो गया था कि जाबकार्ड प्राप्त करने से ज्यादा कठिन है और उनका संघर्ष अभी तक जारी है। हाल ही में उन्होंने ब्लाक कार्यालय में काम की मांग को रखने के लिये 65 महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया। उन लोगों ने बी0डी0ओ0 का घेराव किया और कार्रवाई की मांग किया। एक पखवाड़े के अन्दर 90 महिलाओं को 4 दिन का काम मिला।

इस अनुभव के बाद उनमें और अधिक विश्वास व दृढ़ निश्चय हो गया। यहाँ तक कि उन्होने उच्च जाति के यादव परिवार के नेता का सामना किया जो गरीब गाँव वालों पर अपनी शक्ति दिखा रहा था। किसी ने भी उसको चुनौती देने की हिम्मत नहीं किया लेकिन अनरसी देवी ने उसे चुनौती दिया। यादव ने उन्हें गम्भीर रूप से मारा लेकिन अनरसी देवी ने उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवायी। उसे 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। स्थानीय सत्ता का समीकरण निश्चित ही बदल रहा है।

समुदाय के लोगों ने नारी संघ के गतिविधियों में सहयोग किया और बढ़ावा दिया है। अनरसी देवी ने अधिकतर लोगों में हुए व्यवहार परिवर्तन की सराहना करती हैं। महिला अगुआ गर्व के साथ कहती हैं कि, “नारी संघ हम महिलाओं की सामूहिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारे लोग हमें गम्भीरता से लेते हैं, हमारे सुझावों को महत्व देते हैं, हमारा सम्मान और सहयोग करते हैं।”

5. सक्रिय नेतृत्वकर्ता

गाजीपुर जिले के जखनिया ब्लाक के गौराखास ग्रामपंचायत की नसीम बानो चिंगारी नारीसंघ की अध्यक्ष हैं। वे शक्ति नारी महासंघ की अध्यक्ष भी हैं, जिनमें की सभी ग्रामपंचायतों की नेतृत्वकर्ता ब्लाक पर नारीमहासंघ के रूप में बैठक करती हैं। नसीम बानो ने सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता एवं उनके सक्रिय दृष्टिकोण के आधार पर पहले ही नेतृत्व क्षमता को साबित कर चुकी हैं। हालांकि यहां तक का सफर उनके लिए आसान नहीं रहा है।

नसीमबानो की उम्र 46 वर्ष की है और उनके 5 बच्चे हैं। वो एक बड़े संयुक्त परिवार के रूढ़िवादी दृष्टिकोण से आती हैं। उनके परिवार में महिलाओं को सम्मान मिलता है किन्तु उनको परदे में रहना एवं घर से बाहर निकलने की भी कोई आजादी नहीं है और घर के निर्णयों में बोलने की भी आजादी नहीं है। परिवार की बड़ी बहू होने के कारण परिवार के नियमों का उनको कड़ाई के साथ पालन करना था।



नसीम बानो बताती हैं कि उनको आज भी याद है कि उनको पहली बार घर से बाहर बैठक में जाने के लिए किस तरह से उनके ससुर उनके ऊपर गुस्सा हुए थे। “उन्होंने कहा कि मैं परिवार के भले के लिए ही जैसा सोचता हूँ, वो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं समाज में अपने परिवार की इज्जत कम होते नहीं देख सकता।” इसके बाद भी वो नारीसंघ की बैठकों में प्रतिभाग करती रही और वर्ष 2010 में नारीसंघ की अध्यक्ष के पद के लिए उनका चुनाव हुआ। जब महिलाओं को बैठक में दी जा रही सूचनाओं का महत्व समझ में आया तब से उनकी बैठकों सहभागिता बढ़ती गयी। वर्तमान में नारीसंघ की 150 सदस्य हैं।

जैसे जैसे संगठन के सदस्यों की संख्या बढ़ी, परिणामस्वरूप परिवार का प्रतिरोध कम होने लगा। हालांकि एक घटना के माध्यम से नसीम बानो के विशेष कार्य एवं नारीसंघ के काम के महत्व पर प्रकाश डालता है।

महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय में तभी कमी आ सकती है जब कि महिलाएं स्वयं जागरूक हों यदि महिलाएं अपने साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध जागरूक हों आवाज उठाने लगे, तब ही उनके साथ अन्याय में कमी आ सकती है।

—नसीम बानो
अध्यक्ष, चिंगारी नारीसंघ

नसीमबानो को वह घटना आज भी ताजा याद है “एक दिन जब सुबह की नमाज के लिए उठी, मैंने देखा कि घर के बाहर बहुत से लोग हैं और सब अलग अलग कुछ फुसफुसा रहे थे। पूछने पर पता चला कि पास के घर में युवा बहू की कल रात में ही मृत्यु हो गयी। लोग कह रहे थे कि वह कल सोयी और नींद में ही निधन हो गया। मेरे लिए यह चौंकाने वाली बात थी और इस बात का पता उनके परिवार से लगाने के लिए उनके घर गयी। उसकी सास ने कहा कि वो रात में खाना खा करके सोयी और अब कोई सुराग नहीं कि क्या हो गया। बात करने के दौरान ही उन्होंने अपनी बहू के चरित्र पर संदेह व्यक्त किया। उनकी बात सुनने के बाद मुझे संदेह लगा और जहां मृत शरीर रखा था मैं वहां पर गयी। उसके मृत शरीर को देख करके उनकी मृत्यु मुझे स्वाभाविक नहीं लगी। जब मैंने उनके परिवार से पूछा कि क्या उन्होंने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, तब उनके बड़े पुत्र ने बताया कि उन्होंने सूचित कर दिया और अब अंतिम संस्कार करने के लिए भी जा रहे हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा कि उसके मायके वालों को सूचित किए बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे प्रश्न उन लोगों को परेशान कर रहे थे और उनका डर चेहरे पर दिखने लगा था।” इसी के साथ नसीम बानो का शक विश्वास में बदलने लगा। फिर उन्होंने पुरानी घटनाओं को इस घटना से संबद्ध किया। उनकी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और उसको पड़ोस के लोगों से भी बात करने की आजादी नहीं थी। यह सब सोचने के बाद अब नसीम बानो के लिए घटना पर पहल करने का समय था। उन्होंने तुरंत ही वहाँ उपस्थित नारीसंघ के सदस्यों से बात की और सभी से पुलिसस्टेशन चलने का अनुरोध किया। हालांकि किसी ने सहयोग नहीं किया। वह अकेले ही घटना की रिपोर्ट करने गयी। थोड़ी देर बाद पुलिस आयी किन्तु जाँच करके बिना किसी कार्यवाही के वापस चली गयी। नसीमबानो उस मृत महिला को न्याय दिलाने के लिए चिंतित थी, किन्तु इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि उन्होंने शांत बैठने के बजाय नारीसंघ की बैठक बुला करके मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने उस घटना को

अपने शब्दों में नारीसंघ की बैठक में कहा और बहनों को इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाने का अनुरोध किया। अंत में नारीसंघ की सदस्यों ने संगठित हो कर दोषियों को सजा दिलाने का निर्णय किया और इस बार नारीसंघ सदस्यों ने उनको निराशा नहीं किया। सभी एक साथ पुलिस स्टेशन पर इस केस लिखने की मांग की। 8 दिन बीत चुके थे, अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। बिना किसी निराशा के नसीम बानो पुनः नारीसंघ की 150 सदस्यों को ले करके थाने पर पहुँच गयी, किन्तु इसका भी कोई प्रभाव नहीं दिखायी दिया तब नारीसंघ की बैठक में चर्चा के उपरांत इस मुद्दे को तहसील दिवस पर उच्च अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। एक वकील की सहायता से महिलाओं ने इस घटना पर विस्तृत आवेदन तैयार करके अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके निरंतर प्रयासों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। अंततः नारीसंघ और मुख्य रूप से नसीम बानो की पहल का प्रभाव दिखायी देने लगा। अंत में इस केस की सी0बी0आई0 जाँच हुई और जांच के दौरान उसके पति ने स्वीकार किया वह स्वयं एवं उसके परिवार के सदस्य ही उसकी पत्नी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। नारीसंघ की नसीम बानो एवं लक्ष्मीदेवी ने भी अपने बयान दर्ज कराए। आरोपियों में उसके परिवार के सदस्य एवं पति को अदालत में दोषी साबित होने के बाद उनके विरुद्ध मजबूत मामला बनाया गया।

नसीम बानो का मानना है कि “महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय में तब तक कमी नहीं आ सकती, जब तक की वे जागरूक हो कर इन पर हस्तक्षेप करना प्रारम्भ नहीं कर देती।” उन्होंने स्वयं ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, किन्तु वे इसका श्रेय नारीसंघ को देते हुए कहती हैं कि “यदि मैं नारीसंघ से नहीं जुड़ती तो मैं यह सब नहीं कर पाती, अमूल्य जानकारी एवं समर्थन के कारण ही संभव हुआ।”

गाँव एवं परिवार के सदस्य भी नसीम बानो के द्वारा किए गए प्रयास की सराहना करते हैं। अब उनके ससुर उन्हें बाहर निकलने के लिए कभी विरोध नहीं करते। नसीम बानो का सोचना है कि परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार तो अवश्य ही हुआ है किन्तु अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है।

6. चन्द्रमी देवी

मऊ जिले के मोहम्मदा ब्लाक में मालव गाँव की रहने वाली चन्द्रमी देवी कहती हैं कि “दीदी ने हमें महिलाओं के अधिकारों के इस्तेमाल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम ग्राम सभा की खुली बैठक में भाग ले सकते हैं, जब भी हम काम करना चाहे हम काम की मांग कर सकते हैं। हमारे लिए यह सब नया था और एक सपने की तरह अविश्वसनीय लग रहा था।” यह उन दिनों की बात कर रही है जब उनके गाँव में नारीसंघ की गठन की प्रक्रिया का बस शुरुआत भर हुयी था।

अब स्थिति बदल गयी है। वह केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है बल्कि उसे पूरा लेना भी सीख गयी है। चन्द्रमी देवी डॉ० सविता अम्बेडकर नारी संघ की अध्यक्ष हैं जिसका गठन मई 2010 में किया गया। वर्तमान में 93 महिलायें सदस्य के रूप में जुड़ी हैं।

पैंतीस वर्ष की चन्द्रमी देवी एक गरीब, मजदूर वर्ग के परिवार से हैं। पांच साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गयी थी, उनके समुदाय में रीति रिवाज के रूप में बाल विवाह की प्रथा मौजूद है। ये पांच बच्चों की मां हैं और इनके पति दर्जों का काम करते हैं। यह स्वयं एक कृषि मजदूर के रूप में काम करती हैं।

इससे पहले उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के बारे में केवल सुना था लेकिन किसी से भी लाभ नहीं मिला था। उन्होंने और उनके गाँव की बहुत सी महिलाओं ने एक ही अनुभव का बताते हुए कहा कि, “कल्याणकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। बालिक प्रधान से कोई भी काम करवाना असंभव कार्य लग रहा था। रिश्वत देने के बाद ही वह कोई काम करता था। महिलाओं के लिए बस यह दुर्गम काम था।”



“मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ—बैंक में खाता खुलवाने से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने तक।”

— चन्द्रमी देवी,
अध्यक्ष, डॉ० सविता अम्बेडकर नारी संघ

चन्द्रमी देवी बताती है कि, “इस कठिनाई का अनुभव होने के बाद हमने एहसास किया कि हम एक साथ मिलकर हम कुछ बदलाव लाने में सक्षम हो जायेंगे। हम सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सक्षम हो जायेंगे।” महिलाओं ने सोचा— व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने में क्या मुश्किल है जब सामूहिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

नारी संघ, महिलाओं को एक न्यायसंगत मंच प्रदान करता है जहाँ वह अपनी समस्याएँ रख सकती है। आजीविका का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था और इसीलिए वे लोग इसे सबसे पहले प्राथमिकता पर लेने का फैसला किया। जिनको मनरेगा के तहत काम की आवश्यकता थी, ऐसे कई लोगों के पास जाब कार्ड नहीं था, इसलिए जाब कार्ड बनवाने के लिए प्रयास किया गया। संस्था के कार्यकर्ताओं ने अधिकार और अधिनियम के प्रावधानों पर अच्छी तरह से अभिमुखीकरण किया। अपने पहल करने के पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से बताते हुए चन्द्रमी देवी कहती है कि, “जानकारी के आधार पर मैंने रोजगार सेवक से मुलाकात किया और 55 महिलाओं का जाब कार्ड हेतु आवेदन दिया। 31 महिलाओं के परिवार में जाब कार्ड तो था लेकिन महिलाओं का नाम उसमें शामिल नहीं था। जाब कार्ड अपने नाम करवाने के बाद, हमें बैंक में खाता खुलवाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से जाकर, स्वयं के नाम से स्वतंत्र खाता खुलवाने के लिए बैंक मैनेजर पर दबाव बनाया।”

अपने नाम जाब कार्ड व बैंक खाता होने के बाद महिलायें काम प्राप्त करना चाहती थी। सही जानकारी और सामूहिक आत्मविश्वास होने के बाद महिलायें जो चाहती थी वह प्राप्त कर पायीं। चन्द्रमी देवी गर्व के साथ कहती है कि, “110 महिलाओं ने एक साथ लिखित आवेदन देकर काम की मांग किया। हम लोग यह जानते थे कि प्रधान हमारे साथ चाल चलेगा इसलिये हम लोग सीधे ब्लाक कार्यालय जाकर ए०पी०ओ० (कार्यक्रम सहायक अधिकारी) को अपना आवेदन दिया। 15 दिनों के अन्दर ही हम लोगों को काम मिल गया।” चन्द्रमी देवी मनरेगा प्रावधानों से अच्छी तरह से वाकिफ थी, उन्हें कार्य स्थल पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधाओं के बारे में पता था। इसके लिए पहल करने के कारण पीने के पानी की सुविधा, मूलभूत दवायें और छाया की सुविधा उपलब्ध कराया गया।

सभी मनरेगा कार्यस्थल पर एक मेट होता है, प्रत्येक 25 मजदूर पर एक मेट होता है और इसका चुनाव गँवों वालों के बीच से ही इसका चुनाव किया जाता है। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि अगर कार्यस्थल पर महिला मजदूरों की बहुमत है तो वहाँ महिला मेट होगी। फिर भी, आमतौर पर पुरुषों को ही मेट के रूप चयन किया जाता है, बहुत कम ही महिलाओं को मेट का काम करते हुए देखा जा सकता है। विशेष रूप से इस ग्राम पंचायत के संदर्भ में, नारी संघ के प्रभाव के कारण पहली बार ग्राम सभा में चंदा देवी नाम की महिला का चुनाव मेट के काम के लिए किया गया। अपनी क्षमता के आधार पर वह पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही है। अन्य बातों के अलावा, मजदूरों का पर्यवेक्षण, बी०पी०एल० परिवार का रिकार्ड तैयार करना, जाब कार्ड सुनिश्चित कराना और मस्टर रोल के अपडेशन के साथ—साथ मजदूरी वितरण भी शामिल है।

महिलाओं को चन्द्रमी देवी और उसकी क्षमता पर विश्वास है। नारी संघ के सदस्यों के लिए वह एक अच्छी नेतृत्वकर्ता और आदर्श महिला है। “मैं उनको ग्राम सभा में अपनी बात रखने के लिए सक्षम बनाती हूँ और उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देती हूँ।” पहले महिलायें प्रधान के पास जाने में स्वयं को योग्य नहीं थी, लेकिन अब वे अपने काम को पूरा कराने के लिए प्रधान के पास जाने लगी हैं। कभी—कभी ग्राम प्रधान को नारी संघ की बैठक में, महिलाओं के सुझावों व मांग को सुनने के लिए बुलाया जाता है। वह उनको और अधिक नजरअंदाज नहीं कर सकता है। समान परिवर्तन समुदाय के सदस्यों के अन्दर भी दिखायी देता है। पहले लोग सोचते थे कि महिलायें कुछ भी नहीं जानती हैं और कुछ नहीं कर सकती हैं। हांलाकि अब वे महिलाओं के महत्व को कम नहीं कर सकते हैं। चन्द्रमी देवी कहती है कि, “अब हमारे समुदाय के लोग हमारा सम्मान करते हैं और हमारे विचारों को भी ध्यान में रखते हैं।”

चन्द्रमी देवी अपने अन्दर एक बड़ा परिवर्तन देख रही हैं। उन्हें लगता है कि अधिक मुखर और आश्वस्त हो गयी हैं। “मैं अब सब कुछ करने में सक्षम हूँ— बैंक में खाता खुलवाने से लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने तक।” कोई भी कठिनाई होने पर वह संस्था के कार्यकर्ताओं से सलाह लेती हैं। एक सच्चे अगुआ की तरह, वह अपनी आवाज को गँव, ब्लाक व जिला स्तर पर महिलाओं की मांग को बढ़ावा देने और महिला मुद्दों पर पैरोकारी के लिए उठाती हैं।

7. उत्पीड़न के चक्र को तोड़ता नारीसंघ

पुष्पा देवी महिलाओं की दुर्दशा को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करती है। उनके अनुसार महिलाएं आपस में ही कभी खुल करके बात नहीं करती। पारिवारिक दबाव उन्हें समाज में जाकर लोगों से मिलने में बाधा बनता है। जानकारी के अभाव में वे पति के ऊपर ही निर्भर रहती हैं। परिवार के लोग न तो महिलाओं की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं और न ही उन्हें सहयोग करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी न खत्म होने वाला काम ही उनके जीवन का हिस्सा है और दूसरी की सेवा महिलाएं जीवन के अंतिम पड़ाव तक ही करती रहती हैं। आमतौर पर महिलाओं के लिए यही निर्धारित है, जब तक की वे स्वयं से इसमें परिवर्तन करने की पहल एवं प्रयास नहीं करती।

नारीसंघ के गठन के माध्यम से ही 37 वर्षीय पुष्पा देवी एवं अन्य सदस्य वाराणसी जिले के आराजी लाइन ब्लॉक की महिलाएं उत्पीड़न के चक्र को तोड़ने में सक्षम हो सकीं। वह कहती हैं कि "हम किसी से कम नहीं हैं।"



वर्तमान में पुष्पा देवी सुरक्षा नारीसंघ की कोषाध्यक्ष हैं और इसका गठन वर्ष 2008 में हुआ एवं वर्तमान में 253 सदस्य हैं। उनका कहना है कि "हम लोगों के यहाँ पहले से ही दो स्वयं सहायता समूह हैं, किन्तु वह भी सिर्फ बचत के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। संगठित होकर अपने अधिकारों को समझ करके प्राप्त करने की बात से हम लोग प्रभावित हुए।"

शुरुआत में परिवार के सदस्यों का सहयोग नहीं मिल रहा था। मुख्यरूप से उनके जेट (पति का बड़ा भाई), जेटानी (बड़े भाई की पत्नी) उनके बाहर जा करके बैठको एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने का विरोध करते थे। दोनों ही उनके पति से शिकायत करते एवं उनके खिलाफ भड़काने का भी प्रयास करते। किन्तु जब उन लोगों के अवरोधात्मक प्रयासों के बावजूद भी पुष्पा देवी ने बैठको एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना नहीं छोड़ा, अंत में परिवार से उनको पूरी तरह से असहयोग मिलने लगा।

"महिलाओं को संगठन की अवधारणा से यह महसूस हुआ कि वे इसी के माध्यम से अपने हक एवं अधिकारों को समझ कर प्राप्त करने में सक्षम हो सकती हैं।"

—पुष्पा देवी
अध्यक्ष, सुरक्षा नारीसंघ

एक विशेष घटना बहुत ही रोचक है। पुष्पा देवी की रोज घर की गतिविधियों में घर के लोगों की देखभाल करना एवं खाना खिलाना तो था ही साथ ही गाय के चारा खिलाने से लेकर दूध निकालने तक की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। नारीसंघ की ओर से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए उनको कलकत्ता जाना पड़ा। जब वे चली गयी तो परिवार के किसी भी सदस्य ने गाय को न तो किसी न चारा खिलाया और न ही उसका दूध निकाला। उनके ऐसा करने के पीछे सोच थी कि पुष्पा देवी को बाहर जाने से रोकना और इसी लिए परिवार के लोगों ने ऐसा किया जिससे कि वे प्रिय

गाय दुर्दशा देखने के बाद आगे से कहीं भी नहीं जाएंगी। वह उस गरीब जानवर की घोर उपेक्षा देख करके बहुत ही दुखी हुईं और इसी घटना के बाद उन्होंने उसके बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने नारीसंघ को प्राथमिकता देते हुए किसी भी ऐसे घरेलू काम को न करने का निर्णय जिससे की घर की चहरदिवारी में ही सिमट कर रह जा।

सुरक्षा नारीसंघ में पुष्पा देवी जैसे प्रतिबद्ध सदस्य नारीसंघ के कार्यों की छाप छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। महिलाओं के द्वारा किए जा रहे संगठित प्रयासों से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। ग्रामसभा की बैठक एवं उसकी प्रक्रिया के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था किन्तु आज नारीसंघ के द्वारा बैठक के आयोजन की मांग की जा रही है और बैठक में महिलाएं अपने मुद्दों पर चर्चा भी कर रही हैं। इसके अलावा नारीसंघ के द्वारा अनेक मुद्दों पर आवाज उठा कर पहल भी की गयी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमितिकरण से लेकर मिड डे मिल, जननी सुरक्षा योजना, महामाया और मनरेगा जैसी योजनाओं के अंतर्गत आ रही समस्याओं के समाधान के लिए पहल भी की गयी। पुष्पा देवी ने मनरेगा एक्ट, आर0टी0आई0, घरेलू हिंसा एवं जेण्डर विषयक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। पुष्पा देवी सदैव प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए उत्सुक रहती हैं क्योंकि उनका मानना है कि जानकारी से ही पहल करके आगे बढ़ कर सफलता प्राप्त करने का साहस मिलता है।

पुष्पा देवी के अनुसार महिलाए अब महिलाए अधिक स्वतंत्र हो गयी है। वे अपना निर्णय लेने में सक्षम हो रही है। महिलाएं आज परिवार के बदले हुए स्वभाव पर आज गर्व महसूस करती है। उनके निकट संबंधी जिन्होंने पहले नारीसंघ में जाने का विरोध किया, आज वे ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले भी मेरी राय मांगते है। परिवार एवं समाज के उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय प्रयासों की श्रृंखला के कारण ही आज महिलाओं की भी जानकारों में गिनती की जाने लगी है और उनके सुझावों को भी महत्व दिया जा रहा है। पुष्पा देवी बताती है "मुख्य रूप से बच्चों के भविष्य अर्थात् शिक्षा एवं उनके विवाह के मुद्दे पर" महिलाओं के सुझावों को प्राथमिकता दी जाने लगी है।

महिलाए गर्व महसूस करती है कि आज उनके नाम से बैंक में खाता है जिसमें कि नरेगा का पैसा सीधे स्थानान्तरित हो जाता है। अतः उनकी आय पर पूरी तरह से उनका ही अधिकार है। रोजगार गारंटी कानून आने के परिणामस्वरूप पहले की तुलना में आज उनकी आय में वृद्धि हुई है, और कृषि मजदूरी भी पहले से अभी में 3 गुना बढ़ गयी है। यह भी जानना रोचक है कि किस तरह से महिलाए अपने पैसे का उपयोग करने लगी है जैसे कि पहले वे पैसे बेटी की शादी के लिए जमा करती थीं किन्तु अब वे उन पैसे को बच्चों मुख्यतः बेटियों की शिक्षा पर निवेश करने में इच्छुक है।" नारीसंघ की सदस्य चन्द्रमी एवं मीरा के भी बेटियां हैं और दोनों ही पढ़ने में तेज हैं, लेकिन पहले वे भी सोचती थी कि 1 से 2 साल में उनकी शादी कर देगी। हालांकि आज वे भी अपनी बच्चों की पढ़ाई को जारी कर रहे हैं और दोनों ने ही अपनी बच्चियों के विद्यालय जाने के लिए साइकिल भी खरीदी है।" नारीसंघ की एक और सदस्य ने अपने लिए भी साइकिल खरीद कर सीखी और आज आसानी से बैठकों में और ब्लाक तक जाने के लिए उसी का प्रयोग करती है।

8. सामाजिक मानदण्डों को चुनौती एवं परिवर्तन

ललिता देवी की गाँव के विकास के लिए अपनी एक सरल अवधारणा है कि गाँव का विकास सड़कों एवं बड़े बड़े मकानों के बनने से नहीं माना जा सकता बल्कि उनका मानना है कि गाँव के विकास के बारे में सोचने के पहले उनको स्वयं में परिवर्तन लाना आवश्यक है। "जब तक स्वयं में परिवर्तन नहीं होगा तब तक गाँव में भी परिवर्तन संभव है।" उनको यह महसूस होता है और 2009 में गठित हुए बनासुर नारीसंघ में जुड़ने के पीछे भी यही सोच थी।

32 वर्षीय ललिता देवी वाराणसी जिले के आराजी लाइन ब्लॉक के बैरावन ग्रामपंचायत की निवासी हैं। वो संयुक्त परिवार में निवास करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके परिवार की महिलाए आपस में एक दूसरे का बहुत ही सहयोग करती है। अतः जब ललिता देवी ने नारीसंघ की बैठकों में भाग लेने के लिए विचार बनाया, तब उनकी सास एवं घर की अन्य महिलाओं ने पूरा सहयोग किया, किन्तु घर के पुरुषों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि महिलाओं के घर के बाहर जाने से परिवार की प्रतिष्ठा एवं सम्मान पर असर पड़ेगा और वे पूरी तरह से विरोध करने लगीं।

हमेशा महिलाओं के व्यवहार से ही परिवार की प्रतिष्ठा पर जोखिम क्यों आता है, जबकि पुरुष नशा करके दुर्व्यवहार भी करते हैं? इस तरह का प्रश्न कभी समाज ने पुरुषों से नहीं किया, जबकि महिलाओं का व्यवहार हमेशा से ही जाँच के दायरे में रहा है। नारीसंघ के माध्यम से महिलाए इस तरह के समाज में व्याप्त दोहरे मापदण्डों पर प्रश्नचिन्ह लगा कर चुनौती देना चाहती थीं।

जाहिर है कि नारीसंघ नशा करने वाले पुरुषों के लिए आलोचना का लक्ष्य बन गया था। उनका कहना था कि महिलाए बैठकों के नाम पर बाहर जा करके दावतों में समोसा पकौड़ी का मजा लेती है। जब महिलाए बैठक में प्रतिभाग करने के लिए जा रही होती, तब गाँव के पुरुष कहते कि "चल दी चाट पकौड़ी, समोसा और लांगलता खाने।"



“जो महिलाएं पहले गाँव के तालाब तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, आज वे सरकारी अधिकारियों से मिलने में भी आत्मनिर्भर हो गयी है।”

— ललिता देवी
कोषाध्यक्ष, बनासुर नारीसंघ

अनेक बार तो ललिता देवी को भी अपने पति के गुस्से को भी झेलना पडा और पडोस के लोग उनको भडकाने का काम करते थे। हालांकि ललिता देवी सीखने की इच्छुक थी अतः इन अवरोधो से उनके काम में कोई अवरोध नहीं आया, अपितु अधिक लगन से गतिविधि को करने लगी।

एक बार की घटना है जब संस्था के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि अनेक ग्रामपंचायतो की महिलाओ ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम में महिलाओ ने पारंपरिक गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया। नारीसंघ के अंतर्गत ललिता देवी ने भी अन्य महिलाओ के साथ नृत्य में प्रतिभाग कर

आनन्द लिया। गाँव के किसी व्यक्ति ने उनका यह कार्यक्रम देख लिया और वह जा करके उनके पति को बढा कर बताते हुए कहा कि “वहाँ संस्था वाले महिलाओ से अश्लील नृत्य करा करके उसकी रिकार्डिंग कर रहे हैं और वे उसको विदेशो में भेज करके पैसा कमाएंगे.....।” वह ही जानता था कि उसने कैसे बताया। फिर भी वह कार्यक्रम के बारे में ग्रामीण की बातों को सुन कर उसने अपना आपा खो दिया। दहशत ग्रस्त पति ने स्वयं को फांसी लगाने का प्रयास किया, किन्तु किसी तरह से परिवार के लोग उसको रोकने में सफल हुए। ललित देवी जब कार्यक्रम से वापस घर लौटी तब उन्हें असाधारण स्थिति का सामना करना पडा। उनके पति ने उसको घर में आने से रोक दिया और उसकी कोई भी बात या याचना सुनने को तैयार नहीं था। अंततः कुछ बातचीत होने के बाद वह उन्हें अपने साथ संस्था के कार्यालय पर ले करके पहुँची, और जब संस्था के लोगो ने उसकी बातों को सुन करके उसको पूरी घटना बतायी, अंत में पूरी बात समझने के बाद वह शांत हुआ।

ललिता देवी अपने विशिष्ट अनुभव पर प्रकाश डालते हुए कहती हैं कि जब महिलाएं परंपरागत मानदण्डों का अनुपालन नहीं करती हैं तब उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पडता है। अतः यह स्पष्ट है कि बिना नियमों को चुनौती दिए परिवर्तन संभव नहीं है। ललिता देवी ने ऐसा करने की साहस किया, परिणामस्वरूप आज भी वह नारीसंघ नेतृत्वकारी सदस्य हैं। आज उनके पति में भी परिवर्तन हुआ है। अब उनको प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा आवासीय प्रशिक्षणों में भाग लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है और कभी कभी तो वे स्वयं भी उनको प्रशिक्षण स्थल तक पहुँचने में सहयोग करते हैं।

बैरवन नारीसंघ में 218 सदस्य हैं और ललिता देवी कोषाध्यक्ष हैं। नारीसंघ के माध्यम से हक एवं अधिकारों से संबंधित अनेक मुद्दों जैसे ग्रामसभा के आयोजन, मनरेगा के अंतर्गत काम एवं भुगतान एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुद्दों पर पहल कर सफलता प्राप्त की है। मनरेगा कार्यस्थल पर अब अधिक संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 45 से 52 दिन तक का काम उनको मिला है।

इसके अतिरिक्त नारीसंघ की सामाजिक मुद्दों पर कुछ अन्य उपलब्धियाँ भी रही हैं। पुरुष जुआ खेल कर एवं नशा करके समय व्यतीत करते थे। अतः नारीसंघ ने उसका निरीक्षण कर सामूहिक पहल कर दुकान बंद करा के समस्या का समाधान किया।

पहले महिलाएं अकेले बाजार नहीं जाती थी, चाहे तो वे पुरुषों के साथ जाती अथवा वे ही इनके लिए खरीदारी करके आते थे। किन्तु अब महिलाएं अकेले जा करके रोजमर्रे के आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य कीमती वस्तुओं की भी खरीदारी करने लगी हैं।

ललिता देवी का महिलाओं के जीवन में परिवर्तन का अवलोकन प्रासंगिक है, वो कहती हैं कि “पहले जो गाँव के तालाब तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, आज वे कचहरी जाने में भी सक्षम हो गयी है।”

9. समर्पित और आशावादी सुनारमती

“हम अपनी मजदूरी से जो चाहते हैं वह खरीद सकते हैं ,हम एक बकरी ,पायल या सेल फोन खरीद सकते हैं, सब कुछ संभव है।” यह कहना है बस्ती जिले की सदर ब्लाक की खदरा खिरियाहवाँ गाँव की रहने वाली सुनारमती का। 44 वर्ष की सुनारमती सदभावना नारी संघ की अध्यक्ष हैं, जिसमें 166 महिलायें सदस्य हैं। नारी संघ के गठन से महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है।

इसके अलावा, महिलाओं को सम्मान मिलने लगा जिसकी वे हकदार थीं। महिलाये घर के भीतर काम करती हैं, जबकि पुरुष बाहर काम करते हैं, अब यह पारंपरिक मानसिकता बदल रही है। यह परिवर्तन क्रमिक था और संभव था, परिवार के सदस्यों के विरोध के बावजूद महिलायें आगे कदम बढ़ाती रही।

शुरुआती दिनों में अपने परिवार की स्थिति बताते हुए सुनारमती कहती हैं कि, “मेरे पति और ससुर नारी संघ में भागीदारी करने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि मैं। कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने मुझे हतोत्साहित किया ,लेकिन मेरे बच्चे बहुत सहयोगी हैं। वे मेरी मदद करते इसीलिए मैं अपना काम जल्दी खत्म कर पाती थी और नारी संघ के बैठक में भागीदारी कर पाती थी।”



अन्य गाँवों के विपरीत इस गाँव में लोग पहले से ही मनरेगा से परिचित थे क्योंकि इसमें से कुछ लोग हाल ही में रोजगार कार्यक्रम के अर्न्तगत काम कर चुके थे। यद्यपि वे मजदूरी भुगतान के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। सुनारमती ने शुरुआती बैठकों में ,जब नारी संघ के गठन की प्रक्रिया बस शुरु ही हुआ था, एक बैठक में इस समस्या को रखा। संस्था के कार्यकर्ताओं से हेल्प लाइन नम्बर की जानकारी लेने के बाद महिलाओं ने इसका इस्तेमाल किया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब एक सप्ताह के अन्दर उनको बकाया राशि मिल गया। इस अनुभव से संस्था और महिलाओं को संगठित करने का उनके मिशन के प्रति लोगों का विश्वास बन गया। शुरु में 35 महिलाये नारी संघ से जुड़ी और वर्तमान में यह सदस्यता बढ़कर 166 हो गयी है।

“संस्था द्वारा प्रशिक्षण और सहयोग मिलने के कारण हम अच्छी तरह से जागरूक हो गये इसीलिए हम अपने अधिकारों के लिए दावा कर सकते हैं।”

— सुनारमती
अध्यक्ष, सदभावना नारी संघ

नारी संघ का गठन मार्च 2010 में किया गया, गठन के तुरंत बाद चुनाव का समय आ गया था। पंचायत राज जागरूकता अभियान के लिए , संस्था के साथ-साथ नारी संघ ने भी ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को ग्राम प्रधान के लिए चंनाव करने की अपील की जो वास्तव में गाँववालों के बेहतरी के लिए काम करे। पूर्व प्रधान को डर था कि अभियान के बाद ,उनके बारे में जनता की राय बदल सकती है इसलिए नारी संघ के सदस्यों को धमकाने का प्रयास किया। सुनारमती

कहती हैं कि, “ उनके बेटे ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और हमें मारने की भी धमकी दिया। ” फिर भी नारी संघ के सदस्यों को डर नहीं लगा ,बल्कि चुनाव के समय तक उन्होंने अपना अभियान जारी रखा।

कोटेदार के बारे में महिलाओं के पास कई शिकायतें थीं। अन्य बातों के अलावा , अतिरिक्त पैसा लेकर भी कभी पूरा राशन नहीं देता था। नारी संघ ने एक बैठक में इस समस्या पर चर्चा किया और अपने सामूहिक शक्ति का उपयोग करके उसके अन्याय को रोकने का फैसला किया। उन्होंने उसके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने का फैसला किया जहाँ से वह वितरण के लिए पूरा राशन लाता है। ” निर्णय के अनुसार हम उसके घर गये और उचित मात्रा व दर में अनाज वितरण करने के बारे में पूछा। हमने उसे अतिरिक्त पैसा नहीं दिया इसीलिए उसने हमें अनाज देने से इन्कार कर दिया। इसलिए हम वहीं पर बैठ गये और मैंने कोटेदार के खिलाफ शिकायत करने के लिए बी0डी0ओ0 को फोन किया। बी0डी0ओ0 ने तुरंत सचिव को मामले को देखने के लिए कहा, पंचायत सचिव मौके पर पहुँचकर कोटेदार को चेतावनी दिया। उस दिन से हमें बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के पूरा राशन मिलने लगा।”

सुनारमती सड़क निर्माण के लिए, नारी संघ द्वारा किये गये पहल के लिए सबसे अधिक खुश है। वह कहती है कि, “जो पिछले 25 सालों से नहीं हो पाया उसको हमने एक साल में कर दिखाया। हम सड़क बनवाने में सक्षम हो गये थे जिसका लाभ गाँव के हर किसी को मिल रहा है।” मुख्य बात यह है कि सड़क ठीक ढंग से बना ही नहीं था। विशेषकर बरसात के मौसम में तो यह गाँव वालों के लिए बाधा बन जाता था। किसी भी स्थानीय नेता को इसकी परवाह नहीं थी। नारी संघ की 23 से भी अधिक महिलाओं ने सीधे सी0डी0ओ0 से सम्पर्क किया और अपना आवेदन देते हुए सड़क निर्माण करवाने का अनुरोध किया। सी0डी0ओ0 ने बहुत सकारात्मक जबाव दिया। तुरंत बी0डी0ओ0 को आदेश दिया और महिलाओं से बोले कि यदि अगले दिन काम नहीं शुरू होता है तो इस मामले में वे लोग पुनः मिल सकती हैं। समतलीकरण का काम तुरंत शुरू कर दिया गया। बाद में नारी संघ ने मनरेगा के धन से स्थायी सड़क बनवाने का प्रस्ताव रखा और प्रधान इस काम को सम्भावित कार्ययोजना में शामिल कर लिया।

इससे पहले प्रधान और पंचायत सचिव, मनरेगा के अर्न्तगत उनके काम के मांग के प्रति बहरे हो गये थे। सुनारमती का कहना है कि, “ अब आप किसी भी कार्यस्थल पर पुरुषों के अलावा महिलाओं को काम करते देख सकते हैं। क्योंकि संस्था द्वारा दिये गये प्रशिक्षण व सहयोग के कारण हम अच्छी तरह से जागरूक बन गये हैं और इसीलिए अपने अधिकारों को पाने के लिए दावा कर सकते हैं। ” अब ना तो सरकारी कर्मचारी और ना ही नेता महिलाओं को गुमराह कर सकते हैं। बल्कि महिलाओं में काफी विश्वास है और अपने हकदारी के बारे में जागरूक हो गये हैं। वे पंचायत सचिव को बताते हुए कहती है कि, “अगर हमारे जाब कार्ड में कार्यदिवस ठीक से नहीं अपडेट करेगे और अपना काम उचित ढंग से नहीं करेगे तो हम आपका तबादला करवा देंगे। ”

“जब हम ब्लाक पर मनरेगा में काम पाने के लिए आवेदन देने जा रहे थे तो इस अवसर पर कमलावती भी नारी संघ से जुड़ गयी। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और घर लौटने पर उसकी पिटाई भी किया। तीन दिनों के भीतर हमें हमारे आवेदन का सकारात्मक जबाव मिला। जब रोजगार सेवक ने हमें काम के बारे में बताया तो कमलावती के पति को अपने व्यवहार पर बहुत बुरा लगा। अब वह उसे कभी नहीं रोकता और हमसे साथ लेने के लिए कहता है।”

10. जागरूक महिलाएं

महिलाओ को घर के बाहर कदम रखने से उनका डर ही उन्हें रोकता है क्योंकि बचपन से ही उन्हें समाज के नियम-कानूनों एवं रीतिरिवाजों को थोपा जाता रहा है। वे अनेक तरह के भय के साथ जीवनयापन करने के लिए उसी के अनुकूल हो गयी हैं, इसलिए उन्हें अपनी क्षमता पर भी संदेह होने लगा है। परिवार एवं समाज सदैव ही महिलाओ के आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास करते रहते हैं। शोभादेवी के परिवार का ही उदाहरण लेते हैं, उनकी सास चेतावनी देते हुए कड़े शब्दों में कहा “जब पूरब और पश्चिम दिशा में अंतर नहीं कर सकती तो और आगे कैसे कुछ करोगी? हम लोग इसमें सहयोग नहीं करेगे और अगर कुछ ऊँच नीच हो जाएगा, तब घर आने की कोई जरूरत नहीं है।” फिर भी शोभा देवी उस डर को भूल करके बैठक में आने लगी और आज वे नेतृत्वकर्ता के रूप में जानी जाती हैं।

42 वर्षीय शोभादेवी बस्ती जिले के बस्ती सदर ब्लाक के सोनबरसा ग्रामपंचायत की रहने वाली हैं। उनके 5 बच्चे हैं। 2009 में गठित हुए नारीसंघ की वे अध्यक्ष हैं। नारीसंघ के गठन के प्रारंभ में नारीसंघ के कुल 15 सदस्य ही थे, किन्तु आज यह संख्या 183 हो गयी है।

इस गाँव में नारीसंघ ने ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून के अंतर्गत काम सुरक्षित करने का प्रयास उल्लेखनीय रहा है। पहले तो वे कानून के बारे में ही नहीं जानती थी तब जॉबकार्ड कैसे जानती। “संस्था की कार्यकर्ता निशा बहन ने ही हम लोगो को प्रधान एवं रोजगारसेवक के पास जा करके जॉबकार्ड आवेदन देने के लिए बताया, हालांकि जब हम लोग पहली बार इस सिलसिले में उनसे



मिले तब उन्होंने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है।" प्रधान ने महिलाओ को चुनौती भरे शब्दों में कहा कि यदि आप लोगों का जॉबकार्ड बन जाएगा "तब मेरी हथेली में बाल जम जाएगा"।

महिलाओं ने उनकी चुनौती स्वीकार कर प्रयास करके जॉबकार्ड बनवाया और नारीसंघ की यही पहली सफलता थी। जाबकार्ड बनने के बाद उन लोगों ने काम की मांग भी की और काम तो मिला किन्तु उसकी पूरी मजदूरी न मिल सकी।

मजदूरी न मिलने पर महिलाओं ने मनरेगा हेल्पलाइन का प्रयोग किया और परिणामस्वरूप 1 सप्ताह में ही मजदूरी का भुगतान हो गया। महिलाओं को हर चरण पर जॉबकार्ड बनवाने से ले कर के मजदूरी प्राप्त करने तक संघर्ष करना पडा, और इसका स्थायी प्रभाव भी पडा। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास मजबूत हुआ और साथ ही संगठन का महत्व एवं उपलब्धियों भी दिखने लगी और परिणामस्वरूप नारीसंघ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुयी।

शोभादेवी बताती है कि महिलाएं आभास करने लगी कि "नारीसंघ से हम लोगों को बहुत सहायता मिल सकती है और जल्दी ही हम लोग सरकारी योजनाओं का लाभ भी संगठन के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।"

जब महिलाओं को मनरेगा में काम मिला, तब वहाँ पर भी महिलाओं को जेण्डर से संबंधित समस्याओं को सामना करना पडा। पुरुष खुदाई करते और महिलाओं को उठा करके फेंकना पडता। महिलाओं ने अपनी टोली बना करके आपस में ही सारा काम करने लगी। शोभादेवी कहती है कि "पहले से अब की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। हम लोग अपने खाते में अपनी मजदूरी की बचत भी कर लेते हैं, जिससे की उनमें आर्थिक सुरक्षा की भावना का विकास हुआ है।" अब हम लोग अपनी आमदनी को अपनी मर्जी से खर्च भी कर लेते हैं जैसे कि उन्होंने बचत के पैसे से बकरी पालन किया और मोबाइल भी खरीदी।

मनरेगा में काम करने के परिणामस्वरूप ही कृषि मजदूरी में भी वृद्धि हुई। महिलाओं को जिन कामों के लिए पहले 50 से 60 रुपए मिलती थी आज उन्ही कामों की मजदूरी 100 रुपए मिलने लगी है।"अभी तो 100 रुपए मिलने लगे हैं लेकिन अब हम लोग मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी के बराबर ही कृषि मजदूरी की भी मांग करते हैं।"

महिलाओं की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है।" पहले हम लोग अपने गाँव की बाजार में भी अकेले नहीं जा पाते थे, किन्तु अब तो दूसरे जिले जहाँ नारीसंघ है, वहाँ पर भी अकेले जाने में सक्षम हो गए हैं।" शोभादेवी यह बताते हुए गर्व महसूस करती है कि उन्होंने फैजाबाद, मऊ एवं महाराजगंज जिले में जा करके अनेक नारीसंघ की बहनो से मिल चुकी है।

नारीसंघ सिर्फ महिलाओं के भले एवं विकास के लिए काम न करके गाँव के विकास के लिए भी काम करने का प्रयास करने लगी है। नारीसंघ ने सफल प्रयास गाँव में लगभग 32 साल से अपेक्षित सड़क का निर्माण हुआ है। शोभादेवी इसका श्रेय नारीसंघ की चार सदस्य मुनक्का, राजकुमारी, शकुन्तला एवं सरोज को देती है। वह बताती है कि "इन्ही चारों सदस्यों ने उनके पति को अपनी जमीन सड़क निर्माण के लिए देने के लिए राजी कराया, अन्यथा यह संभव नहीं था और 32 सालों की तरह ही जाने कब तक यह पुरवा सड़को से अछूता ही रह जाता।"

परिवार के सदस्यों विशेषतौर पर पति के व्यवहार में बहुत परिवर्तन हुआ है। अब तो नारीसंघ की पहल को स्थानीय अखबारों में भी महत्वपूर्ण स्थान मिलने लगा है। वो बताती है कि " जब मेरा नाम और फोटो अखबार में छपती है, तो यह देख करके मेरे पति बहुत खुश होते हैं और उन्हे मेरे ऊपर गर्व भी महसूस होता है।" अब तो वे कहते हैं कि जहाँ भी जाना हो अब तो तुम सब जगह जा सकती हैं। अब तो मैं कभी भी नहीं रोकूंगा क्योंकि तुम बहुत ही समझदार हो।

"जब अखबार में मेरी फोटो या नाम छपता है तो वह देख करके मेरे पति गर्व महसूस करते हैं।"

— शोभा देवी
अध्यक्ष, सद्भावना नारीसंघ

11. चूल्हा चौके से परे

स्वतंत्रता और स्वायत्तता ही स्वच्छंदता का प्रतीक है। लेकिन महिलाओं के मामले में इसका मतलब अलग है, स्वच्छंद महिला को 'बेशर्म' और 'ढीला' महिला कहा जाता है क्योंकि महिलाओं को अपने घरों तक ही सीमित रहने की उम्मीद की जाती है। सावित्री देवी को कई मौकों पर ऐसे भयानक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है, जब उन्होंने नारी संघ के कार्य के लिए चारों तरफ जाना शुरू किया था।

मुखिया होने के नाते, परिवार के सदस्यों के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन गाँव वालों ने उनके पैर खींचने की कोशिश किया। फिर भी, उनको काम की आवश्यकता थी और वह जानती थी कि मनरेगा के अर्न्तगत इसका आश्वासन दिया गया है। इसलिए उन्होंने नारी संघ की महिलाओं को रोजगार गारन्टी कानून के तहत काम पाने के लिए एकजुट किया।

35 वर्ष की सावित्री देवी महाराजगंज जिले में, सदर ब्लॉक की करमहॉ गाँव की निवासी है। वह विवाहित है, इनके तीन बच्चे हैं और परिवार की मुख्य कमाऊ सदस्य है।



जब नारी संघ के गठन के लिए महिलाये एकजुट होने लगी तो मुश्किल से 15 से 20 महिलाये आगे आयी, सावित्री देवी उनमें से एक है। उन्हें एकजुट होने की आवश्यकता पसंद आयी और उन्हें इसका एहसास था कि महिलाओं की स्थिति सुधारने में इससे मदद मिलेगी। वर्तमान में करमहा नारी संघ में 300 महिलायें सदस्य के रूप में जुड़ी हुई हैं।

गरीब व भूमिहीन लोगों का, अमीर जमींदारों के ऊपर निर्भरता ही उन्हें शोषण के लिए संवेदनशील बनाता है। सावित्री देवी ने हाशिए पर रहने वालों अन्य लोगों की इस लाचारी को अपने सुमदाय के साथ चर्चा किया। इसीलिए वह मनरेगा के तहत काम पाने के लिए अधिक उत्सुक थे। वह कहती है कि, "हमारे गाँव का दंबग जमींदार हमारे ऊपर था। चूंकि हम उसपर निर्भर थे इसलिए उसके नियमों का पालन करते थे। लेकिन अब नरेगा विकल्प के रूप में उपलब्ध है और इससे हमे आत्मविश्वास भी मिला है। सावित्री देवी और अन्य लोगों को सम्मान के साथ काम हासिल हुआ।" अब हमें मनरेगा के तहत आसानी से काम मिल जाता है और अपने आमदनी पर हमारा पूरा नियंत्रण है। इस समुदाय में एक नये प्रधान का चुनाव करने की उपलब्धि हासिल किया जो उन लोगों का समर्थन करता है। वह मानती है कि, "नारी संघ के वजह से ही यह सब संभव था।

"अब हमें आसानी से मनरेगा के तहत काम मिल जाता है और अपने पूरे आमदनी पर हमारा नियंत्रण है।"

— सावित्री देवी,
अध्यक्ष, करमहा नारी संघ

सावित्री देवी एक अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक व जिले स्तर पर महिलाओं के मृद्दों की पैरवी करती है। नारी संघ की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को बताते हुए सावित्री देवी कहती है कि, "धरौली और बिसवा गाँव की नारी संघ की महिलायें बैंक में सहायता प्राप्त ऋण के लिए आवेदन दिया था लेकिन प्रबन्धक उनके प्रस्ताव को पास करने से इन्कार कर रहा था। मैं उनसे मिली और बताया कि हम मुद्दी भर महिलायें नहीं हैं हमारे पीछे चार हजार महिलायें हैं। सावित्री देवी ने जिला स्तर पर नारी संघ का नेतृत्व किया और जिला कलेक्टर के सामने कार्रवाई के लिए अपील किया। महिलाओं के पहुँच को देखते हुए प्रबंधक ने तुरंत मंजूरी दे दी। अभी तक एक और घटना में बी0डी0ओ0 के यहाँ बकाया मजदूरी के लिये महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया।

"अभी तक मैं ज्यादा नहीं जानती थी और काम के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती थी, अब मैं आसानी से उन सभी कामों को कर सकती हूँ।" सावित्री देवी ने केवल लोगो के क्षुद्र टिप्पणी को नजरअंदाज कर क्षमता और विश्वास अर्जित किया है। अब तो उनके समुदाय के पुरुष भी मानते हैं कि महिलाओं का पहल सभी के लिए लाभकारी है। इसलिए उनकी टिप्पणी और आलोचना बहुत पहले ही बंद हो गयी।

इन उपलब्धियों को दर्शाते हुए वह कहती है कि, “हमारी स्थिति के बेहतरी के लिए मैं अब खुशी महसूस कर रही हूँ, पहले हम अधिकारियों के सामने खड़े होने से डरते थे पर अब उन्हें, उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं।”

नारी संघ की महिलाओं में परिवर्तन देखकर वह बहुत खुश है। महिलायें जो अभी तक चुल्हे चौके से बंधी थी, अब वे अधिक जागरूक हो गयी हैं और पंचायत के कामकाज में भी भाग लेने लगी हैं। अध्यक्ष कहती हैं कि, अब वे अधिक जागरूक व सहयोगी हो गयी हैं। अपने अधिकारों का दावा करने के लिए एक साथ हो गये हैं लेकिन अब हम किसी भी व्यथित महिला, चाहे वह हमारे नारी संघ की सदस्य हो या नहीं, उसके पीछे खड़े होने के लिए तैयार हैं।”

12. पहचान के लिए खोज

“तुम औरत हो और औरत की तरह ही रहो।” यही बात पिछले कई सालों से हमेशा ही सुनती रही हूँ, यही मुझे आत्मसात करने के लिए कहा गया। मेरे अभिभावक मुझे वे सभी काम करने से मना करते, जो उन्हें लड़कों का काम लगता। क्यों? क्या लड़की के रूप मेरा जन्म लेना पाप था?” महाराजगंज जिले के सदर ब्लॉक की सिसवाबावू ग्रामपंचायत की 35 वर्षीय पूजा देवी पूछती हैं।

लड़कियों के लिए समाज में करने एवं प्रतिबंधित कामों की सूची बहुत ही लम्बी है। लेकिन प्रतिबन्धों के बावजूद भी पूजा देवी ने पढाई करने एवं काम करने का विचार बना कर आग्रह भी किया। पूजा देवी जो महसूस करती हैं कि माता पिता को बच्चों के साथ सहयोग एवं सकारात्मक भूमिका में होना चाहिए, वे बताती हैं कि “मैं बहुत सी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो कि काम करके अपने परिवार के खर्च में हाथ बंटाना चाहती हैं, किन्तु परिवार के सहयोग के अभाव में वे ऐसा नहीं कर पाती। वे अपने परिवार के विरुद्ध भी जा करके कोई काम नहीं करना चाहती।”



उन्होंने कक्षा आठ तक ही पढाई की क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वे घरेलू काम भी सीखें। उन्होंने पूजा से कहा कि “शादी के बाद तुम्हारी स्कूल की पढाई ही काम नहीं आएगी, घरेलू काम आना उससे अधिक आवश्यक है।” 16 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी हो गयी और उनकी आगे पढने और काम करने की इच्छा दबी ही रह गयी।

“मेरे अभिभावक मुझे ऐसे सभी काम करने से मना करते, जो उनको लगता कि ये सिर्फ लड़कों का ही काम है, क्यों? क्या लड़की का जन्म लेना ही गुनाह है।”

—पूजा देवी
अध्यक्ष, नारीमहासंघ

“वास्तव में, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती थी।” लेकिन यह सब बताने और करने के लिए अपने अभिभावकों के समक्ष बहुत ही छोटी थी। हालांकि उन्होंने अनुकूल स्थितियों में भी अपनी इच्छाशक्ति को मरने नहीं दिया, अपितु शादी के कुछ साल बाद सही अवसर देख कर उन्होंने अपना ब्यूटीपार्लर खोल करके बाहर काम करने की इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया। वो बताती हैं कि “मैंने अपने घरेलू काम के साथ ही बच्चों के स्कूल जाने एवं पति के काम पर चले जाने के बाद बाहर जा करके काम करने लगी।” यहाँ पर भी उद्यम के प्रारम्भ में समस्याओं का सामना करना पडा,

जब तक की घर के लोगो ने मेरे काम को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लिया।

समय बीतने के साथ ही उन्होंने नये-नये मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की एवं सीख भी मिली और इसी दौरान सृष्टि सेवा संस्थान के संपर्क में आयी। संस्था के द्वारा गाँव ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत नारीसंघ के गठन की प्रक्रिया चलायी जा रही थी। मेरे लिए यह स्वर्णिम अवसर सिद्ध हुआ और इसके माध्यम से कुछ स्थायी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ जैसा कि वे चाहती थी। “उन्होंने मुझे बताया कि संगठन के माध्यम से ही महिलाएं अपने हक एवं अधिकारों को समझ करके उसको प्राप्त करने का प्रयास कर सकती हैं, इससे उन लोगो की स्थिति में भी सुधार होगा और यह सब समझने के बाद मैं भी संगठन से जुड़ गयी।” यह उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। मैंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं बैठकों में

प्रतिभाग करके अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त की। वास्तव में नारीसंघ अब हम लोगो का अपना मंच हो गया जहाँ बैठ कर हम अपनी बातों पर खुल करके एक दूसरे से चर्चा करते हैं।”

पूजा देवी उत्सुकता एवं जोश के साथ इस काम को करने में लग गयी और काम करते हुए वे नारीसंघ की अध्यक्ष चुनी गयी। उनके व्यक्तित्व में नेतृत्वकर्ता के गुणों के विद्यमान होने के कारण ही वे नारी महासंघ की भी अध्यक्ष चुनी गयी।” मैं अगुआ के रूप में महिलाओं के मुद्दों को ब्लॉक एवं जिले स्तर तक उठाने लगी। मैं अधिकारों से जुड़े संघर्षों में सक्रिय बनी रही।” पूजा देवी ने नारीसंघ में भागीदारी करके मुद्दों पर पहल करने के दौरान ही उनको अपने व्यक्तित्व में नेतृत्वक्षमता का एहसास हुआ।

मनरेगा के अंतर्गत काम सुनिश्चित करते हुए 100 दिन का काम प्राप्त करने के लिए मनरेगा पर्सपेक्टिव प्लान बनाया, जिसके अंतर्गत गाँव के विकास से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी। इसी दिशा में नारीसंघ के प्रयास से गाँव स्तर पर विकास दल का गठन किया गया, विकास दल में गाँव के जागरूक लोग कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी जो कि स्वैच्छिक रूप से गाँव में विकास के कार्यों को करने के इच्छुक हो और नारीसंघ के सदस्यों को मिला करके 10-15 सदस्यीय ही विकास दल कहलाता है। बाद में पर्सपेक्टिव प्लान को ग्रामसभा की बैठक में प्रस्तुत करके चर्चा के उपरांत स्वीकार कर लिया गया। मनरेगा के अंतर्गत पूजा देवी अपने गाँव में मेट के रूप में भी काम करती हैं।

पूजा देवी समाज में लोगों की महिलाओं के प्रति सोच को बदलना चाहती थी और यह नारीसंघ के साथ ही मिल करके करने में सक्षम थी। उनका मानना है कि महिलाएँ किसी भी परिपेक्ष्य में समाज के अन्य लोगों से कम या कमजोर नहीं हैं और वे अन्य लोगों को भी इस बात का एहसास कराना चाहती हैं। अभी हाल ही में उनको एन0एफ0आई0, नई दिल्ली से फेलोशिप भी प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से वो अपने काम का विस्तार कर सकेंगी।

13. एक आज्ञाकारी बहू से एक नेतृत्वकर्ता तक के सफर की कहानी

37 वर्षीय गौड़ समुदाय की माया देवी मऊ जिले में, घोसी ब्लॉक में, गौराडीह गाँव की निवासी हैं। उन्होंने साक्षरता केन्द्र के माध्यम से कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर ली है, जिसको नारी संघ पहल के एक भाग के रूप में शुरू किया गया। वह विवाहित व सात बच्चों की माँ हैं और सीता नारी संघ की अध्यक्ष हैं जिसका गठन दिसम्बर 2007 में किया गया। वर्तमान में संगठन के साथ 157 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं।

माया देवी जब 16 वर्ष की थी तभी उनकी शादी हो गयी थी। उनकी सास ने उनसे एक आज्ञाकारी और अच्छी बहू बनने का कहा जिसका वो पालन करती रहीं। “महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, हर समय घूँघट में रहना चाहिए, उसे किसी के सामने नहीं आना चाहिए और पुरुषों के किसी भी मामले को जानने या प्रतिक्रिया करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।” यह सब आदर्श बहू के सिद्धान्त हैं जो माया देवी की तरह अधिकांश महिलाएँ शादी के बाद करती हैं। उन्हें खाना बनाने और परिवार के सदस्यों की देखभाल करने का काम सौंपा गया था। बाद में उन्होंने मजदूरी का काम करना भी शुरू कर दिया है।



समाजीकरण में अंतर के परिणाम के रूप में महिलाओं को लगता है कि वह अयोग्य हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में जिन विशेष कार्यों को पुरुष आसानी से संभाल रहे हैं, उसके लिए वह संकोची हो जाती हैं। माया देवी भी इसका अपवाद नहीं थीं। “मैं सोचती थी कि स्वयं से कार्यालयों में जाने और अधिकारियों से बात करने के लिए अपर्याप्त हूँ। मेरा मानना था कि केवल पुरुष ही ऐसे कार्यों के लिए सक्षम होते हैं।” लेकिन अब उनकी राय बदल गयी है, क्योंकि उन्हें अनुभव हुआ कि वह क्या कर सकती हैं। वह यह मानते हुए कहती हैं कि, “मैं गलत थी। महिलाएँ समान रूप से सक्षम हैं, किन्तु जानकारी और अवसर से ही सारे फर्क पड़ते हैं।”

एक कृषि मजदूर होने के नाते, माया देवी के जैसी महिलाये काम के लिए स्थानीय जमींदार के ऊपर ही निर्भर रहती है। " जब हमारे हाथ में कोई काम नहीं था , हम बाबू साहब के पास जाते और उनसे कुछ काम देने का अनुरोध करते। " मनरेगा के लागू होने के बाद यह निर्भरता कुछ कम हो गयी थी। " अब हमें मनरेगा के तहत काम मिल रहा है। अपनी आमदनी पर हमारी अच्छी तरह से नियंत्रण है। उसे हम अपने लिए और परिवार के लिए खर्च कर सकते है। "

"अब लोगों के पास जब पैसा हो तब राशन खरीद सकते हैं, यह एक बड़ी राहत है।"

– माया देवी
अध्यक्ष, सीता नारी संघ

लेकिन काम मिलने के बाद भी समस्यायें खत्म नहीं हुई थी। एक बार हम लोगों ने मनरेगा के अर्न्तगत 20 दिन तक काम किया , लेकिन हमारी मजदूरी का भुगतान समय से नहीं किया गया। चूँकि मेरे हाथ में पैसा नहीं था, मैं राशन नहीं ले सकती थी, राशन की दुकान महीने में दो दिन ही खुलता था और हमसे उन्हीं दिनों में राशन लेने की उम्मीद की जाती थी। अगर कोई बाद में राशन लेने जाता था तो उसे नहीं मिल सकता था।"

"जैसे ही मुझे मजदूरी मिली मैं कोटे की दुकान पर गयी। लेकिन कोटेदार ने कहा कोटा खत्म हो गया है अब अगले महीने ही मिल पायेगा। उसने मेरे नुकसान के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया , उसने कहा जब दुकान खुली थी मुझे तभी आना चाहिए था।"

अक्सर बहुत से लोगों को पी0डी0एस0 के नियमों के बारे में पता नहीं है इसीलिए कोटेदार अपने अनुसार बनायी गयी व्यवस्था लोगो पर थोपता था। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने कार्ड धारकों के लिए , जो माया देवी की तरह मुश्किल से किसी तरह का नकद बचत करते है। परंतु कोटेदार को इससे कोई मतलब नहीं था। माया देवी परेशान थी, लेकिन वह चुप नहीं थी।

नारी संघ की बैठक में अपनी समस्या रखने के बाद, उन्होंने राशन की दुकान की कार्य प्रणाली जानने के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन डाला। वह जाना चाहती थी कि दुकान महीने में कितने दिन खुलना चाहिए और उचित दर क्या है व उनके परिवार के लिए कितने मात्रा में अनाज व मिट्टी का तेल मिलना चाहिए।

आमतौर पर जैसा होता है ,सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग से सम्बन्धित अधिकारी का जबाव नहीं मिला लेकिन उन्होंने ,उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। उसने कोटेदार को भी बुलाया ,जिसे यकीन था कि वह उसके खिलाफ कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं होगी। अधिकारी कोटेदार के पक्ष में था और उसने कार्रवाई हेतु पहल करने के लिए माया देवी का चेतावनी देते हुए कहा कि वह उनके कार्ड को निरस्त कर सकते है और कार्रवाई के लिए जेल भी भेज सकते है। जब वह उन्हें गुमराह करने और धमकी देने की कोशिश कर रहा था तो माया देवी चुप थी। उन्हें पता था कि वह क्या कर रही थी और अच्छी तरह से उसे बेनकाब करने के लिए जानकारी लिया गया था। उन्होंने अपने आवेदन के लिए एक औपचारिक जबाव प्राप्त करने के लिए जोर देते हुए कहा कि, "आप मुझे आपेक्षित जानकारी देंगे या नहीं देंगे? यदि आप नहीं देते है ,तो मेरे पास और विकल्प है ,उनका इस्तेमाल करने पर आप मेरे घर पर आकर जानकारी देंगे।" उन्होंने कहा कि उन्हे जिला अधिकारी के पास जाना होगा और नारी संघ के गतिविधियों के बारे में बताना होगा। उनसे यह सुनने के बाद उसने अपनी प्रतिक्रिया बदल दिया और निर्धारित समय में सूचना भेजने का वादा किया।

माया देवी ने 20 दिन में जानकारी प्राप्त किया। इस जानकारी के आधार पर वह कोटेदार की महीने में दो दिन दुकान खोलने के अभ्यास को चुनौती दिया। वह हर दिन दुकान खोलने लगा था। लोगों को पर्याप्त राशन मिलना शुरू हो गया। माया देवी का कहना कि, अब लोगों के पास जब पैसा हो तब राशन खरीद सकते है, यह एक बड़ी राहत है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इसका श्रेय माया देवी व संगठन को जाता है।

14. नारीसंघ की नेतृत्वकर्ता पंचायत प्रतिनिधि के रूप में

प्रभावती देवी सद्भावना नारीसंघ ओरई की अध्यक्ष है और साथ ही वे निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि भी हैं और उनको अपने कार्य एवं जिम्मेदारी पर गर्व है। उनकी संयमित अभिव्यक्ति में भी गहराई दिखाई देती है।

42 वर्षीय प्रभावती देवी बस्ती जिले के सदर ब्लाक के ओरई ग्रामपंचायत के नन्दपुर गाँव की निवासी हैं। उनके 5 बच्चे हैं। कुछ साल पहले जब उनके पति का निधन हो गया, तब उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। विधवा के लिए संयुक्त परिवार में जीवनयापन करना आसान नहीं था। परिवार के सदस्यों की अनेक प्रताड़नाओं का शिकार होने के बाद ही उन्होंने अपने बच्चों के साथ परिवार से अलग रहने का निर्णय लिया और इस दौरान अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए वे अपने परिवार का जीवनयापन करने में सक्षम हुईं। एकल महिला के जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का सामना भी उन्होंने हिम्मत के साथ सामना किया। इन सभी समस्याओं के बावजूद भी उनका जोश एवं जज्बा कम नहीं हुआ अपितु वे जीवन में नयी ऊँचाइयों को छूती रहीं।

सद्भावना नारीसंघ ओरई का गठन मार्च 2010 में हुआ। प्रभावती देवी प्रारम्भ से ही इसकी सदस्य हैं। यहाँ पर ही उन्होंने समझा एवं जाना कि उनके अधिकार क्या हैं और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में नारीसंघ के 160 सदस्य हैं और वे सदस्यों को मुद्दों की पहचान की पहचान करके पहल करने के लिए प्रेरित भी करती हैं।



नारीसंघ के गठन के पश्चात् ही वे पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य के पद के लिए खड़ी हुईं और निर्विरोध निर्वाचित हुईं। प्रभावती देवी बताती हैं कि चुनाव के दौरान और आज भी नारीसंघ की बहनो ने उनका पूरा सहयोग किया और आज जब वे निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में तो नारीसंघ की बहनो के हक एवं अधिकारों को तक पहुँचने में सहायता भी करती हैं।

“एक बार प्रधान ने बताया कि जिन महिलाओं के पति पहले से ही मनरेगा में काम कर रहे हैं, उन्हीं के घर की महिलाओं को काम मिल सकता है।”

— प्रभावती देवी
अध्यक्ष, सद्भावना नारीसंघ ओरई

नारीसंघ की अर्जित अनेक सफलताओं को बताते हुए प्रभावती देवी गर्व महसूस करती हैं। वो बताती हैं कि “हम लोग अनेक परिवर्तन लाने में सक्षम हुए।” सबसे महत्वपूर्ण घटना बताते हुए कहती हैं कि महिलाओं को मनरेगा में रोजगार मिला और वे बैंक में खाता खुलवाने के लिए गयीं, वहाँ बैंक मैनेजर महिलाओं से बिना रिश्ते लिए खाता खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। किन्तु नारीसंघ के प्रयासों एवं जानकारी के कारण वे अपना खाता खुलवाने में सफल हुईं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मनरेगा में काम करने के बाद से महिलाओं ने कृषि कार्यों से संबंधित मजदूरी को भी बढ़ाने में

सफलता प्राप्त की। प्रभावती देवी इन सभी सफलताओं का श्रेय नारीसंघ को देते हुए कहती हैं कि इसके बिना कोई भी विकास अथवा परिवर्तन संभव नहीं था।

प्रारंभ में मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कामों में लैंगिक (जेण्डर) भेदभाव होता था। “बहुत ही कम महिलाओं को मनरेगा में काम मिलता, प्रधान एवं रोजगार सेवक से काम मांगने पर वे कहते कि महिलाएँ भारी एवं तकनीकी काम जैसे खडपजा लगाना, फावड़ा चलाना आदि नहीं कर पाएंगी।”

यह तो पक्षपात का एक ही पहलू था और दूसरी ओर प्रभावती देवी जैसी एकल महिलाओं को मनरेगा में जॉबकार्ड बनवाना ही कठिन था। अनेक चुनौतियों का सामना करके वे बावजूद जॉबकार्ड बनवाने से तो सफल रहीं किन्तु काम मिलने की कोई भी उम्मीद ही नहीं नजर आ रही थी। काम का आवेदन देने पर कहा जाता कि एकल महिलाओं को मनरेगा में काम का कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रभावती देवी याद करते हुए प्रधान का वाक्य दोहराती हैं “सिर्फ उन्हीं महिलाओं को काम मिलेगा, जिनके पति पहले से

ही मनरेगा में काम कर रहे हैं।" उसको इसकी परवाह ही नहीं थी कि एकल महिलाएं इस स्थिति में क्या कर सकती हैं। नारीसंघ ने लोगों के दोनों ही महिला विरोधी विश्वासों को चुनौती देते हुए मनरेगा में काम किया। महिलाओं ने टोली बना करके गड़ढा खोदने, मिट्टी फेंकने एवं खण्डजा बनाने का काम भी सफलता पूर्वक सम्पन्न किया। महिलाओं ने परंपरागत सोच को चुनौती देते हुए सफलतापूर्वक काम करने एवं उसकी पुरुषों के समान ही मजदूरी मिलने से बहुत खुश हुईं और आगे बढ़ने का हौसला भी मिला। जब महिलाओं ने सभी काम कर दिए, तब से प्रधान या अन्य कोई भी पुरुष उनकी क्षमता को चुनौती नहीं देता।

काम के अधिकार के लिए काम करते हुए ही महिलाओं ने असमान कृषि मजदूरी के मुद्दे पर भी पहल की। सामान्यतः लोगों की यह धारणा रही है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर मेहनत का काम नहीं कर सकतीं और इसलिए उनके काम को महिलाओं के काम की अपेक्षा अधिक मूल्य एवं महत्व मिलता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम मजदूरी देने के अवधारणा थी। प्रभावती देवी बताती हैं कि "हमारे गाँव में पुरुषों की मजदूरी जब 60 रुपए थी तब महिलाओं को सिर्फ 40 रुपए ही मिलता था।" सामान्यतः लोग इसको भी एक नियम ही मानते थे। हालांकि नारीसंघ के गठन के बाद मनरेगा में काम करके महिलाओं ने यह समझा कि वे भी पुरुषों के बराबर ही तकनीकी काम एवं मेहनत करती हैं, किन्तु उनके कामों को फिर भी कम महत्व दिया जाता है। अतः उन्होंने कृषि कार्यों की मजदूरी में असमानता को चुनौती देने का निर्णय किया।

प्रभावती देवी बताती हैं कि "नारीसंघ ने भूस्वामियों के विरुद्ध कम एवं असमान मजदूरी के मुद्दे पर आवाज उठाने का निर्णय लिया। हम लोगों ने कहा कि जब महिला-पुरुष दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं तो हम लोगों को भी समान मजदूरी मिलनी चाहिए। जब हम लोगों ने इस बात को गाँव में लोगों के सामने रखा, तब पुरुषों ने इसका विरोध किया। सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि जिन महिलाओं ने आगे बढ़ करके यह बात रखा, उन लोगों को अलग कर दिया गया और उन लोगों को कहीं भी काम नहीं मिला।" समाज से इस तरह की प्रतिक्रिया आने के बाद सभी महिलाओं ने संगठित हो कर सर्वसम्मति से इस मांग को दोहराया। महिलाओं के संगठन के समक्ष गाँव वालों ने नरमी दिखाते हुए आश्वासन दिया कि अगले साल मजदूरी में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए 2011 में हम लोगों की मजदूरी 60 रुपए से बढ़ करके 100 रुपए हो गयी।

पंचायत की निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण ग्रामपंचायत की बैठकों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाती हैं। वे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सेवादाताओं से बराबर ही मिलती रहती हैं। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के वितरण के अंतर्गत उन्होंने पहल करके 15 पात्र व्यक्तियों की वृद्धा पेशन दिलवाने में सफल रही। वे अपनी भूमिकाओं अर्थात् निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि एवं नारीसंघ की अध्यक्ष, दोनों ही पदों के साथ न्याय करते हुए सफलतापूर्वक वहन कर रही हैं।

15. नारी संघ और महासंघ की अध्यक्ष

सीमा सरोज महिलाओं की स्थिति और उन्हें जो महसूस होता है उसे बताते हुए कहती हैं कि, "महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं है, मैं सोचती हूँ कि मेरा जीवन घूँटे में बंधी गाय से अलग नहीं है, लेकिन मुझे आशा है किसी दिन इससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा।"

उनके अनुसार दलित व अन्य पीड़ित समुदाय की महिलाओं की स्थिति, अच्छे परिवार की महिलाओं की तुलना में ठीक नहीं है। यद्यपि, यदि परिवार स्तरीय स्थिति को अलग रख दिया जाय तो, महिलाओं पर एक या अन्य तरह के प्रतिबंध होते हैं और महिलाओं अपने स्वयं के जीवन से सम्बन्धित फैसले लेने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं।

उनके और बहुत सी ऐसी महिलाओं के जीवन के मामले में, नारी संघ एक निर्णायक बिंदु साबित हुआ। बाहर कदम निकाल कर अपनी क्षमता का पता लगाने के लिए, यह संगठन उन्हें एक अवसर प्रदान कर रहा था और वह भी इसे एक अवसर के रूप में देख रही थी।



“यहां तक कि मेरे पति भी मुझे साइकिल से बैठकों में छोड़ आते हैं और जब कि अब मैं और अधिक विश्वास के साथ परिवार में निर्णय कर रही हूँ।”

—सीमा सरोज
अध्यक्ष, चिंगारी नारीसंघ और महासंघ

27 वर्षीय सीमा देवी, प्रतापगढ़ जिले में, लालगंज ब्लाक में अजहरा ग्राम पंचायत की निवासी है और अनुसूचित जाति के समुदाय से है। वह विवाहित है व उनके तीन बच्चे हैं और कक्षा 10 तक पढ़ी लिखी है। वह मजदूरी का कार्य करती है और उनके पति सब्जी विक्रेता है। यह दम्पति जो किसी तरह से जो मिलता है उसी में प्रबंधन करता है।

जब से नारी संघ के गठन का शुरुआत हुआ था सीमा सरोज तभी से शामिल है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में अपने पति से नहीं बताया था। किन्तु एक दिन

उसे इसके बारे में पता चल गया और उनसे नाराज हो गया। अब तक, सीमा सरोज को नारी संघ की गतिविधियों के प्रति जुड़ाव हो गया था और उन्होंने इसके साथ जुड़े रहने का निश्चय किया। इन सबसे ऊपर वह आगे की तरफ देख रही थी और अन्य महिलाओं के साथ काम करने में सक्षम होने के लिए जाब कार्ड प्राप्त किया। धीरे-धीरे उनके पति की शिकायत भी कम होने लगी और उनके खिलाफ कुछ भी बोलना बंद कर दिया।

चिंगारी नारी संघ का गठन अप्रैल 2010 में हुआ था और वर्तमान में 150 महिलायें उसकी सदस्य हैं। सीमा सरोज को नारी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और बाद में नारी महा संघ की भी अध्यक्ष हुई। उनके नेतृत्व में बहुत पहले जाब कार्ड प्राप्त करने के लिए पहल किया गया था। लगभग 60 महिलाओं को बहुत कठिनाई के साथ अपना जाब कार्ड प्राप्त हुआ। यह उनके लिए विजय का क्षण था। लेकिन काम मिलना और भी कठिन था।

नारी संघ द्वारा लगातार मांग के बाद 15 महिलाओं को काम मिला लेकिन पुरुष मजदूरों द्वारा एक तरह से उनका बहिष्कार कर दिया गया। महिलाओं ने अपने दम पर उतने ही कुशलता से काम किया। अपनी क्षमता या कौशल से सम्बन्धित गलतफहमी को स्पष्ट करने के बाद उन्होंने नियमित रूप से काम करना शुरू कर दिया।

यहाँ मनरेगा कार्य स्थलों पर दूसरी समस्या भी थी। सीमा देवी का कहना है कि, मेठ बुरे विचारधारा का और हमें परेशान करता था। “नारी संघ की महिलाओं ने एक मेठ को प्राथमिकता दिया जो उनके साथ आरामदायक ढंग से काम करता है। इसलिए उन्होंने पुरुष मेठ का विरोध किया और नारी संघ की सदस्य सुनीता देवी का मेठ के रूप में चुनाव किया गया।

धीरे-धीरे ज्यादा महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया। अब लगभग 115 महिलायें नरेगा कार्यस्थल पर काम कर रही हैं। वे कहती हैं कि, “हम काम करना चाहते हैं अब और निष्क्रिय नहीं बैठेंगे।” यह काम महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है और सीमा सरोज भी इसकी अपवाद नहीं है। यह उन्हें अपने दम पर होने का अवसर देता है, इससे उनकी बचत में वृद्धि हुई है और अपने आमदनी पर नियंत्रण का मायने दिया है।

सीमा सरोज सक्रिय रूप से विकास दल में भी शामिल हुई, यह समूह गाँव में मनरेगा के अर्न्तगत होने वाले कार्यों के लिए संभावित मनरेगा कार्ययोजना के लिए प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह समूह इस तरह से कार्ययोजना बनाता है जिससे काम करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को 100 दिन का काम स्थानीय स्तर पर ही मिल जाय।

अध्यक्ष के रूप में सीमा सरोज ने सोच समझकर अपने काम के अधिकार के लिए सदस्यों को शामिल होने पर जोर दिया। विशेष रूप से मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए इनहोंने मीन समितियों का गठन किया, उनमें से एक काम की मांग ट्रैक करता है, दूसरा काम करवाता है और तीसरा कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाओं का देखता है। वह इन तीनों के साथ सहयोग से काम करती है और इनके बीच समन्वयन बनाये रखती है।

मनरेगा के बारे में जागरूकता फैलाने और इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने के लिए संगठन ने ठोस कदम उठाये हैं और सुविधाजनक सिस्टम विकसित किया है। उसमें से एक उपाय ब्लाक सतरीय समिति— मनरेगा समन्वयन समिति है जो ब्लाक स्तरीय अनुसरण के लिए जिम्मेदार होती है। सीमा देवी भी इस समिति की एक सदस्य हैं। समिति की बैठकों में उन्होंने फोरम का ध्यान महिलाओं द्वारा जाब कार्ड प्राप्त करने की मांग की तरफ आकर्षित करवाया। उन्होंने जाब कार्ड वितरित करवाने की प्रक्रिया को गति देने का सुझाव दिया क्योंकि कई गाँव की महिलायें जाब कार्ड प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसके परिणाम स्वरूप इस ब्लाक में अब नारी संघ से जुड़ी सभी महिलाओं के पास जाब कार्ड है।

कई बार परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से पति की मानसिकता बदलना बहुत मुश्किल होता है। सीमा सरोज इस स्तर पर सफलता पाने में सक्षम रही। वह खुशी के साथ बताती है कि, “अब परिवार के लोग मेरे काम की सराहना करते हैं। कभी-कभी मेरे पति अपनी साइकिल पर मुझे बैठक में छोड़ आते हैं और मैं अधिक विश्वास के साथ परिवार में निर्णय ले रही हूँ। जाहिर है, महिलाओं ने घर के बाहर और भीतर दोनों जगह अपने अधिकारों को सुरक्षित कर रही है।

16. सहायक एवं सक्रिय नेतृत्वकर्ता

“पहले मुझे किसी से मिलने एवं बात करना में संकोच लगता था।” यह कहना है गाजीपुर जिले के सदर ब्लाक के ग्रामपंचायत विशनुपुर पिपरी की रहने वाली उषा देवी का, लेकिन यह नारीसंघ के गठन के पहले की स्थिति थी। पहले संकोची एवं शर्मीली उषा देवी अब साहस एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण नेता में तब्दील हो गयी है और वर्तमान वे दुर्गा नारीसंघ की अध्यक्ष भी हैं। उनकी छवि में सकारात्मक परिवर्तन आने के परिणामस्वरूप ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

हालांकि नारीसंघ में उनका प्रवेश आकस्मिक ही था। पहली बार उन्होंने बैठक में पूरे उत्सुकता से प्रतिभाग किया, लेकिन वे अपने पति के गुस्से से बैठक में आने से डरती थी, अतः वे जब बाहर होते तभी वे बैठक में जाती थी। उन्होंने सभी बैठकों में तो प्रतिभाग नहीं किया था लेकिन कुछ में आ करके ही उन्हें संगठन एवं चर्चा अच्छी लगने लगी। “मुझे याद है कि जब मैं पहली बार बैठक में आयी, तो उस चर्चा से मुझे बहुत जानकारी प्राप्त हुई इसलिए मैं प्रत्येक बैठक में आने का प्रयास करने लगी।” उषा देवी आज नारीसंघ की प्रतिबद्ध एवं समर्पित सदस्य हैं। अंत में 106 सदस्यीय नारीसंघ की अध्यक्ष भी चुनी गयी। अध्यक्ष के रूप में वे लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करती हैं।

अन्य जगहों की अपेक्षा में इनके गाँव के लोग मनरेगा कानून से अनभिज्ञ नहीं थे। कुछ लोगों का तो पहले से जॉबकार्ड भी बना था और काम भी मिल रहा था, हालांकि उन लोगों की भी मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं हो पा रहा था। रोजगार गारण्टी कानून पर ग्रामप्रधान का ही नियंत्रण था और वह उन लोगों को कृषि मजदूरी के बराबर ही मनरेगा के काम का भी भुगतान करते थे। “लगभग 50 महिलाओं को मनरेगा के काम का भुगतान भी 50 रूपए प्रतिदिन के अनुसार ही हुआ था। नारीसंघ की बैठक में आने से हम लोगों को जानकारी हुई कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों का जितना पैसा मिलना चाहिए, अभी उसका आधा ही मिल रहा है, जबकि महिला-पुरुष दोनों को ही समान मजदूरी मिलने का प्रावधान भी है।” महिलाओं को तब एहसास हुआ कि गाँव के उच्च जाति के शक्तिशाली एवं अमीर प्रधान अभी तक मजदूरों को धोखा दे रहे थे। महिलाओं ने संस्था से संपर्क कर अपनी पूरी मजदूरी प्राप्त करने का तरीका भी पूछा।

“ग्रामपंचायत में मनरेगा के अंतर्गत जब भी कोई काम प्रारम्भ होना होता है, तब प्रधान नारीसंघ को सबसे पहले सूचित करते हैं। ग्रामसभा एवं अन्य आवश्यक बैठकों की सूचना भी देते हैं।”

— उषा देवी
अध्यक्ष, दुर्गा नारीसंघ

नहीं सुनते और हम लोगों की मजदूरी में से भी पैसा ले लेते हैं। हम लोगों ने उनको पूरी समस्या विस्तार से बतायी और उन्होंने शीघ्र पहल करते हुए खण्डविकास अधिकारी को इस मुद्दे पर शीघ्र कार्यवाही करने का आदेश दिया।” जिलाधिकारी के



कार्यालय से महिलाएँ सीधे ही खण्डविकास अधिकारी के कार्यालय पहुँची। उसी समय उन्होंने भी प्रधान को बुलाया और प्रधान को चेतावनी भी दी। “ हम लोगो को देखते ही प्रधान ने हम लोगो से माफी मांगी।” उसकी हताश मुद्रा में माँफी मांगना अभी भी इनको याद है। अगले ही दिन उसने सभी की मजदूरी का भुगतान भी कर दिया। उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे अपनी समस्या किसी अधिकारी को बताने के बजाय पहले उन्हें भी बता सकती हैं। उसके बाद उन्होंने हमेशा हम लोगो को पूरी मजदूरी का भुगतान किया।

शक्तिशाली प्रधान को चुनौती देने में महिलाओं ने बहुत साहस एवं हिम्मत से काम लिया। इस सफलता के साथ ही महिलाओं को संगठन की शक्ति एवं सूचना का महत्व दोनों ही बातें समझ में आ गयीं और परिणामस्वरूप महिलाओं का आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ। अंततः मनरेगा के अंतर्गत पारदर्शिता लाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन के लिए पैरवी की गयी। नारीसंघ के पहल एवं प्रयास के परिणामस्वरूप प्रधान ने पूरे कोरम के साथ ग्रामसभा का आयोजन निर्धारित समयांतराल पर करवाने लगे।

गाँव से संबंधित मुद्दों पर नारीसंघ की राय को भी महत्व मिलने लगा है, वो बताती हैं कि “ अब यदि कोई काम प्रारंभ होने वाला होता है, तो प्रधान हम लोगो को पहले ही सूचित कर देते हैं, ग्रामसभा और अन्य बैठकों की सूचना भी नारीसंघ को दी जाने लगी है और नारीसंघ के सदस्य इन बैठकों में पूरी संख्या में प्रतिभाग भी करते हैं। ग्रामसभा की बैठक में उठाए मुद्दों को हम लोग बैठक रजिस्टर की कार्यवाही से भी मिलान कर लेते हैं।”

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये परिवर्तन सतही न हो कर वास्तविक एवं निरंतर रूप से चलने वाले हैं। महिलाओं की ईमानदारी और निष्ठा में सभी विश्वास करने लगे हैं। इसी तरह की एक घटना उषा देवी बताती हैं, “ मनरेगा में मेहनत से काम करने के बाद शाम को हम लोगो ने रोजगार सेवक से अनुरोध किया कि वे हम लोगो के काम को जाँच लें, तो रोजगार सेवक ने विश्वास के साथ कहा कि आप लोगो ने किया है तो जाँचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रधान एवं रोजगार सेवक के विश्वास को देख करके भी हम लोगो को आत्मबल मिला।”

महिलाएँ अन्याय के खिलाफ हिम्मत, साहस एवं विश्वास से चुनौती देती हैं। पहले उषा देवी मनरेगा में मेट थीं किन्तु अचानक उनको हटा करके अन्य किसी को मेट बना दिया गया। महिलाओं ने इसका विरोध भी किया। इस मामले में नारी महासंघ अध्यक्ष नन्हकी देवी ने भी हस्तक्षेप करते हुए रोजगार सेवक से उषा देवी को मेट पद से हटाए जाने का कारण भी जानना चाहा। परिणामस्वरूप उषा देवी आज मेट के रूप में पुनः कार्य करने लगीं।

महिलाएँ अब अपना महत्व स्थापित करने में सक्षम हो गयीं हैं। नारीसंघ की पहल को लोग गम्भीरता से लेने भी लगे हैं। अब महिलाओं को सम्मान भी मिलने लगा है। पहले रोजगार सेवक, ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान महिलाओं के मुद्दों को अनदेखा एवं अनसुना करते थे, लेकिन आज वे नारीसंघ फोन पर हुयी बातों को सुनते एवं महत्व देने लगे हैं। अब हर काम के लिए पंचायत कार्यालय तक जाने की भी जरूरत नहीं रहती। “हम लोग उनको फोन कर सकते हैं और वे हमारी बातों को सुनते एवं महत्व भी देते हैं।” ये बताते हुए नारीसंघ की अध्यक्ष गर्व महसूस करती हैं।

17. निडर और मुखर राजमनी देवी

“इससे पहले हम अपनी क्षमता को कम करके आंकते थे। हम सोचते थे कि हम अपने दम पर कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं और चुपचाप भुगतना हमारी किस्मत में है। लेकिन नारी संघ ने हमारी स्वयं की धारणा को बदल चुका है, हमें हमारी महत्व और ताकत का एहसास हो गया है।” यह कहना है 35 वर्षीय राजमनी देवी का, जो वाराणसी जिले में, चोलापुर ब्लॉक में, लाखनपुर ग्राम पंचायत के नारीसंघ की अगुआ हैं। इस संगठन का गठन मई 2011 में किया गया वर्तमान में इसमें 150 सदस्य हैं, राजमनी देवी सभी की भावनाओं को बताती हैं।

एक अगुआ के रूप में राजमनी देवी ने मनरेगा कार्य स्थल पर काम की स्थिति सुधारने



“मुझे खुशी है कि मैं अपने जीवन में कुछ ठोस काम करने में सक्षम रही क्योंकि अब यहां मेरी जैसी कई महिलायें निडर व मुखर हो गयीं।”

—राजमनी देवी,

अध्यक्ष, लाखनपुर नारी संघ

के लिए काम किया, काम की मांग से लेकर कार्य स्थल पर मस्टर रोल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए, काम का ठीक से मापन के लिए, महिला और पुरुष मजदूरों के बीच काम के वितरण के लिए। इससे पहले कि वह अपने प्रयासों में सफल हो नारी संघ को कई चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ा।

जब महिलाओं ने पहली बार अपने अधिकार की मांग की तो प्रधान को बहुत गुस्सा आया। उसने चेतावनी दी कि, “यदि आप मेरे तरीके से काम करना चाहते हैं, तो काम करिये, अन्यथा कार्य स्थल छोड़ कर चले जाइये। महिलाओं ने बी०डी०ओ० से शिकायत किया तथा उन्होंने प्रधान व पंचायत सचिव को मनरेगा के बारे में समझाया। इस घटना के बाद महिलाओं ने बिना समस्या के काम करना शुरू कर दिया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति में सुधार के लिए इसी प्रकार का पहल किया गया। जब महिलाओं ने कोटेदार को सबक सिखाने के लिए पी०डी०एस० हेल्पलाइन का उपयोग किया तो वह डर गया और असानी से उन्हें उचित मात्रा देने लगा।

“हर चुनौती के बाद मुझे और अधिक विश्वास हो गया। मुझे खुशी है कि मैं अपने जीवन में कुछ ठोस कार्य करने में सक्षम रही क्योंकि वहां पर मेरे जैसी कई महिलायें मुखर और निडर हो गयी हैं। हममें से हर एक अपनी समस्याओं से निपटने के लिए आश्वस्त हो गयी हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जरूरत के समय हमेशा नारी संघ हमारे साथ है,” यह कहना है राजमनी देवी का, जिन्हें विश्वास है कि महिलाये अपने अधिकारों का दावा करती हैं और अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हमेशा एक दूसरे का समर्थन करती हैं।

18. नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते

36 वर्षीय राधिका देवी अम्बेडकरनगर जिले के जलालपुर ब्लाक के टिकरी ग्राम पंचायत की निवासी हैं। उनका विवाह 14 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, वे कृषि मजदूर के रूप में काम करती हैं। उनके 4 बच्चे हैं और पति का निधन हो चुका है।

उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और उनका जीवन कठिनाइयों में ही बीता था। उन्होंने कक्षा 8 तक शिक्षा प्राप्त की। एकल महिला होने के बावजूद भी नारीसंघ से जुड़ करके सम्मान के साथ जीवन जीना सीख लिया है।

सावित्री बाई फुले नारीसंघ का गठन अप्रैल 2011 में हुआ और संगठन के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति भी जानकार हुईं। इसी वाक्य से उनका मार्गदर्शन हुआ परिणामस्वरूप आत्मबल भी मिला, “नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते”।

“जब हम लोग प्रधान के खिलाफ आवेदन डाले, तब गाँव के लोगो ने हम लोगो को निर्लज्ज भी कहा, क्योंकि अभी तक उनके विरुद्ध जा करके किसी ने चुनौती नहीं दी थी।” राधिका देवी बताती हैं, जिन्होंने लोगो की टिप्पणियों का कुशलता के साथ जबाव दिया। जब आप अपनी बकाया राशि के लिए दावा करते हैं तो विरोध एवं टकराव अनिवार्य है।

उन्होंने पहले एकल महिलाओं के कल्याण से संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और फिर जिला मुख्यालय से सभी योजनाओं से संबंधित आवेदन पत्र ले करके नारीमहासंघ एवं नारीसंघ की बैठको में बताया, उनका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।



“हम लोग सभी जानकारियों को अपने परिवार में बताते हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिवार में भी परिवर्तन हो रहे हैं।”

— राधिका देवी
सावित्री बाई फुले नारीसंघ

एक बार की घटना है जब गाँव की ही कुछ महिलाएं उनसे मिलने आयी। उन्होंने बताया कि उन लोगों को पट्टे की जमीन मिली है, किन्तु अभी तक उस पर उनका कब्जा नहीं हो पा रहा है। प्रधान महिलाओं को सहयोग नहीं कर रहा था और जब समस्या बताने जाती तब उन लोगों की बातों ध्यान भी नहीं देता। अतः महिलाओं ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। जब पुलिस ने महिलाओं को थाने पर बुलाया, तब महिलाएं डरने लगीं,

राधिका देवी ने उनका सहयोग करने के लिए उनके साथ गयी। उन्होंने महिलाओं की हिम्मत बंधा करके थाने तक ले गयी और वे भी पहली बार ही थाने पर गयी थीं, किन्तु उनको अपने संगठन पर पूरा विश्वास था और इसी कारण वे पूरी घटना पर अच्छी तरह से पहल करने सक्षम हुईं।

अभी एक अन्य मुद्दे पर राधिका देवी ने लोक अदालत में प्रतिभाग करके काम के अधिकार के मुद्दे पर पहल किया। जिसके परिणामस्वरूप 60 लोगों को मनरेगा में 15 दिन का काम प्राप्त हुआ। सत्ताधारियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए साहस की जरूरत होती है और कई अवसरों पर वे अपने साहस का प्रदर्शन कर सफलता भी प्राप्त की है।

वे कहती हैं कि “जीवन कठिन है किन्तु हम लोगों को संगठन पर पूरा भरोसा है। नारीसंघ की अन्य सहयोगी सदस्यों मुन्नी, शोभा, सुनीता, उर्मिला, समरथी के साथ मिल करके हम लोग महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। विश्व मानवाधिकार के अवसर पर 12 किलोमीटर रैली में प्रतिभाग करके पुलिस को ज्ञापन दिया। इस तरह की पहल के कारण ही लोग जागरूक हो रहे हैं।”

राधिका देवी का कहना है कि मासिक बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त होने सूचना एवं जानकारी समझ विकसित करने के उद्देश्य से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।” मैं बैठकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को परिवार में भी चर्चा करती हूँ, परिणामस्वरूप उनमें भी परिवर्तन दिखाई देने लगा है।”

19. एक सच्ची नेतृत्वकर्ता संगीता देवी

45 वर्षीय संगीता देवी, अम्बेडकर नगर जिले में, जलालपुर ब्लाक में, गुवावा ग्राम पंचायत की रहने वाली हैं। उनकी शादी कम उम्र में ही हो गयी थी और ये चार बच्चों की माँ हैं। 13 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी हो गयी थी और 25 वर्ष की आयु में विधवा हो गयी। उन्होंने पुनर्विवाह के लिए इन्कार कर दिया और अपने चार बच्चों के साथ कड़ी मेहनत करने लगी। एक स्थानीय जमींदार के यहां वह कृषि मजदूर के रूप में काम करने लगी और अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था।

नारी संघ की गठन की प्रक्रिया ने आगे की तरफ देखने के लिए एक नया रास्ता दिया। यहाँ पर पहली बार उन्होंने नरेगा के बारे में सीखा और इस कार्यक्रम से लाभ पाने के लिए संगठन से जुड़ गयी। कुल 192 महिलायें सावित्री बाई फुले नारी संघ के साथ जुड़ी हैं, जिसका गठन मार्च 2010 में किया गया।

मनरेगा के तहत काम सुरक्षित करने के लिए संगीता देवी ने आत्मविश्वास के साथ काम किया और प्रधान, पंचायत सचिव व अन्य संबन्धित अधिकारियों का सामना किया। काम के अधिकार पर प्रशिक्षण लेने के बाद वह अपने अधिकारों को पाने के लिए प्रेरित होने लगी। उन्होंने 98 महिलाओं की तरफ से काम की मांग का लिखित आवेदन दिया। महिलाओं ने अपने गाँव से 15 किलोमीटर दूर ब्लाक कार्यालय तक अपने खर्चे पर यात्रा किया। यहाँ पर ए0पी0ओ0 उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा था तो उन्होंने हेल्पलाइन का प्रयोग किया। महिलायें अपनी ताकत और एकजुटता दिखाने के लिए नारे लगाने लगीं। बी0डी0ओ0 स्वयं महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए आया और ए0पी0ओ0 को काम नकरने के लिए डाँट लगायी। इस नारी संघ ना केवल काम की मांग की बल्कि अपने गाँव में भूमि विकास कार्य के लिए जमीन भी सुझाया जिन पर दलित परिवारों का स्वामित्व था।



“जानकारी बढ़ने और बाहर आने जाने से मेरे अन्दर बदलाव आ गया। मुझे एहसास हुआ है कि अगर हम साथ रहेंगे तो ही हमारा विकास होगा।”

— संगीता देवी

सावित्रीबाई फूले नारीसंघ, गुवावा

लेकिन जिस काम को 15 दिन की मंजूरी मिली थी, उसे बीच में चार दिन के बाद ही बंद कर दिया गया। संगीता देवी ब्लाक कार्यालय पर गयी और बी0डी0ओ0 से पुनः काम शुरू कराने की मंजूरी लिया।

महिला मजदूरों को दिन भर के काम का केवल 50 रुपये ही मिलता था। लेकिन नारी संघ ने मजदूरी बढ़ाने की मांग की और नरेगा के

बराबर मजदूरी लेने का फैसला किया। स्थानीय जमींदारों ने नरेगा के काम को बंद करवाने की कोशिश किया, प्रधान के ऊपर दबाव बनाया जिससे उसने नरेगा का काम बंद कर दिया। लेकिन नारी संघ के सदस्यों ने प्रधान के इस निर्णय के लिए उनसे पूछताछ किया और उनसे कहा कि काम देकर वह कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वह केवल एक सरकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करवा रहे हैं और वह नरेगा कानून के प्रावधानों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। महिलाओं ने बी0डी0ओ0 से सम्पर्क किया। संगीता देवी ने इस पर पहल के लिए नेतृत्व किया और स्थानीय जमींदार उनके इस उचित मांग के लिए सहमत हो गये। ग्राम सभा के माध्यम से नारी संघ, 27 जरूरतमंद परिवारों को महामाया योजना के अर्न्तगत लाभ दिलवाने में सफल हो गया।

वह कहती है कि, “मुझमें बहुत कुछ बदल गया और कुछ भी करने में संकोच नहीं लगता है। जानकारी बढ़ने और बाहर आने जाने से मेरे अन्दर बदलाव आ गया। मुझे एहसास हुआ है कि अगर हम साथ रहेंगे तो ही हमारा विकास होगा।”

20. निडर और मुखर चन्दा देवी

“हम लोग प्रधान एवं सचिव को ही बड़े अधिकारी मानते थे, इसलिए हम लोग की उनसे बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी।” वाराणसी जिले के चोलापुर ब्लाक के भदवा ग्रामपंचायत के नारीसंघ की अध्यक्ष चन्दा देवी बताती हैं। प्रधान के समक्ष उनका अधिकारो को प्राप्त करने के दावा करने के ढंग से लोग आश्चर्यचकित रह गए।

21 वर्षीय चन्दा देवी के 2 बच्चे हैं। एक गरीब मजदूर एवं जरूरतमंद होने के बावजूद भी पंचायत के समक्ष अपनी बातों को रखने में सक्षम नहीं थी। किन्तु 2011 में नारीसंघ के गठन से ही उन्हें साहस मिला। अभी नारीसंघ से कुल 75 सदस्य ही जुड़े हैं।

चन्दा देवी ने गठन की प्रक्रिया के प्रारंभ से नेतृत्व प्रदान किया है। वो बताती हैं कि “मुझे लगा कि संगठन से जुड़ करके ही मैं अपनी समस्याओं पर पहल करके समाधान कर सकूंगी।” उनका नारीसंघ में सक्रिय भागीदारी के परिणामस्वरूप ही सदस्यों ने उन्हें संगठन का अध्यक्ष चुना। अगुआ के रूप में चुनाव से उनके आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ। अध्यक्ष के रूप में वे संगठन का सक्रिय नेतृत्व एवं मुखर हो करके महिलाओं के हक एवं अधिकारों को भी दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करती हैं। जाहिर है कि प्रधान को चन्दा देवी के परिवर्तित व्यक्तित्व अर्थात् विनम्र एवं साहसी अगुआ महिला के रूप में देखना नागवार गुजरा, परिणामस्वरूप मनरेगा में उनके द्वारा किए गए काम की मजदूरी का भुगतान ही प्रधान ने प्रयास करके रोक दिया।

चन्दा देवी घटना का कुछ इस तरह से बयान करती हैं “अन्य सभी महिलाओं की मजदूरी का भुगतान हो गया, किन्तु मेरा पैसा बैंक में ही नहीं जमा हुआ। जब मैं प्रधान से पूछने गयी, तब उन्होंने बैंक में जा करके पता करने को कहा। बैंक में दो-तीन चक्कर लगाने के बाद मैं पुन प्रधान के पास गयी और वही पर उन्होंने अपनी मंशा व्यक्त की, कि उन्होंने उनकी मजदूरी ही बैंक को नहीं भेजी। “अभी तक तुम बहुत बड़ी नेता बन रही थी और अब दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं।” अहंकारी प्रधान ने उनसे कहा कि आप को न तो किए गए काम का भुगतान मिलेगा और न ही भविष्य में मनरेगा में काम, जाओ जो कर सकती हो कर लेना।



प्रधान ने सिर्फ़ उनका पैसा ही नहीं रोका, बल्कि संगठन की कुछ महिलाओं को अधिक सुविधाएँ दे करके नारीसंघ को तोड़ने का भी प्रयास करने लगा। चन्दा देवी उनकी इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए अभी तैयार नहीं थी। प्रधान के व्यवहार से निराश हो करके उन्होंने संस्था से सहयोग मांगा। संस्था से उन्हें एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी पता चला और उन्हें लगा कि प्रशिक्षण में प्रतिभाग करके उनकी समस्याओं का भी कोई हल निकल पाएगा। वास्तव में, प्रशिक्षण में भाग लेना ही उनके लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इसी दौरान उन्हें बहुत सी महिलाएँ भी मिलीं जो कि चुनौतियों के बावजूद संघर्ष करके अपने लक्ष्य की तरफ़ दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही हैं। उनको मनरेगा की हेल्पलाइन अथवा ब्लॉक स्तर पर आयोजित मनरेगा लोकअदालत में शिकायत दर्ज कराने का सुझाव मिला। अतः उन्होंने दोनों ही स्थानों पर शिकायत दर्ज करायी। विभिन्न ग्रामपंचायतों की 135 महिलाओं ने मनरेगा से संबंधित समस्या के समाधान के लिए 13 जुलाई, 2011 को ब्लॉक मुख्यालय पर एक जुलूस निकाला, जिसमें की चन्दा देवी ने भी सक्रिय सहभागिता की। खण्डविकास अधिकारी ने महिलाओं के साथ बैठक करने में आनाकानी की, और जब अन्य कर्मचारियों ने आवेदन रिसीव करने के लिए बोले, तब महिलाओं ने दृढ़ता से कहा कि हमें बीडीओ से ही मिलना है। चिलचिलाती धूप एवं गर्मी में भी महिलाएँ जोश के साथ नोरबाजी करके अधिकारी से मिलने की मांग करती रहीं। हालांकि बीडीओ ने पुलिस को भी बुला लिया, किन्तु इससे कोई भी समाधान नहीं हुआ। अंततः उनको महिलाओं से मिल करके आवेदन भी रिसीव किए और उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर ही कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि “यदि दो से तीन दिन के अंदर कोई कार्यवाही नहीं होती, तो हम लोग इस मुद्दे को जिलाधिकारी के समक्ष ले जाएंगे।” उन्होंने अपने अपने वायदे को पूरा करते हुए महिलाओं की मांगों को पूरा किया एवं चन्दा देवी की भी मजदूरी उनके खाते में आ गयी।

“महिलाओं ने मुझे अध्यक्ष चुन करके मुझमें बहुत ही विश्वास दिखाया है, अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करा सकूँ।”

—चन्दा देवी
अध्यक्ष नारीसंघ

जैसे ही यह मुद्दा समाप्त हुआ, चन्दा देवी को एक अन्य चुनौती का भी सामना करना पड़ा। मजदूरी मिलने के एक दिन बाद ही प्रधान ने उनके घर में पथराव कराके धमकी भी दी। नारीसंघ की बैठक में चर्चा करके चन्दा देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराया और नारीसंघ की सभी सदस्यों ने उनका पूरा सहयोग भी किया। पुलिस ने प्रधान को चेतावनी दी, तब उनको महसूस हुआ कि इस तरह के रणनीतिक दबावों से भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

चन्दा देवी इस समयावधि में नारीसंघ एवं संस्था से प्राप्त सहयोग की सराहना करती हैं। “अकेले मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। पति भी मेरे विरोध में थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि सत्ताधारी प्रधान को मैं व्यर्थ में चुनौती दे रही हूँ, यदि नारीसंघ एवं संस्था के कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं होते तो मुझे गाँव से पलायन ही करना पड़ जाता।” प्रधान की दमनात्मक रणनीति के समक्ष भी नारीसंघ के सदस्यों ने साहस एवं हिम्मत से मेरा सहयोग किया। उनके प्रयास की लोगो ने सिर्फ़ प्रशंसा ही नहीं की बल्कि वे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाने लगी।

“महिलाओं ने मुझे अध्यक्ष चुन करके मुझमें बहुत ही विश्वास दिखाया है, अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सदस्यों के अधिकारों तक पहुँच एवं प्राप्ति सुनिश्चित करा सकूँ।” यह कहना है चन्दा देवी का, जोकि एक गरीब मजदूर से एक आत्मनिर्भर अगुआ के रूप में तब्दील हो गयी है।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में नागर समाज संगठनों की भूमिका और आगे की दिशा

● नागर समाज संगठनों की भूमिका

सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में, सहयोगात्मक प्रयास का विशेष महत्व है क्योंकि दायरा व्यापक है और इसीलिए काम का प्रभाव है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम एक सहयोगी कार्यक्रम होने के कारण इसमें संस्था की बहुत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य भूमिका है।

ई आर डब्लू कार्यक्रम में, विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव और विशेषता रखने वाली कुल 37 पार्टनर संस्थायें हैं, जो 9 जिलों के, 666 ग्राम पंचायतों में समान लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ काम कर रही हैं। महिला अगुआ, नारीसंघ एवं नारी महासंघ की कहानियाँ ई आर डब्लू कार्यक्रम द्वारा जमीन स्तर पर शुरू हुए परिवर्तनों को दिखाता है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया की शुरुआत है और संस्था द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है।

इन संगठनों का पहला काम सहजकर्ता के रूप में, महिलाओं को एकजुट करने, महिलाओं को समझ व अधिकारों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना और अपने अधिकारों के लिए पैरवी करने हेतु नेतृत्वकर्ताओं को सक्षम करना है। इनकी भूमिका बहुआयामी है और इस काम के हर स्तर पर इनकी विशिष्ट जिम्मेदारी है। नारीसंघ की शुरुआती प्रक्रिया में, संस्था महिलाओं तक पहुँच बनाने और महिलाओं को एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करती है। नारीसंघ के सक्रिय होने के बाद उनकी भूमिका प्रेरक एवं प्रशिक्षक के रूप में बदल जाती है। संस्थायें ठोस जानकारी देती हैं, नेतृत्वकर्ताओं के क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और रणनीति बनाने में सहयोग करती हैं। संस्था का सहयोग, महिलाओं के संगठित पहल के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए सक्षम बनाता है। यह ब्लाक और जिले स्तर पर पहल एवं पैरवी के उद्देश्य के लिए भी सहयोग करते हैं। अंततः संस्थाएँ कठिन प्रयास करके पंचायत स्तरीय नारी संघ की महिलाओं के संगठन को सक्षम एवं सशक्त करने के लिए ब्लाक स्तरीय नारी महा संघ का गठन किया और विभिन्न ब्लाकों की महिलाओं को जिले स्तर पर एक सामूहिक एवं संगठित रूप में साथ लाने के लिए अवसर उत्पन्न किया।

संगठनात्मक प्रयास के साथ काम करते हुए संस्थायें भी सीख प्राप्त करके आगे बढ़ रही हैं। पहली एवं सबसे महत्वपूर्ण बात, मुद्दा आधारित बिन्दु पर उनकी समझ एवं क्षमता का विकास हो रहा है। उनकी जानकारी का स्तर भी बढ़ रहा है। साथी संगठनों के साथ अनुभवों का निरंतर आदान प्रदान होने से सीखने के अनेक अवसर मिल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप संस्थाओं में मानव संसाधनों का भी विकास हो रहा है।

सी0एस0ओ0 के विकास के साथ ही नयी संस्थाओं के अनुभवों में वृद्धि हो रही है। इस काम के द्वारा कुछ संस्थाओं को सहायता भी प्राप्त होती है, मुख्य रूप से नयी संस्थाओं को अपने काम के आधार पर क्षेत्र में पहचान भी स्थापित करने में सहायता प्राप्त हो रही है। उन्हे स्वैच्छिक संगठनों के रूप में मान्यता प्राप्त करने एवं महत्व बढ़ाने में भी सहायक हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे संस्थाओं के आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है। अनुभवी संस्थाएँ अपने अनुभवों को एकीकृत करके ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने में भी सक्षम हुई हैं। उदाहरण के लिए, कुछ संस्थाओं ने लोक अदालत, सूचना का अधिकार, पंचायती राज और वन अधिकार से काम का अधिकार और भोजन के अधिकार को आगे बढ़ाया है।

पानी संस्थान के स्तर पर प्रोग्राम सपोर्ट टीम-पी.एस.टी. का गठन कर साथी संस्थाओं को मुद्दा आधारित एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय किया गया, इसमें अधिकारों का दस्तावेज, सरकारी कार्यक्रमों और प्रस्तावों एवं कानूनी और तकनीकी जानकारी भी शामिल है। पीएसटी प्रभावी रूप से अपनी भूमिका को आगे बढ़ाते हुये हैण्ड होल्डिंग के माध्यम क्षमता वृद्धि, बैठकों का अनुश्रवण और सहयोगात्मक देखरेख कर रही है। पीएसटी मुद्दा आधारित क्षमता वृद्धिकार्यक्रमों और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण को भी आयोजित करता है, जो पार्टनर संस्थाओं का ज्ञान बढ़ाने में मदद करता है। पीएसटी, पहल के लिए सामूहिक कार्ययोजना तैयार करने में भी सहयोग करता है और काम को उचित ढंग से दस्तावेजीकरण के लिए आसान प्रारूप के उपयोग का सुझाव देता है एवं उपलब्ध भी कराता है।

● आगे की दिशा

हालांकि कार्यक्रम के परिणाम उत्साहजनक हैं और पार्टनर संस्थाएँ जीवंत संगठनों के गठन के लिए सहजीकरण करने, अधिकार आधारित पद्धति में आने वाली चुनौतियों को कम करने में सक्षम हैं। इस तरह के कार्य में कई तरह की चुनौतियाँ व मांग आती रहती हैं और संस्था को उसे पूरा करने के लिए जानकारी से युक्त किया जाना चाहिए। संस्था को दृढ़ता के साथ इस दृष्टिकोण में विश्वास होना चाहिए और आवश्यक जानकारी, दृष्टिकोण और पैरवी के साथ तैयार रहना चाहिए। इन्हें कानून, अधिकार, अधिकारों के स्रोतों और शासन के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए।

अधिकार आधारित किसी भी काम में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ई आर डब्लू पार्टनर संस्थाएँ भी इसका सामना कर रही हैं। महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और मुख्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वे प्रशासन और स्थानीय नेताओं के आलोचना का लक्ष्य बन गये हैं। कुछ लोगों को तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से धमकियों का सामना करना पड़ा है लेकिन वे लोग इसे अपने काम के एक हिस्से के रूप में देखते हैं। इस काम में, अधिकार आधारित दिशा की ओर प्रशासन की नकारात्मक मानसिकता प्रमुख बाधा है। अक्सर बहुत से लोगों के हितों को इस प्रक्रिया ने चुनौती दी है, इन्होंने प्रतिक्रिया किया और काम करने की इस प्रक्रिया को दबाने की कोशिश किया। समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं को धमकी देने और अपने साथ शामिल करने का भी प्रयास किया गया।

चुनौतियों के बावजूद भी पार्टनर संस्थाएँ अपने कार्यों का विस्तार करने के लिए उत्साहित हैं, एवं निम्न मुख्य मुद्दों पर भविष्य में वे काम करना चाहती हैं।

- अब तक विशिष्ट परिवर्तनों का हासिल किया गया है, अब और अधिक प्रभाव के लिये समेकित परिवर्तनों और नारी संघ के सदस्यों की सामूहिक प्रेरणा के प्रयासों को बनाये रखने की जरूरत है।
- महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठित करने का प्रयास किया जायेगा।
- ग्राम सभा में नारी संघ को अपने एजेण्डे के साथ, मुखर और सक्रिय भागीदारी करने के लिए सहज करने का प्रयास किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिले स्तर पर पैरवी के लिए प्रयास किया जायेगा।
- नारी संघ का स्थायी पहचान बनाने की जरूरत है और इस दिशा में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के हस्तक्षेपों को शामिल करके और आगे क्षमता वृद्धि करके सक्षम किया जायेगा।
- पंचायत स्तर पर सूचना एवं संदर्भ केन्द्र तैयार करना।
- समाजिक नागर संगठन की कल्पना है कि नारी संघ को आत्मनिर्भर, महिलाओं के संगठन का सदस्यों द्वारा संचालन और संस्थाओं पर निर्भरता कम से कम हो। इसी उद्देश्य के साथ महिला अगुआ का क्षमता वर्धन जारी रखा जायेगा। नारी संघ को सभी सरकारी विभागों तक पहुँचने के लिये बेहतर जानकारी से युक्त करने की आवश्यकता है। नारीसंघ को आगे ढांचागत विषमताओं के लिए जागरूक और चुनौतियों के लिए जानकारी से युक्त हो जाना चाहिए।
- अंत में, इस कार्यक्रम की कल्पना महिला अगुवाओं का समूह विकसित करना है जो परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण के लिए पैरवी करेगा।

Empowering Rural Women-ERW Program Partners List

S. No.	ERW partner organizations	Chief Functionary	Telephone	E-mail Id	District	Block
1.	Grameen Vikas Sansthan - GVS	Mr. Shameem Abbasi	9415281073	gvsabbasi123@rediffmail.com; gvs.cso@gmail.com	Ghazipur	Sadar
2.	Jan Gramin Vikas Sansthan - JGVS	Ms. Vimala Maurya	9450571541	jgvsup@gmail.com		Jakhaniya
3.	Jan Sewa Prashikshan Sansthan -JSPS	Mr. Ram Bachan Bharati	9005674120	jpsngo@gmail.com		Devkali
4.	Gyandeep Mahila Kalyan Samiti- GMKS	Ms. Lalsa Bhardwaj	9415889777	lalsa.ghazipur@rediffmail.com		Manihari
5.	Manav Sewa Samiti- MSS	Ms. Sunita Singh	9450724472	mss_karanda@sify.com		Karanda
6.	Jan Sewa Samiti- JSS	Mr. Jamshed Alam	9918797970	jssgzp@gmail.com		Jamaniya
7.	Gram Vikas Sewa Sansthan - GVSS	Mrs. Kiran Baheti	9415381180	kiran.baheti@rediffmail.com; gvss007@gmail.com	Pratapgarh	Magraura
8.	Lokpriya Janhit Sewa Sansthan - LJSS	Mr. Niranj an Prakash Tiwari	9451275040	lokpriyapbh@gmail.com		Lalgaanj
9.	Netaji Subhash Chandra Bose Jan Shiksha Prasar Samiti-NSCBJSPS	Mr. Sadashiv Tripathi	9415745219	netajaurain@rediffmail.com		Aaspur Devsara
10.	Tarun Chetna-TC	Mr. Nasim Ansari	9415230412	tarunchetna@rediffmail.com		Patti
11.	Grameen Punarnirman Sansthan - GPS	Mr. Rajdev Chaturvedi	9451113651	gps.azm@gmail.com	Azamgarh	Atrauliya
12.	Jan Kalian Evam Gramin Utthan Sansthan - JKGUS	Mr. Umashanker	9450821519	jkgus.um@gmail.com		Tahbarpur
13.	Akhil Bhartiya Jyoti Mahila Sewa Sansthan - ABJMSS	Ms. Anita Yadav	9415656016	mahilajouti@gmail.com		Phoolpur
14.	Sri Ramdhani Jan Sewa Sansthan -SRJSS	Dr. Pannalal	9451652085	pannalaj94@gmail.com	Ajmatgarh	

15.	Bhagwan Manav Kalyan Samiti - BMKS	Mr. Ramesh Singh	9452050368	bmkmau@gmail.com			Ghosi
16.	Mahila Gramodyog Sewa Samiti - MGSS	Mrs. Radhika Mishra	9415836938	mgss_radhika@yahoo.co.in			Mohamadab ad Gohna
17.	Nehru Yuva Samajik Samarsata Sewa Samiti - NVSSSS	Mr. Sher Narayan	9451132416	nysssup@rediffmail.com		Mau	Ratanpura
18.	Gramin Vikas Prayas Samiti -GVPS	Ms. Savita Suman	9452284443	gvpsmau@gmail.com			Kopaganj
19.	Jan Sahyog Sansthan - JSS	Mr. Mahendra	9450520280	mpratap67@rediffmail.com			Badrao
20.	Mahila Swarojgar Samiti- MSS	Ms. Rekha Singh Chauhan	9415256472	mss_vo@rediffmail.com			Araji Line
21.	Voluntary Association for Rural Upliftment & Networking- VARUN	Mr. Anjani Kumar	9415812309	varun_kashi@yahoo.co.in		Varanasi	Cholapur
22.	Brij Jan Jagran Samiti-BJJS	Mr. Chandra Bhushan	9415240640	csingh17@yahoo.com			Kashi Vidhyapeeth Harhua
23.	Sri Sachchidanand Shikshan Sansthan - SSSS	Mr. R. A. Singh	9415914620	sssvns@gmail.com			Sadar
24.	Sadbhawana Grameen Vikas Sansthan - SGVS	Mr. D. S. Singh	9450575727	sgvs_bst@rediffmail.com		Basti	Gaur
25.	Bal Vikas Evam Mahila Utthan Sansthan - BVMUS	Mr. Akhilesh Kumar Pandey	9451861831, 9454854728	bvmus_basti@yahoo.com			Parasrampur
26.	Sampurn Sahyog Sansthan- SSS	Mohamad Jamal	9838744805	sss_lko777@rediffmail.com			Katehari
27.	Lok Jagriti Sansthan- LJS	Mrs. Rajesh Tripathi	9451232090	lokjs@rediffmail.com			Jalalpur
28.	Jan Shikshan Kendra - JSK	Mr. R. B. Pal	9415183210	jskkutiya@rediffmail.com		Ambedkar nagar	Katehari
29.	Gyanodaya Gramodyog Sewa Samiti - GGSS	Mr. Gynadatt Singh	9415969644	ggss_fzd@rediffmail.com			Bhiti
30.	Gramin Mahila Shashaktikaran Karyakram Nagahara, Bhiti, Ambedkarnagar.	Mr. Bharat Bhushan	9792445836	erw.bhiti@gmail.com			

31.	Sristhi Sewa Sansthan - SSS	Mr. Sunil Kumar Pandey	9839591950	srishti_seva@yahoo.co.in	Maharajganj	Sadar
32.	Jagriti Sewa Sansthan - JSS	Mr. Sanjay Lal Srivastava	9919195922	jagriti_mah@rediffmail.com		Mithaura
33.	Samadhan Manav Seva Sansthan - SMSS	Mr. Vijai Kumar	9793151329	samadhan_1968@rediffmail.com	Maharajganj	Partawal
34.	Sarvodaya Seva Sansthan - SSS	Mr. Aanad Mohan Lal Srivastava	9838523933	sarvodayseva@rediffmail.com		Pharenda
35.	Nehru Yuva Gram Vikas Kalyan Seva Sansthan - NYGVKSS	Mr. Sadhu Sharan Sharma	9919359486	nssmaharajganj@gmail.com	Jaunpur	Nichloul
36.	Rashtriya Jan Vikas Sansthan - RJVS	Mr. Rajamani	9450085584	jvsleduka@rediffmail.com		Buxa
37.	Manav Kalyan Sewa Samiti - MKSS	Mr. Sushil Kumar Tiwari	9415267420	mkssbahur@gmail.com		Khutahan

दस्तावेज में सामान्य रूप से उपयोग किये गये संक्षिप्त एवं स्थानीय शब्द

डी0एम0	– जिलाधिकारी
ए0डी0एम0	– सहायक जिलाधिकारी
बी0डी0ओ0	– खण्ड विकास अधिकारी
डी0एस0ओ0	– जिलापूर्ति अधिकारी
पी0ओ0	– कार्यक्रम अधिकारी
मनरेगा	– महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून
पी0डी0एस0	– सार्वजनिक वितरण प्रणाली
आर0टी0आई0	– सूचना का अधिकार कानून
सी0एल0डब्ल्यू	– समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता
सी0एस0ओ0	– नागर समाज संगठन
महिला मण्डल	– पुरवा स्तरीय महिला संगठन
नारीसंघ	– ग्रामपंचायत स्तरीय महिलाओ का संगठन
प्रधान	– ग्रामपंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि जो ग्रामपंचायत का मुखिया होता है
कोटेदार	– सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गाँव में वितरण करने के लिए नियुक्त व्यक्ति
खुली बैठक	– ग्रामसभा की बैठक जिसमें की कोरम की उपस्थिति में गाव से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाती है एवं पंचायत स्तरीय निर्णय भी लिए जाते हैं
रोजगार सेवक	– ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून के अंतर्गत कानून एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्रामपंचायत स्तरीय सेवादाता
ग्रामसचिव	– ग्रामपंचायत स्तरीय योजनाओं को बनाना एवं ग्रामपंचायत के दस्तावेजीकरण करने वाला सरकारी कर्मचारी
मेठ	– मनरेगा कार्यस्थल पर काम की देखरेख करने के लिए ग्रामीणों के मध्य से ही चयनित व्यक्ति
विकासदल	– मनरेगा के अंतर्गत संभावित कार्ययोजना के निर्माण हेतु कार्यों के चिन्हीकरण करके ग्रामसभा में प्रस्तुत करने वाला स्वैच्छिक दल ।

Published by :

People's Action for National Integration-PANI under the Empowering Rural Women (ERW) program

Address :

PANI

Programme Support Team-PST

For Empowering Rural Women-ERW Programme in Uttar Pradesh

1/13/190 Civil Lines, Dist-Faizabad-224 001, UP

Phone & Fax No. 05278-225175, E-mail: panipst@gmail.com

Support :

SIR DORABJI TATA TRUST, MUMBAI